R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 18
16 से 30 जून 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

घातक हो रही धार्मिक कट्टरता

आज देश को नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता ने घेरा हुआ है

सियासत, मौका परस्ती और कट्टरता का नया टूल बना धर्म

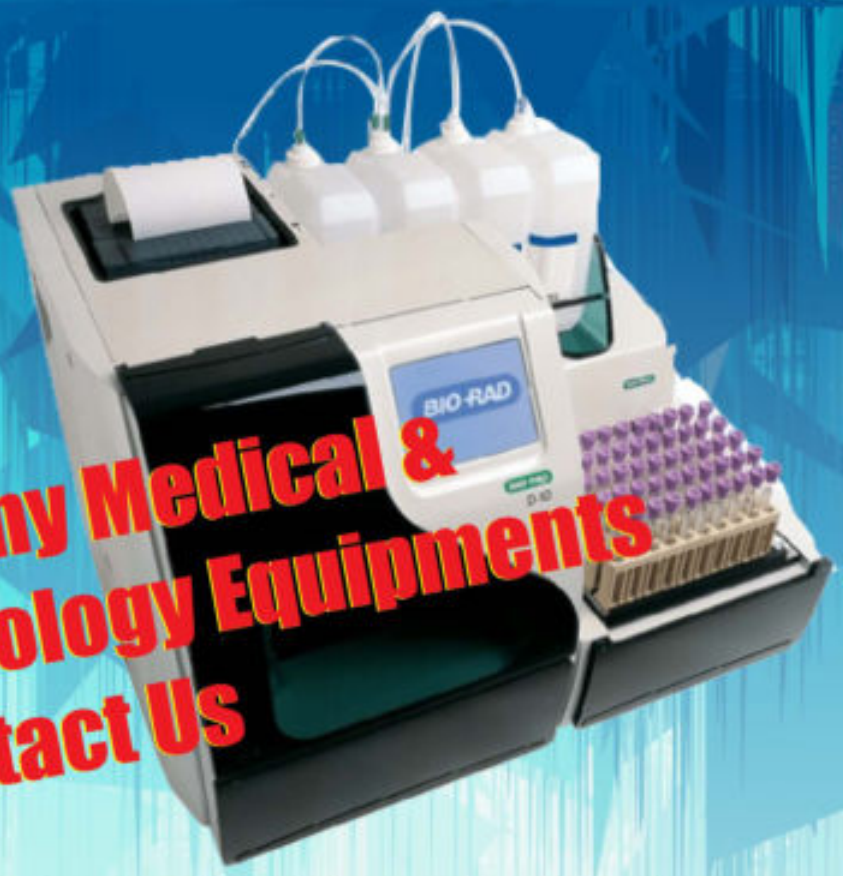

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

तैयारी

9 | इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कवायद तेज

इंदौर-भोपाल के बीच में प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रीयल हब में बनने वाले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए कवायद तेज हो गई है। हाल ही में गौतम अडाणी के साथ ही कई अन्य औद्योगिक घरानों ने संभावित क्षेत्र का दौरा कर...

राजपथ

10-11 | पंचायत चुनाव बनेंगे मिसाल

मप्र में देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से पंचायत चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। गैर राजनीतिक होने के बाद भी पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की साख दांव पर है। क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने...

घपला

13 | फेरों के नाम पर हेराफेरी

सरकारी योजनाओं को पतीला लगाने में नेता, पदाधिकारी व सरकारी कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। अवैध वसूली के चक्कर में सरकारी योजना को बट्टा लगाने का काम खरगोन जिले में हुआ है। दरअसल यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना...

आर्थिकी

18 | तैयार होंगे नए औद्योगिक क्लस्टर

मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में 7 और 8 जनवरी 2023 को इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट को सक्सेस करने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

गंगा-जमुनी तहजीब वाले भारत में धार्मिक कट्टरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस कारण देश में आए दिन धरना-प्रदर्शन, आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में ज्ञानवापी मामले में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से शुरू हुई बहस जो पैगंबर मोहम्मद साहेब तक पहुंच गई, उसे देखकर लग रहा कि धार्मिक कट्टरता विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए घातक होती जा रही है।

राजनीति

30-31 | महागठबंधन का मुद्दा...

नेशनल हेराल्ड मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार से पूछताछ करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। इसी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया...

महाराष्ट्र

35 | राज्यपाल भरोसे उद्धव

सरयू नदी के तट पर एक आरती, पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिकों के आने के लिए ट्रेनों और बसों की बुकिंग और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन - ये नजारा था शिवसेना के वंशज आदित्य ठाकरे की अयोध्या की पहली एकल यात्रा का। 32 साल के आदित्य ने अपने पिता...

बिहार

38 | जातीय जनगणना की चाल चली

बिहार की सियासी बिसात पर शह और मात का नया खेल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर जो गोलबंदी शुरू की थी, इफ्तार की दावतों ने उसमें तूफानी तेजी ला दी और तभी तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के नाम पर ललकारने लगे।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

...तो सूख जाएंगे पंप

किसी शायर ने क्या खूब कहा है...

आ रही जलती हुई तीली, बिखरा पेट्रोल था..
क्या आग लगने के लिए इतना काफी नहीं है?

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बाद अब मप्र सहित देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने आमजन को पसोपेश में डाल दिया है। लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या भारत भी श्रीलंका की तरह उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जहां पेट्रोल-डीजल की कमी हो गई है? यह सवाल इसलिए पूछा जाने लगा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से मप्र, पूर्वी उप्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों से यह खबर आई कि इन इलाकों में फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इन इलाकों के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल कंपनियों को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है, पेट्रोल बेचने में घाटा हो रहा है, इसलिए सप्लाई कम करके घाटे को कम किया जा रहा है। मप्र में पेट्रोल-डीजल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। प्रदेश के 1 हजार पंप सूखने जैसी स्थिति में हैं। आगरा-मुंबई रोड और दूसरे हाईवे पर मौजूद आधे से ज्यादा पंपों पर डीजल खत्म हो गया है। जिन पंपों पर ईंधन है भी, तो वहां तीन-चार दिन का ही स्टॉक बचा है। प्रदेश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की सप्लाई करीब 40 प्रतिशत तक घटा दी। इससे पंप ड्राई हो रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश में हर रोज 2.77 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की खपत होती है, लेकिन कंपनियां करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन कम दे रही हैं। सरकारी क्षेत्र की तीन पेट्रोल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के लगभग 70,000 पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी अपेक्षाकृत कम है, जबकि निजी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर स्थिति ज्यादा खराब है। रिलायंस एनर्जी से जुड़े पेट्रोल पंप ने तेल सप्लाई लगभग ठप कर दी है, तो एसआर ग्रुप और नायरा एनर्जी कुल मांग का लगभग 25 फीसदी पेट्रोल-डीजल की सप्लाई ही कर रहे हैं। तेल विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल की कमी के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों को लगभग 15 दिन पहले से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें किसी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न पेट्रोल पंप डीलरों के एसोसिएशन पत्र लिखकर इसके बारे में अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। भारत के पास तेल उत्पादक देशों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर उपलब्ध है, तो साथ ही कच्चे तेल की उपलब्धता में भी कहीं कोई कमी नहीं है। तेल कंपनियों को तेल बेचने पर घाटे वाली बात भी सही नहीं है। दरअसल, असली परेशानी तेल की रिफाइनिंग को लेकर है। कोविड के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटे दुनिया के सभी देशों में तेल की खपत बढ़ी है। भारत में भी अप्रैल के मुकाबले मई महीने में 8 फीसदी तेल की खपत बढ़ी है, जबकि इसी दौरान तेल रिफाइनिंग करने वाली कंपनियों के काम में सुधार नहीं हुआ है, लिहाजा देश के कुछ हिस्सों में तेल कम पहुंच रहा है। वजह कोई भी हो, लेकिन जिस तरह पेट्रोल पंप दिन पर दिन सूख रहे हैं, उससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 18, पृष्ठ-48, 16 से 30 जून, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

भाजपा की तैयारी

2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में कभी भी अनबन सतह पर नहीं दिखाई देती। देश में एकमात्र मप्र ऐसा राज्य है, जहां भाजपा का संगठन सबसे मजबूत और संगठित है।

● **सतीश मिश्रा,** भोपाल (म.प्र.)

कांग्रेस मैदान में

आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। कमलनाथ सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने आलाकमान के निर्देश पर अपने-अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी वचन-पत्र तैयार करने में जुट गई है। जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगी।

● **पूनम सोनी,** इंदौर (म.प्र.)

शौचालयों में ताले

मप्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत को गांव में शौचालय निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी। प्रत्येक शौचालय के लिए 3.50 लाख रुपए दिए गए। पंचायतों ने शौचालयों का निर्माण भी करा लिए, लेकिन अधिकांश पर ताले लगे हैं। बाहर से आने-जाने वाले इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

● **ऋतु वर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

दुनियाभर में फैला वायु प्रदूषण

देश सहित दुनियाभर की हवा जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। दुनिया की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर है जो धीरे-धीरे उसकी जान ले रही है। इतना ही नहीं वातावरण में बढ़ता प्रदूषण अस्थमा, कैंसर और मानसिक रोगों जैसी बीमारियों की जड़ है। जिसका बोझ दुनिया के लाखों लोगों को ढोना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण समाज के कमजोर तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। यूएन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी रैंकिंग जारी की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की कैपिटल सिटी के रूप में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे खराब गुणवत्ता वाले 50 शहरों में से 35 शहर भारत के हैं।

● **राजेश मिश्रा,** सीहोर (म.प्र.)

पंजाब मॉडल की तारीफ

आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सुशासन का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गया है। जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या अन्य राज्य भी पंजाब के इस मॉडल को अपनाएंगे। मप्र में भी कई भाजपा नेता गुपचुप तरीके से कहने लगे हैं कि मप्र में भी इस फॉर्मूले को लागू कर देना चाहिए।

● **प्रमोद चौहान,** ग्वालियर (म.प्र.)

कब खत्म होगा वंशवाद

कांग्रेस को अगर वंशवाद की पार्टी कहेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी और अब धीरे-धीरे प्रियंका गांधी भी कांग्रेस में वंशवाद का उदाहरण बन गई हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी दिन पर दिन रसातल में जा रही है, उसके बावजूद पार्टी वंशवाद से मुक्त नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि पार्टी के नेता भी वंशवाद को बढ़ाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस कारण पार्टी मजबूत नहीं हो रही है।

● **अहमद अली,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अधर में नकवी का राजनीतिक भविष्य!

भाजपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी को जाना जाता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा में नकवी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी नकवी का पत्ता कटने के आसार बन रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अभी राज्यसभा के सांसद हैं उनका राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है लेकिन भाजपा ने उनके नए कार्यकाल के लिए फिर से राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला लिया है। ऐसे में 7 जुलाई के बाद वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। उनकी संसद पहुंचने की उम्मीद रामपुर उपचुनाव पर टिकी थी लेकिन यहां से भी उन्हें टिकट नहीं मिला है। ऐसे में कई प्रकार की कयासबाजी लगाई जा रही है कि नकवी का भविष्य क्या होगा। गत सप्ताह भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें उप्र के आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी शामिल है। माना जा रहा था कि नकवी को रामपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। उनकी जगह घनश्याम लोधी को टिकट दे दिया गया है। नकवी ने पहले भी रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था इसलिए उम्मीद थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा।

बढ़ सकती है देशमुख की मुश्किलें

भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में 59 पेज की चार्जशीट फाइल की है। देशमुख के अलावा उनके निजी सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ आरोप पत्र फाइल किया गया है। बता दें कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सीबीआई ने देशमुख, पलांडे और शिंदे को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ 21 अप्रैल 2021 को ही भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद उन पर केस दर्ज किया गया था। 20 मार्च 2021 को शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने कुछ मुंबई पुलिस के अफसरों को 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इसमें सचिन वझे भी शामिल था। मुंबई पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सचिन वझे को सीबीआई ने राहत दे दी है। अब उसे सरकारी गवाह बनाया जाएगा। कोर्ट ने वझे के सामने शर्त रखी थी कि माफी के बदले सरकारी गवाह बनकर खुलासे करने होंगे। उसने शर्त स्वीकार कर ली। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।

तेज हुई थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई क्षेत्रीय नेता खुद को केंद्र में स्थापित करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। इस सूची में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का नाम भी शामिल हो चुका है। केसीआर ने पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय राजनीति, केंद्र की नीतियों, संघीय व्यवस्था, भारत के विकास में राज्यों का योगदान सहित कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यही नहीं इसके बाद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ केसीआर चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे तब तक आंदोलन करते रहें जब तक कि उन्हें एमएसपी की संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती। केजरीवाल से मुलाकात के पहले राव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की थी। इससे पहले वो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। उनकी इस कवायद को लेकर माना जा रहा है कि चंद्रशेखर 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं।

अखिलेश की बढ़ती मुश्किलें

अखिलेश यादव इन दिनों कई बड़े नेताओं के बागवती रुख से जूझ रहे हैं। इस बीच विधानसभा में जिस तरह सपा अलग-थलग पड़ती दिखी उससे राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी की राह आसान नहीं मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पर अपनों का दबाव काफी बढ़ चुका है और यदि समय रहते उन्होंने बागी सुरों को शांत नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल बीते हफ्ते उप्र सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भारी शोर-शराबे के बीच अभिभाषण पढ़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि, महंगाई, कानून-व्यवस्था और आवारा पशु जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच नंबर बढ़ाने की कोशिश में किया गया हंगामा अखिलेश यादव के लिए ही उलटा पड़ता दिखा।

वसुंधरा की बढ़ी बेचैनी

अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे व कमल निशान पर लड़े जाने के संकेत दिए जाने के बाद राज्यों के क्षत्रपों में बेचैनी बढ़ गई है। खुद नेता तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनके खेमे मुखर होने लगे हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व मप्र जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं। खासकर राजस्थान, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमा और प्रदेश के मौजूदा नेतृत्व वाले खेमा के बीच तनातनी बनी रहती है। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी ने इस बात को साफ करने की कोशिश की थी कि आने वाले चुनावों खासकर राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा व कमल निशान ही सबसे ऊपर होगा। गौरतलब है कि राजस्थान में पार्टी में सबसे ज्यादा खेमेबाजी है। केंद्रीय नेतृत्व विभिन्न खेमों में समन्वय करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार दबाब बनाए हुए हैं कि पार्टी को वसुंधरा राजे के चेहरे को सामने लाना चाहिए।

मंत्रीजी को भी दिखाया आईना

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा गर्म है कि बड़े साहब ने जब से प्रशासन की कमान संभाली है, तब से किसी की भी मनमानी नहीं चल पा रही है। इससे अफसरों के साथ कई मंत्री भी आहत हैं। विगत दिनों एक ऐसे ही मामले में बड़े साहब ने एक मंत्रीजी को आईना दिखा दिया। दरअसल, प्रदेश के एक सबसे बड़े विभाग में एक लंबित भुगतान को लेकर उस विभाग के मंत्रीजी सक्रिय हुए थे। मंत्रीजी ने दम भरा था कि जो भुगतान वर्षों से लंबित है, उसे मैं करा दूंगा। बता दें कि यह भुगतान उस समय से लंबित है, जब इस विभाग की कमान एक साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले 1987 बैच के आईएएस संभाल रहे थे। विभाग में एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे साहब ने भी उक्त पेमेंट को कराने का प्रयास किया था, तो उन्हें अर्श से फर्श पर आना पड़ा था। हालांकि साहब के रिटायरमेंट के बाद मंत्रीजी के हस्तक्षेप से बड़े साहब को बिना बताए आधा भुगतान कर दिया गया। ऐसे में मंत्रीजी ने बकाया बिल का भुगतान करने दोबारा प्रयास किया तो बड़े साहब ने हस्तक्षेप करते हुए भुगतान न करने का निर्देश दिया। यही नहीं बताया जाता है कि बड़े साहब ने यहां तक कह दिया है कि मेरे रहते कोई भी यह पेमेंट नहीं करा सकता। जो इसका भुगतान करेगा, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं आधा भुगतान करने वालों पर भी साहब गाज गिराने की तैयारी में हैं।

प्रतिमा के चक्कर में अटका उद्घाटन

कई बार किसी की जिद इस कदर भारी पड़ जाती है कि बड़े से बड़ा मामला अधर में लटक जाता है। ऐसी ही जिद के शिकार इस समय 1999 बैच के एक आईएएस अधिकारी हुए हैं। दरअसल, दक्षिण भारत के मूल निवासी ये साहब इस समय एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो विभाग सामाजिक समरसता और न्याय के लिए काम करता है। साहब के विभाग का कार्यालय राजधानी के एक उपनगर में बनकर तैयार है। साहब यहां पर एक प्रतिमा लगाना चाहते हैं। यह प्रतिमा एक धर्म विशेष की पहचान कराती है। सूत्रों का कहना है कि साहब की मंशा थी कि उनके सपने को मुख्यमंत्री साकार करें, लेकिन उन्होंने इस भवन का उद्घाटन करने से मना कर दिया है। बताया जाता है कि सरकार की मंशा है कि इस सरकारी भवन में ऐसी कोई प्रतिमा न लगाई जाए जो विवाद का विषय बन जाए। उधर, साहब हैं कि हर हाल में उक्त प्रतिमा को स्थापित करने पर तुले हुए हैं। साहब की इस अति महत्वाकांक्षा का असर यह हुआ है कि बनकर तैयार हुआ भवन अभी तक उद्घाटन की राह ताक रहा है। उधर, भवन बनाने वाली एजेंसी की परेशानी और बढ़ गई है।

सैय्या नहीं बन पाए साहब

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक प्रमोटी महिला आईपीएस के समर्पण की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि मैडम ने अपने प्रमोटी आईपीएस पति को साहब (एसपी) बनाने के लिए खूब हाथ-पैर मारे, लेकिन न तो उनकी मेहनत और न ही उनका जुगाड़ काम आया। हद तो यह रही कि मैडम ने प्रदेश के बलवान मंत्रीजी को भी पटाकर इस काम पर लगाया था। लेकिन फिर भी दाल नहीं गल पाई। मैडम प्रतिनियुक्ति पर देश की राजधानी में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनको हर वक्त अपने पति की चिंता सताए रहती है। मैडम के पति प्रदेश की राजधानी में सेवारत हैं। मैडम का सपना है कि जल्द से जल्द उनके पति को किसी जिले की कमान मिल जाए। इसके लिए वे दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपने संपर्कों के माध्यम से पति को एसपी बनाने के लिए जुगाड़ पर जुगाड़ लगा रही हैं। मैडम को अनुमान था कि इस बार तबादले पर से प्रतिबंध हटने के साथ ही साहब की कहीं न कहीं लॉटरी लग जाएगी। लेकिन इनकी राह में पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता आड़े आ गई है। वैसे पति को एसपी बनाने के लिए मैडम ने अभी तक जितने भी जुगाड़ लगाए हैं, कोई काम नहीं आए हैं। फिर भी मैडम निराश नहीं हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक तबादले होंगे, तब वे अपने पति परमेश्वर को एसपी बनवा देंगी। बताया जाता है कि मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया है।

क्लास फेलो जो ठहरा

ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होय... ये कहावत इन दिनों प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर सटीक बैठ रही है। दरअसल, माननीय जिस विभाग के मंत्री हैं, कहा जाता है उस विभाग में जमीन से सोना निकलता है। खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश में हर माननीय की ख्वाहिश होती है कि वह इस विभाग का मंत्री बने। वर्तमान में जिन माननीय को इस विभाग की कमान मिली है इन दिनों उनकी दसों उंगलियां घी में डूबी हुई हैं। ऐसे में सोने पर सुहागा यह कि मंत्रीजी को दो खदानों में पार्टनरशिप भी मिल गई है। सूत्रों का कहना है कि लंबे समय तक कमाई के लिए मंत्रीजी चाहते थे कि बिना कुछ दिए उन्हें ऐसा रास्ता मिल जाए, जिससे निरंतर लक्ष्मी आती रहे। मंत्रीजी की यह मंशा इस समय पूरी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दो जिलों में मंत्रीजी को एक ऐसा पार्टनर मिल गया है, जो उनका क्लास फेलो भी था। जिन खदानों को पूर्व में परेशान होकर ठेकेदार छोड़ गए थे, उनको मंत्रीजी ने अपने क्लास फेलो को दिलाकर अपना हित भी साध लिया है।

ठाकुर साहब की जेबें सिलीं

आदिवासी बाहुल्य एक जिले के एसपी साहब की चर्चा इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही हैं। दरअसल, साहब ने जब से जिले की कमान संभाली है उनकी दरियादिली और कंजूसी बढ़ गई है। बताया जाता है कि आदिवासी बाहुल्य इस जिले में साहब महिला थानाधिकारियों के साथ पैग से पैग लड़ाने में हिचक नहीं कर रहे हैं। एक महिला थानाधिकारी से तो उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। दरअसल, साहब जिले में अकेले निवास कर रहे हैं, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए साहब दरियादिली का सहारा ले लेते हैं। वहीं साहब की कंजूसी भी इस कदर चर्चा में है कि लोग यह कहने लगे हैं कि साहब की जेबें पूरी तरह सिली हुई हैं। आलम यह है कि साहब अपने खर्चे के लिए अपने पॉकेट से चवन्नी भी खर्च नहीं करते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि साहब अपना टूथब्रश भी थाना इंचार्ज से खरीदवाते हैं। साहब की दरियादिली और कंजूसी से महकमे के अधिकारी-कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन करें तो क्या, क्योंकि साहब के आगे सब मजबूर हैं।

अपनी सुस्ती का ठीकरा केंद्र पर

पंचायत चुनाव के शंखनाद के साथ ही आधी-अधूरी सड़कों का मुद्दा गर्मा गया है। जब नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उन्हें मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोकनिर्माण विभाग और मंत्री गोपाल भार्गव केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि विभाग के पास पर्याप्त बजट है। निष्क्रियता और सुस्ती के कारण लोनिवि पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया है और ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के विभाग ने बजट से अधिक यानी 105 प्रतिशत खर्च करके वाहवाही लूटी थी। खर्च बजट आवंटन से ज्यादा होने की वजह लोक निर्माण विभाग ने जिन विभागों का काम किया, उसे उनसे जो राशि प्राप्त हुई, लेकिन उसे मूल बजट में नहीं दिखाया गया। अब विभाग की हकीकत सामने आने लगी है। यही नहीं विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। गांवों की सड़कों के निर्माण, मेंटेनेंस से लेकर मॉनिटरिंग का सारा काम जीएम और एजीएम के भरोसे रहता है। प्रदेश में जीएम के 75 में से 22 पद खाली पड़े हैं। विभाग ने इनके लिए भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। इंजीनियरों के इंटरव्यू भी हो चुके है पर विवादों के चलते अक्टूबर 2021 में नियुक्तियां रोक दी गई। इसका असर मेंटेनेंस पर पड़ रहा है।

लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भले ही आधी-अधूरी सड़कों के लिए केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिलने का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी विभाग के पास 522 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इसके लिए विभाग के पास कोई कार्ययोजना ही नहीं है। विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि सड़कों के विकास के लिए पिछले साल मिले 1,252 करोड़ में 730 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 1,113 करोड़ के स्थान पर 737 करोड़ रुपए खर्च हुए। आदिवासी बहुल झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और शहडोल जिलों में निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों में विभिन्न विकास कार्य के लिए हर साल एक हजार करोड़ से ज्यादा की राशि आदिवासी उपयोजना में आवंटित होती है। इन जिलों के पिछले 6 साल के आंकड़े देखें, तो वहां शत-प्रतिशत बजट राशि खर्च नहीं हुई। झाबुआ, अलीराजपुर, धार अनसूचित जाति क्षेत्रों बड़वानी, खंडवा, खरगोन, केमजरे-टोलों में बुरहानपुर, रतलाम, मंडला, निर्मित होने वाली सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, सड़कें नहीं बन पा रही छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, सीधी, श्योपुर, होशंगाबाद, बैतूल जिलों के 89 विकासखंडों में सड़कों के लिए जाएगा। बजट जारी किया जाता है, लेकिन उपयोजना में आवंटित होने वाली राशि का पूरा उपयोग इन जिलों में नहीं हो रहा है।

कागज से बाहर नहीं आ पाईं 2 हजार करोड़ की सड़कें

सड़कों के निर्माण और संधारण में हो रही लेतलाली के लिए लोक निर्माण विभाग फंड का रोना रो रहा है, लेकिन प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने जिन 2,000 करोड़ की सड़कों को मंजूरी दी है, वे अभी तक अधर में हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार से केंद्रीय सड़क निधि में पिछले साल 24 सड़कों को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी तक अधिकांश सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। करीब एक दर्जन के तो टेंडर भी नहीं किए गए हैं। गौरतलब है कि वैसे 2020 में मप्र को केंद्र से केवल एक ही सड़क मिली थी। उधर, 2019 में स्वीकृत सड़कों के काम भी आधे-अधूरे पड़े हुए है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 2021 में मप्र को करीब 2 हजार करोड़ की सड़कों को मंजूरी दिलाई थी। लेकिन आज तक अधिकांश सड़कों का काम अधर में हैं। पीडब्ल्यूडी के सचिव आरके मेहरा का कहना है कि केंद्रीय सड़क निधि फंड में स्वीकृत सड़कों में से कुछ के टेंडर हो चुके हैं। कुछ सड़कें बची हैं, जिनके टेंडर जल्द कर दिए जाएंगे। इनका काम बारिश बाद प्रारंभ हो जाएगा।

मप्र में एक-एक गांव को सड़कों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 90 हजार किमी सड़कों का जाल बिछा दिया है। इससे गांवों में आने-जाने की व्यवस्था सुगम हो गई है। लेकिन भारी वाहनों की धमाचौकड़ी और मरम्मत नहीं होने के कारण करीब 20 हजार किमी सड़कें खराब हो गई हैं। अब इन सड़कों की मरम्मत पंचायतों में 'सरकार' बनने के बाद की संभव है। ऐसे में इस साल मानसून में ये सड़कें ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। क्योंकि मानसून के दौरान सड़कों की मरम्मत होना संभव नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी की अनुसार, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पिछले कुछ साल से खराब होती जा रही है। राजनीतिक उठापटक, कोरोना संक्रमण और बजट के अभाव के कारण सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी। अब जाकर स्थिति सामान्य हुई है तो पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग गई है। ऐसे में सड़कों के सुधार का काम अब पंचायतों के गठन के बाद ही होगा। तब तक प्रदेश में मानसून आ चुका होगा। ऐसे में करीब 20 हजार किमी खराब सड़कों की मरम्मत मानसून के बाद होने की ही संभावना है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली 20 हजार किमी से अधिक सड़कें उधड़ गई हैं। इनके अब चुनाव के बाद ही ठीक होने की संभावना है, क्योंकि पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई है। ये सड़कें 16 जिलों की हैं। ऐसे में **खस्ताहाल सड़कें** बारिश में आफत बन सकती है। सड़कों के ठीक नहीं होने के पीछे बड़ी वजह बजट और अमले की कमी बताई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि इन सड़कों के लिए उपरोक्त 16 जिलों के सांसद और विधायकों ने भी पत्र लिखे हैं। चुनाव से पहले इन सड़कों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिया जा चुके हैं। सीएस की साधिकार समिति की बैठक में भी मेंटेनेंस का मुद्दा उठ चुका है। हाल ही में विभागीय बैठक में शिकायतों के चलते इंदौर जीएम को विभागीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने फटकार लगाई है। इसके बाद बजट के लिए फंड जारी किए गए हैं।

● **सुनील सिंह**

इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कवायद तेज

पीथमपुर और देवास जैसे क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

मप्र के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला गत दिनों सीआईआई मप्र के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी इसमें शामिल हुए। शुक्ला ने कहा कि इंदौर के 35 से 40 किमी के दायरे में अंतरराष्ट्रीय विमानतल बनने से पीथमपुर और देवास जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इंदौर और इसके आसपास मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बड़ी संख्या में है। विमानतल तैयार होने से लॉजिस्टिक क्षेत्र बेहतर होगा। प्रदेश भारत के मानचित्र में बीच में आने से कई लाभ हैं। हम 12 घंटे के सफर में आसपास के किसी भी शहर में पहुंच सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क बनने से भी उद्योगों को गति मिलेगी। नई उद्योग नीति के संदर्भ में महिंद्रा और टाटा जैसी कई कंपनियों की राय भी ली गई है। इसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए सरकार कई काम कर रही है। मेडिकल पार्क के साथ ही कई तरह के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जहां सभी क्षेत्रों के उद्योगों को जगह मिलेगी। ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इंदौर सहित पूरे प्रदेश में काम किया जा रहा है। फार्मा और कई तरह के पार्क तैयार होंगे। आने वाले कुछ समय में उद्योग नीति भी आ रही है। इसमें प्रदेश के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह की बातों को शामिल किया गया है।

इंदौर-भोपाल के बीच में प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रीयल हब में बनने वाले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए कवायद तेज हो गई है। हाल ही में गौतम अडाणी के साथ ही कई अन्य औद्योगिक घरानों ने संभावित क्षेत्र का दौरा कर संभावनाओं को तलाशा। जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कई औद्योगिक घराने निवेश को उत्सुक हैं। प्रदेश सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। देश के प्रमुख एयरपोर्ट में जगह की कमी के बीच इस एयरपोर्ट के मध्यभारत के गेटवे बनने की भी पर्याप्त संभावना है। यहां से यात्री उड़ान चलने के साथ-साथ कार्गो उड़ान भी चल सकेगी। वहीं कई विदेशी एयरलाइंस जिनके बड़े विमान प्रदेश के एयरपोर्ट के छोटे रनवे पर नहीं उतर पाते हैं। वे भी प्रदेश में अपने संचालन कर सकेंगी।

उद्योग विभाग इस योजना को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। गत दिनों इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें यहां पर 25 से 30 हजार एकड़ इलाके में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनेगा। जानकारों का कहना है कि अगर योजना पर सही तरीके से काम हो जाता है और एयरपोर्ट बन जाता है तो उससे पूरे प्रदेश को फायदा हो जाएगा। अभी इंदौर प्रदेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां से प्रदेश की एकमात्र सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी संचालित होती है। लेकिन यहां का रनवे भी विदेशी एयरलाइंस के बड़े विमानों के लिए छोटा है। वहीं कोरोनाकाल के पहले ही यहां का टर्मिनल यात्रियों के लिए छोटा पड़ने लगा था। यहां पर भी नए टर्मिनल की मांग की जा रही है। नया एयरपोर्ट बनने के बाद इंदौर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसे निर्माण में सरकार को कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान रखना होगा। इंदौर से भोपाल के बीच की करीब 200 किलोमीटर की दूरी है। यहां तक पहुंच मार्ग, कनेक्टिविटी, कार्गो सुविधा आदि का ध्यान रखा जाए तो प्रदेश से निर्यात भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे दुबई को पश्चिमी विश्व का गेटवे कहा जाता है। उसी तरह से यह दुनिया के लिए भारत का गेटवे बन सकता है। यहां आकर लोग आगे जा सकेंगे। मध्यभारत में होने से पूरे भारत का सफर करना आसान हो सकेगा।

सीआईआई के चेयरमेन सुधांशु जोहरी बताते है कि सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है। सरकार यहां पर इंडस्ट्रीयल हब तो बना ही रही है। साथ ही एयरपोर्ट भी बना रही है, जिससे इंदौर और आसपास के औद्योगिक इलाके को तो फायदा मिलेगा ही लेकिन इसके साथ भोपाल और उसके पास के औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ मिल जाएगा। यहां बनने वाला सामान सीधे देश-विदेश में विमान से भेजा जा सकेगा, जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यहां के माल को सड़क या रेल से भेजने के बजाय जल्द भेजा जा सकेगा। प्रदेश से कई चीजों को विदेश भेजा जाता है।

ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि अगर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनता है तो यह प्रदेश के लिए काफी बेहतर बात होगी। अगले कुछ सालों में इंदौर एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाना है। इसके बाद भोपाल का नंबर आएगा। वहीं देश के बड़े एयरपोर्ट पर जगह की कमी है। मध्यभारत की ही बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई जैसे एयरपोर्ट जगह की कमी से जूझ रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग के लिए सीमित जगह है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने पर एयरलाइंस यहां पर विमान पार्क करेगी। जिससे उड़ानें ज्यादा चलेंगी। जिससे यात्रियों को कम कीमत में टिकट भी उपलब्ध हो सकेंगे।

एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने के साथ ही इस पूरे क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी। ज्यादा जगह होने पर एयरलांइस इसे अपना बेस बना सकती है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में भी नए रोजगार पैदा होंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मप्र में बनाए जाने की संभावना तेज हो गई है। इंदौर से 35 से 40 किमी के दायरे में यह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि देवास और सोनकच्छ के बीच यह एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, हालांकि एक संभावना यह भी है कि देवास जिले के चापड़ा क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है लेकिन यह बताया जा रहा है कि उद्योग विभाग ने इसके लिए 25 हजार एकड़ जमीन तलाश ली है। दरअसल, यात्रियों के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब को बढ़ावा देने के लिए यह एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए मप्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जमीन के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस जमीन से भोपाल-इंदौर रोड, भोपाल-जयपुर रोड, शाजापुर-देवास रोड और नरसिंहगढ़ को आपस में जोड़ा जाएगा।

● **राकेश ग्रोवर**

मप्र में देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से पंचायत चुनाव का घमासान शुरु हो गया है। गैर राजनीतिक होने के बाद भी पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की साख दांव पर है। क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने समर्थकों को सरपंच से लेकर अन्य पदों पर मैदान में उतारा है। लेकिन इन सबके बीच इस बार का पंचायत चुनाव मिसाल बनने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश की अधिकांश पंचायतें समरस हो रही हैं।

पंचायत चुनाव बनेंगे मिसाल

मप्र में हो रहे पंचायत चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विचारधारा वाले जमीनी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे भाजपा और कांग्रेस का जमीनी वोटबैंक मजबूत होगा। वहीं इस बार पंचायत चुनावों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस अपील का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन पंचायतों में चुनाव निर्विरोध होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पंचायतें समरस हो रही हैं। यानी पंच-सरपंच या अन्य पद पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा रहे हैं।

दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करके मुख्यमंत्री चौहान ने गांव में नया राजनीतिक अध्याय लिखने की कोशिश की है। राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां निर्विरोध निर्वाचन की दिशा में कदम न बढ़ाया गया हो। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पोलिंग स्टेशन पर निर्विरोध निर्वाचन का प्रयास करते दिखाई दिए। इस कारण चुनाव में उनका पलड़ा स्वाभाविक तौर पर भारी दिखाई देगा। समरसता के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है तो कई कदम एक साथ इस दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, अगले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 51 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा के चुनाव अगले साल के नवंबर-दिसंबर में होना है। राज्य में इन दिनों पंचायत और नगरीय निकाय दोनों की ही निर्वाचन प्रक्रिया एक साथ चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। जबकि नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं। ये दोनों चुनाव अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन चुनावों में भाजपा की रणनीति अधिकतम वोट और समर्थन हासिल करने की है। ग्रामीण इलाकों में समरस पंचायत का उपयोग भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कर रही है। जबकि कांग्रेस इन चुनावों का उपयोग रणनीतिक तौर पर नहीं कर रही है। ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस पार्टी सक्रिय भी दिखाई नहीं दे रही है। उसने इस चुनाव से दूरी बना रखी है।

मप्र सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रही है। यह मिशन तभी कारगर होगा, जब प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव कराने पर जोर दिया है, ताकि पूरी पंचायत एकमत होकर एक व्यक्ति को अपनी पंचायत के विकास की जिम्मेदारी सौंप सके। समरस पंचायत को बनाने का उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में प्रेम और सद्भाव को बरकरार रखना है। पिछले कुछ चुनावों में छुटपुट ऐसी घटनाएं सामने आईं थीं जिनमें आपसी रंजिश की वजह पंचायत चुनाव रही। गांव में समरसता को बढ़ाने के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने के लिए विकास के लिए अतिरिक्त राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है। इसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होंगे, उन्हें 5 लाख रुपए का ईनाम दिया जाएगा। इसके अलावा सरपंच पद के लिए वर्तमान निर्वाचन व

नारीशक्ति ही पंच परमेश्वर

प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी और दावेदारी की लंबी कशमकश के बाद गांव की सरकार बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान मप्र की कई ग्राम पंचायतों ने अपने पंच, सरपंच का चुनाव निर्विरोध कर लिया है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि निर्विरोध चुनी गईं सभी पंच सरपंच महिलाएं हैं। यहां भी महिलाएं ही निर्विरोध चुनकर अपना परचम लहरा रही हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील क्षेत्र के ग्राम मांजरोद में 60 साल से सरपंच निर्विरोध चुनते चले आ रहे हैं। इस बार गांव की सरकार जैसे सरपंच, उप-सरपंच सहित पंचों के पदों पर सभी महिलाएं चुनी गई हैं। इसके चलते पंचायत का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। राज्य सरकार भी इस ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए की राशि देकर पुरस्कृत करेगी। वहीं बालाघाट की ग्राम पंचायत मांजरोद में बीते 60 सालों से आज तक यहां पर मतदान ही नहीं हुआ है। यहां हर बार निर्विरोध सरपंच चुनकर आते हैं। इस बार ग्राम सरकार के सभी पदों पर महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई हैं।

पिछला निर्वाचन लगातार निर्विरोध होने पर 7 लाख और सरपंच-पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। गांव के समरसता के भाव को समझते हुए जबलपुर जिले के विधायक अजय विश्नोई ने भी खुद के विधानसभा क्षेत्र में होने वाले निर्विरोध निर्वाचन के लिए ढाई लाख रुपए की राशि पुरस्कार में देने की घोषणा की है। बुरहानपुर जिले के ग्राम मांजरोद समरस पंचायत का अनूठा उदाहरण है। इस गांव की पंचायत में पिछले 60 साल से निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। इस बार इस पंचायत की महिला सरपंच सहित सभी 12 पंच पदों पर निर्विरोध महिला प्रतिनिधि बनने जा रही हैं। इसका असर गांव के सामाजिक कार्यों में भी दिखाई देता है।

राज्य के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में समरस पंचायत बनाने में सक्रिय रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल में लगातार सातवीं बार सरपंच सहित पंच निर्विरोध चुने गए। आदिवासी महिला के लिए आरक्षित पंचायत सरपंच पद पर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से शारदा आदिवासी को चुना। 32 साल पहले जगदीश कपस्या का चुनाव निर्विरोध हुआ था। इस पंचायत में ग्रामीण आपसी सहमति से मंदिर में बैठकर पंच और सरपंच पदों पर दावेदारी करने वालों से चर्चा करते हैं और सर्वसम्मति से पंच, सरपंच चुन लेते हैं। चुने गए प्रतिनिधि नामांकन की औपचारिकता पूरी करते हैं और एक-एक नामांकन होने पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है। इस साल पंचायत सरपंच पद पर शारदा आदिवासी निर्वाचित हुई हैं। निर्विरोध निर्वाचन का सबसे रोचक उदाहरण मंदसौर जिले में देखने को मिला। आदिवासी क्षेत्र राणापुर से करीब 35 साल पहले जिले के आक्याबिका में मजदूरी के लिए आए परिवार की महिला अब गांव की प्रधान होकर कमान संभालेगी। सालों से गांव के खेतों में मजदूरी करने वाली मांगी बाई अब गांव का विकास करेगी।

दमोह जिले की कुंवरपुर खेजरा ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ सभी 17 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि

सरपंच के अलावा इस ग्राम पंचायत की अन्य सभी सीटें अनारक्षित थीं लेकिन यहां किसी भी सीट पर किसी पुरुष ने नामांकन नहीं किया और सभी 17 पदों पर महिलाओं का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बीते पंचायत चुनाव में इसी ग्राम पंचायत से सोमेश गुप्ता ने सरपंच का चुनाव जीता था। सोमेश ने प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से यह चुनाव जीता था। जिसके बाद सोमेश को सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। विकास के लिए अतिरिक्त राशि के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा भी की थी कि वे समरस पंचायत में लोगों का धन्यवाद करने पहुंचेगें। मुख्यमंत्री की इस अपील का भी असर दिखाई दिया है। रतलाम जिले की धानासुता के निर्विरोध निर्वाचित पंच-सरपंच अपने मांग पत्र के साथ अब मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत आनंद और हर्ष का क्षण है कि पंचायत निर्वाचन-2022 में मप्र समरस पंचायतों की दिशा में अग्रसर हो रहा है। प्रदेश में अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के बाद हमारी बहनें और भाई निर्विरोध सरपंच और उप सरपंच चुने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समाज में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का द्योतक होने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में नामांकन-पत्रों की जांच के बाद सामने आई स्थिति पर ट्वीट कर भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सबका ध्येय केवल विकास और जन-कल्याण है। मुझे खुशी है हमारी समरस पंचायतें और हम सभी इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी बहनें बढ़ें, पंचायतें बढ़ें और मप्र विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दे, मेरी यही कामना है।

पंचायत चुनाव में बुरहानपुर जिले खकनार जनपद क्षेत्र का एक गांव उदाहरण बना है। यहां की मांजरोद खुर्द पंचायत में बीते 60 साल से बिना किसी चुनाव के ग्राम पटेल और बाद में सरपंच चुनने की परपंरा कायम थी। इस बार इस पंचायत की महिला सरपंच सहित सभी 12 पंच पदों पर निर्विरोध महिला प्रतिनिधि बनने जा रही हैं। ग्रामीण विकास का ध्येय लेकर और जन-भागीदारी को बढ़ाते हुए विकास की ओर अग्रसर होते मुख्यमंत्री चौहान पिछले माहों में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे। उन्होंने ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि सभी एकजुट होकर गांव में विकास की भावना के साथ काम करें और निर्वाचन में अपनी पंचायत को समरस बनाकर उदाहरण प्रस्तुत करें।

● **कुमार राजेन्द्र**

महिला सशक्तिकरण की मिसाल

इसी तरह मुरैना में भी निर्विरोध महिला सरपंच को चुना गया है। जिले की तीन ग्राम पंचायतें महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। यहां सरपंच और पंच के पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुना गया है। मुरैना जिला संभवतः पूरे राज्य में पहला है, जहां तीन ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को चुनावी जंग में निर्विरोध मैदान में उतारा गया है। वहीं आंवलीखेड़ा ग्राम पंचायत महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी, जिसमें सरपंच से लेकर 10 पंच निर्विरोध चुने गए। उक्त ग्राम पंचायत आष्टा विकासखंड में निर्विरोध की सूची में दर्ज होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए 15 लाख रुपए निर्विरोध चुने जाने पर दिए जाएंगे। वहीं सीहोर, धार सहित प्रदेश के कई जिलों में नामांकन पत्रों की जांच के बाद समरस पंचायत यानी निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनी है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर नजर आ रही है। इस बार के पंचायत चुनावों में पुरुषों पर महिलाएं भारी हैं। प्रदेश की 112 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं। 112 में से 75 ग्राम पंचायतों में महिलाएं निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं।

जिसने टिकट दिलाई वही जिम्मेदार!

प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों में जीत का लगभग एक ही फार्मूला है, जिसने टिकट दिलवाया है, वही प्रत्याशी को जिताएगा। कांग्रेस ने सबसे पहले अपने 15 महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। दोनों पार्टियों के महापौर प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। भोपाल ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। यहां भाजपा ने मालती राय और कांग्रेस ने विभा पटेल को टिकट दिया है। वहीं इंदौर (अनारक्षित) से भाजपा ने पुष्यमित्र भार्गव कांग्रेस ने संजय शुक्ला, जबलपुर (अनारक्षित) से भाजपा ने डॉ. जितेंद्र जामदार कांग्रेस ने जगत बहादुर सिंह अन्नू, ग्वालियर (अनारक्षित महिला) से भाजपा ने सुमन शर्मा तो कांग्रेस ने शोभा सिकरवार को मैदान में उतारा है। वहीं उज्जैन (एससी) भाजपा ने मुकेश टटवाल, कांग्रेस ने महेश परमार, सागर (अनारक्षित महिला) से भाजपा ने संगीता सुशील तिवारी तो कांग्रेस ने निधि जैन, रीवा (अनारक्षित) से भाजपा ने प्रबोध व्यास तो कांग्रेस ने अजय मिश्रा, मुरैना (एससी महिला) से भाजपा ने मीना जाटव कांग्रेस ने शारदा सोलंकी, सतना (ओबीसी) से भाजपा ने योगेश ताम्रकार तो कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा, कटनी (अनारक्षित महिला) से भाजपा ने ज्योति दीक्षित तो कांग्रेस ने श्रेया खंडेलवाल, सिंगरौली (अनारक्षित) से भाजपा ने चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा, कांग्रेस ने अरविंद सिंह चंदेल, रतलाम (ओबीसी) से भाजपा ने प्रहलाद पटेल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किया है। वहीं खंडवा (ओबीसी महिला) से भाजपा ने अमृता यादव कांग्रेस ने आशा मिश्रा को, बुरहानपुर (अनारक्षित महिला) से भाजपा ने माधुरी पटेल कांग्रेस ने शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा (एसटी) से भाजपा ने अनंत धुर्वे कांग्रेस ने विक्रम अहाके और देवास (अनारक्षित महिला) से भाजपा ने गीता अग्रवाल और कांग्रेस ने विनोदिनी रमेश व्यास को टिकट दिया है।

भोपाल में भाजपा ने मालती राय को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व महापौर विभा पटेल से होगा। भोपाल में विश्वास सारंग के सुझाव पर मालती राय को महापौर प्रत्याशी बनाया है। मालती राय को मजबूत नहीं माना जा रहा था। सारंग ने ही मालती राय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। इसके बाद कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग तीनों विधायकों ने राय को जिताने का भरोसा दिलाया। तब जाकर मालती का नाम अंतिम हुआ।

भाजपा नेताओं में महापौर के टिकट के लिए ग्वालियर में जमकर खींचतान चल रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 14 नगर निगम के मेयर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों को क्षेत्रीय नेताओं की गारंटी पर टिकट दिया गया है। सागर से संगीता तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर है। कटनी में पूर्व मंत्री संजय पाठक के समर्थक और रेत कारोबारी विनय दीक्षित की पत्नी ज्योति दीक्षित को टिकट दिया गया है। रीवा से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की गारंटी पर प्रबोध व्यास को टिकट दिया गया है। जिन सीटों पर दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, वहां पार्टी ने नए फॉर्मूले के तहत टिकट फाइनल किया है। इसके तहत जिसने टिकट देने की सिफारिश की, उस पर ही उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी है। यानी नगर सरकार बनाने का दारोमदार सीधे तौर पर क्षेत्रीय नेताओं पर है। सामान्य सीट सिंगरौली से ओबीसी उम्मीदवार को उतारने में ब्राह्मणों की नाराजगी के बावजूद विधायक रामलल्लू वैश्य की सिफारिश पर चंद्रप्रताप विश्वकर्मा को टिकट दिया गया है। खंडवा से उम्मीदवार अमृता यादव को जिताने की जिम्मेदारी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा ने ली है। भोपाल में फंसे पेंच को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहां मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर ने उम्मीदवार मालती राय को जिताने की गारंटी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में गारंटी का फार्मूला इस्तेमाल किया है। दरअसल, क्षेत्रीय नेताओं के बीच अपने समर्थक को टिकट दिलाने की खींचतान को खत्म करने के लिए यह फार्मूला लागू किया गया। भोपाल से उम्मीदवार मालती राय दो बार पार्षद का चुनाव हार चुकी हैं। बावजूद, इसके विधायक उन्हें टिकट देने पर अड़े रहे।

भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने भोपाल से ओबीसी वर्ग के नए चेहरे को आगे बढ़ाने की कवायद की थी, लेकिन स्थानीय विधायकों के दबाव के चलते फैसला बदलना पड़ा। जब कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई, तो मालती राय के दावे को सभी ने खारिज कर दिया था। उनकी जगह नया नाम तलाशने का निर्णय लिया गया था, लेकिन भोपाल के विधायकों ने साफ कर दिया था कि मालती राय ही बेस्ट कैंडिडेट हैं, जबकि मुख्यमंत्री नए चेहरे को टिकट देना चाहते थे। क्योंकि मालती दो बार पार्षद का चुनाव हार चुकी थीं। ऐसे में कांग्रेस की विभा पटेल के सामने पार्टी कमजोर कैंडिडेट उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। बाद में मुख्यमंत्री ने तीनों विधायकों की राय के बाद मालती राय पर सहमति दे दी। जबलपुर से जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

संघ की पसंद के 3 उम्मीदवार

भाजपा के महापौर पद के 3 उम्मीदवार संघ की पसंद से मैदान में उतारे गए हैं। जबलपुर से उम्मीदवार डॉ. जितेंद्र जामदार की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है। वे पिछले कई वर्षों से संघ के विभिन्न संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं। फिलहाल वे जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। इसी तरह सतना से योगेश ताम्रकार को मौका दिया गया है। उनके पिता शंकर ताम्रकार प्रांत संघ चालक रहे हैं। उन्हें भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाया गया। अब उन्हें महापौर का टिकट दिया गया है। इसमें सबसे रोचक घटनाक्रम इंदौर की टिकट को लेकर हुआ। यहां से डॉ. निशांत खरे को टिकट देने की पैरवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। हालांकि उन्होंने विकल्प के तौर पर मधु वर्मा के नाम पर विचार करने का सुझाव दिया था, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला का नाम आगे बढ़ाकर पेंच फंसा दिया था।

फेरों के नाम पर हेराफेरी

भिलाला आदिवासी समिति के अध्यक्ष ने ली राशि

बड़वाह में आयोजित सामूहिक विवाह के संबंध में गजराजसिंह चौहान ने कहा कि भिलाला आदिवासी समिति के अध्यक्ष महिम ठाकुर द्वारा 11 हजार रुपए जमा करवाए। चौहान ने कहा, इनको पोस्टरों में अध्यक्ष दर्शाकर भ्रमित किया गया। ठाकुर के संबंध में रिटायर समन्वयक अधिकारी अनारसिंह सोलंकी ने कहा कि बड़वाह समिति के अध्यक्ष ठाकुर है। उनके द्वारा 30 जोड़ों का विवाह में 11-11 हजार रुपए दोनों पक्षों से लिए गए। ऐसे कई पीड़ित हैं जिन्होंने बयान दर्ज कराए हैं। बयान दर्ज करवाने वालों में सुनील बड़ोले के साथ ही अन्य लोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि महिम ठाकुर भाजपा जिला महामंत्री के पद पर भी है। जांचकर्ता अधिकारी ने बताया कि खरगोन एसपी के समक्ष मामले रखे हैं। जल्द ही एफआईआर हो सकती है। यह कार्रवाई खरगोन थाने में ही संभव है। डिप्टी कलेक्टर सिंह ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया है। इनके अलावा विजय कोचले, विश्राम डुडवे, बलवंत डावर, महिम ठाकुर, पीसीओ नरेंद्र बड़ोले, श्यामलाल उपाध्याय चंदावड़ व अन्य लोगों पर अवैध वसूली व धमकाने जैसे तथ्यों व बयानों के आधार पर एफआईआर की जाएगी। जांच आगे भी जारी रहेगी।

सरकारी योजनाओं को पतीला लगाने में नेता, पदाधिकारी व सरकारी कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। अवैध वसूली के चक्कर में सरकारी योजना को बट्टा लगाने का काम खरगोन जिले में हुआ है। दरअसल यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ अपात्रों को दिलाने के लिए अवैध वसूली की गई। मामले की शिकायत 31 मई को सीएम हेल्पलाइन के जरिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तक पहुंची तो उन्होंने जांच दल गठित किया। 11 दिनों की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सरकारी सिस्टम के तहत नवयुगल के सात फेरों में कुछ शासकीय कर्मचारी और संगठन पदाधिकारियों ने हेराफेरी की है। एक शिक्षक व सचिव को निलंबित किया गया है जबकि अवैध वसूली मामले में बड़वाह के भाजपा जिला महामंत्री सहित 6 लोगों पर एफआईआर के आदेश भी दिए हैं और नोटशीट चलाई है।

31 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गड़बड़ी की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन सहित व्यक्तिगत फोन पर तथा मीडिया के जरिए कलेक्टर तक पहुंची। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर ओमनारायण सिंह और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को संयुक्त रूप से जांच सौंपी। प्राथमिक तौर पर जांच में लिप्त शासकीय हाईस्कूल कदवाली के शिक्षक रोहित मनाग्रे और मांडवखेड़ा के सचिव मालसिंह बर्डे को निलंबित किया है। समिति के सदस्य और डिप्टी कलेक्टर ओमनारायण सिंह ने बताया 31 मई के बाद कई पीड़ितों के बयान लिए हैं।

मप्र के एक मामले में भाजपा जिला महामंत्री सहित 6 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कुछ सरकारी कर्मचारियों और बिचौलिए कथित समाजसेवियों ने भ्रष्टाचार का बट्टा लगाया है। योजना का लाभ अपात्रों को दिलाने अवैध वसूली की गई। मामले की शिकायत 31 मई को सीएम हेल्पलाइन के जरिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तक पहुंची तो उन्होंने जांच दल गठित किया।

11 दिनों की जांच में स्पष्ट हुआ है कि सरकारी सिस्टम के तहत नवयुगल के सात फेरों में कुछ शासकीय कर्मचारी व संगठन पदाधिकारियों ने हेराफेरी की है। मामले में एक शिक्षक और सचिव को निलंबित किया गया है। जबकि अवैध वसूली मामले में बड़वाह के भाजपा जिला महामंत्री सहित 6 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। नोटशीट चलाई गई है। जांच के दौरान प्राथमिक तौर पर जांच में लिप्त पाए गए शासकीय हाईस्कूल कदवाली के शिक्षक रोहित मनाग्रे और मांडवखेड़ा के सचिव मालसिंह बर्डे को निलंबित किया गया है। समिति के सदस्य और डिप्टी कलेक्टर ओमनारायण सिंह ने बताया 31 मई के बाद कई पीड़ितों के बयान लिए गए हैं।

जांच में कई शिकायतें सामने आईं, जिनमें भगवानपुरा जनपद के दामखेड़ा निवासी वर जगदीश अवासे ने बयान में कहा कि 16 मई को गलतार के सामूहिक विवाह में उनकी शादी रजनी बर्डे से हुई। मांडवखेड़ा के सचिव मालसिंह बर्डे ने निशुल्क विवाह होने के बावजूद वर जगदीश और वधू रजनी से 5100-5100 रुपए विवाह खर्च के नाम पर लिए गए। इसके अलावा इसी आयोजन में अन्य जोड़े देवेंद्र मंडलोई व सुषमा जमरे से सचिव बर्डे ने 10,200 रुपए लेने के बयान समिति को दिए। जांच समिति ने बताया कि नांदिया झिरन्या के राहुल रंधावे ने अपने बयान में कहा कि 16 मई को ही हुए विवाह आयोजन में सम्मिलित होने के लिए भिलाला समाज के अध्यक्ष विश्राम डोडवे ने 10,200 रुपए विवाह में खर्चे के नाम पर लिए। भगवानपुरा जनपद के कदवाली निवासी आशाराम व संगीता बिलरसिंह ने बताया शिक्षक रोहित मनाग्रे ने विवाह का फार्म लेकर नगर पालिका खरगोन में जमा कराया। शिक्षक ने रुपए तो नहीं लिए लेकिन आने-जाने में 3 से 4 हजार रुपए खर्च होना बताया। योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने और वसूली के मामले की शुरुआत जिस सीएम हेल्पलाइन से हुई है, उस मामले के पीड़ित पंधानिया के विजय राणे ने बयान में कहा कि खरगोन की कपास मंडी में हुए विवाह में विजय कोचले द्वारा 5000 हजार रुपए मांगे गए। इसी बात की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी हुई। इनके अलावा दामखेड़ा के दीपक जाधव ने गलतार के ही आयोजन में बलवंत डावर द्वारा 10,200 रुपए लेने के बयान दिए।

● **जितेंद्र तिवारी**

अब इंदौर में जल क्रांति मिशन

पूरे देश में स्वच्छता का डंका पीटने के बाद अब इंदौर जल संरक्षण पर तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई विशेषज्ञों को साथ लेकर एक सेल बनाया गया है, जो कुएं-बावड़ियों की सफाई से लेकर उन्हें पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए स्थानों पर सरोवर बनाने में जुटा है। शहर में 25 बावड़ियां हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद अच्छी है। वहां साफ-सफाई के बाद उन्हें नया रंग-रूप दिया जा रहा है, वहीं कई कुओं की सफाई की तो उनमें गर्मियों के दौरान भी अच्छी खासी पानी की आव मिली। गर्मियों में कई बोरिंग सूख गए, लेकिन कुओं से पानी आता देख निगम के अफसर भी हैरान थे।

पिछले दो माह से इस नई कवायद की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले तालाबों की स्थिति सुधारने के साथ-साथ उनके गहरीकरण और बारिश का पानी चैनलों के माध्यम से तालाब तक पहुंचने के मामले में ध्यान दिया गया। अभी करीब 40 से ज्यादा स्थानों पर चैनलों के गहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ-साथ अब निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की योजना जल शक्ति मिशन के तहत **अमृत सरोवर योजना** पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शहर के 5 से 7 जल विशेषज्ञों की तैनाती कर सेल गठित कर दिया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी के अफसरों के साथ-साथ कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले दिनों कई स्थानों का दौरा सेल में शामिल अधिकारियों ने किया था और उसके बाद फिर शहरभर के कुएं-बावड़ियों के उत्थान के लिए काम शुरू हुए।

कुएं-बावड़ियों की सफाई अभियान के साथ-साथ इस बात का भी रिकार्ड रखा जा रहा है कि किन कुएं-बावड़ियों से कितना कचरा और गाद निकाली गई। इसके साथ ही प्रत्येक कुएं और बावड़ी की गहराई नापकर उसका भी रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। कुएं-बावड़ियों के आसपास इसकी गहराई से लेकर उन्हें पुनर्जीवित करने से लेकर कई जानकारी वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अप्रैल से जून की अवधि में शहर के जलस्रोत सूखने लगते हैं और इसी अवधि में वहां सफाई अभियान से लेकर कई कार्य कराए जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी ने दो माह पहले जो अभियान शुरू कराया था। वह जून अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जारी रह सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर भीषण गर्मी के दौरान सफाई के बाद कुओं और बावड़ियों की स्थिति काफी अच्छी निकली। अफसरों का कहना है कि शहर में 563 कुओं और 25 बावड़ियों की सफाई के बाद क्षेत्र के उन रहवासियों का समूह बनाया जाएगा, जो इन जलस्रोतों का उपयोग करते हैं। उनके जिम्मे कुएं-बावड़ियों की सुरक्षा का काम रहेगा और इसके लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।

इंजीनियरिंग की मिसाल... विश्रामबाग की बावड़ी

जब अधिकारियों की टीम ने विश्रामबाग में 150 साल पुरानी एक बावड़ी का निरीक्षण किया तो वहां लोगों द्वारा फेंके गए कचरे के कारण बावड़ी का काफी हिस्सा ढंका हुआ था और जब वहां निगम की टीम और संसाधन लगाकर सफाई अभियान शुरू किया गया तो बावड़ी में काफी पानी जमा होने लगा। कुछ ही दिनों में बावड़ी पानी से भर गई। अधिकारियों का कहना है कि उक्त बावड़ी का निर्माण करीब डेढ़ सौ साल पहले हुआ था और इसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग वहां देखने को मिलती है, क्योंकि इस अवधि में बावड़ी का एक भी चढ़ाव या हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और उसमें पानी की आव आज भी बनी हुई है। इसके अलावा लालबाग की चंपा बावड़ी, बाणेश्वर कुंड की बावड़ी, पंचकुइया और कुछ अन्य स्थानों की बावड़ियों की सफाई का काम न केवल तेजी से चल रहा है, बल्कि वहां इस प्रकार से रंग-रोगन किया जा रहा है कि वहां लोगों का आवागमन भी हो सके। शहर में ऐसी 25 बावड़ियां हैं।

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर दो दिन पहले शहर के तालाबों की सफाई गहरीकरण और चैनलों को ड्रोन से ढूंढकर उनका गहरीकरण करने के मामले की रपट प्रकाशित हुई थी। इस रपट को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड कराया। कई अधिकारियों ने इस कार्य को बेहतर बताते हुए निगम के कार्यों की प्रशंसा की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरों का कहना है कि शहर में कुल 629 कुएं हैं, जिनमें से 563 कुओं से पानी आ रहा है और इसके लिए अब वहां बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर कुओं की न केवल साफ-सफाई की जा रही है, बल्कि वहां तमाम इंतजाम कर रहवासियों को भी इस अभियान से जोड़ने की कवायद चल रही है। पुराने इंदौर के कई हिस्सों में वर्षों पुराने कुओं में लोगों ने कूड़ा-करकट डालकर उन्हें बंद कर दिया था। जब कुओं की साफ-सफाई की गई तो 25 फीट की गहराई वाले कुओं में पानी की आव फिर से होने लगी और उनमें पानी जमा हो रहा है।

संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर संभाग के ही बुरहानपुर को शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने वाला जिला घोषित किया था। बुरहानपुर जिला शत-प्रतिशत ग्रामों में नल से जल उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला जिला घोषित हो चुका है। प्रदेश में संचालित जल-प्रदाय योजनाओं के कार्यों से अब तक चार हजार 258 ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा चुकी है। मिशन में इंदौर संभाग 905 गांवों के हर घर में नल से पानी मुहैया करवाकर प्रदेश में अग्रणी है। वहीं सीहोर जिला भी 258 ग्रामों के हर घर में जल पहुंचाकर पहले स्थान पर है। प्रदेश में मिशन के कार्य जून 2020 से प्रारंभ किए गए थे। बीते वर्ष 2020-21 और 2021-22 (22 महीनों) में 48 लाख 69 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के 4 हजार 258 गांव ऐसे हैं, जिनके हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल की पूर्ति की जा चुकी है। मिशन में शत-प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाने वाले ग्रामों की संभागवार प्रगति में इंदौर संभाग के 905, उज्जैन के 754, भोपाल के 668, जबलपुर के 497, होशंगाबाद के 362, ग्वालियर के 327, सागर के 295, शहडोल के 159, मुरैना (चंबल) 151 और रीवा संभाग के 140 ग्राम शामिल हैं।

● **विकास दुबे**

दो साल बाद बहाल हुई सांसद निधि

कोरोना संक्रमण के कारण सांसद निधि सस्पेंड होने के कारण सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांसद निधि बहाल कर दी है। ऐसे में सांसदों के पास चुनौती है कि पहले वे कौनसा काम करवाएं। प्रदेश के अधिकांश सांसदों ने प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव तैयार करवाना शुरू कर दिया है। वहीं कई सांसदों ने प्रस्ताव भेज दिया है अब उन्हें निधि का इंतजार है।

जानकारी के अनुसार सांसद निधि बहाल होने के बाद प्रदेश के 29 में 16 लोकसभा सांसदों को पहली किस्त के तौर पर कुल 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यसभा के पांच सांसदों को राशि मिलना केंद्र सरकार के एमपी लैड पोर्टल में बताया जा रहा है। जिन सांसदों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इन सांसदों के करोड़ों रुपए लागत के प्रपोजल तैयार हैं। एमपी लैड नई दिल्ली के अधिकारी कहते हैं कि जो सांसद एमपीआर यानि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा उसे प्राथमिकता पर निधि दी जाएगी। देखने में आया है कि कई सांसदों ने अपने कामों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं भेजा है। एमपीलैड्स नई दिल्ली के उप सचिव सुनील जस्सल का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांसद निधि जारी की जा रही है। पहले उन्हें किस्त भेज रहे हैं जिन्होंने पिछले कामों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए हैं। हम सांसदों के कामों को भी देखते हैं।

सांसद निधि मिलने के बाद सांसदों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर ली है। कोई किसानों पर तो कोई महिलाओं पर राशि खर्च करेगा। सतना सांसद गणेश सिंह को पहली किस्त के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा वे पूरी राशि किसानों के नाम पर खर्च करेंगे। कोरोनाकाल में किसानों के फसल उत्पादन में असर पड़ा है। गांव-गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो गए। कई गांवों में बिजली की लाइनें डलने की जरूरत है। इसलिए सभी प्रपोजल किसानों के नाम पर बनाकर दिए हैं। वहीं भिंड की सांसद संध्या राय को पहली किस्त नहीं मिली है। वे कहती हैं लोकसभा चुनाव आगे है। इसलिए महिलाओं और युवाओं के नाम पर ज्यादा राशि खर्च करेंगे। हमारे पास बड़ी संख्या में प्रपोजल आए हैं। कोरोना के कारण सांसद निधि स्थगित कर दी गई थी। इन दो सालों में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विकास कार्य कराने हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) योजना के तहत पूर्ववर्ती सांसदों की 1,723 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की जा सकी है। सरकार ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि बची हुई राशि का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब पूर्ववर्ती सांसदों के सभी अनुमोदित कार्य पूरे हो जाएं और उनका बैंक खाता बंद कर दिया जाए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संसद की प्राक्कलन समिति को बताया है कि सांसद निधि योजना के तहत पूर्ववर्ती सांसद की धनराशि का बाद के सांसद द्वारा सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रैल में 'एमपीलैड कोष योजना के तहत निधि के आवंटन एवं उपयोग की समीक्षा' विषय पर लोकसभा में पेश प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ववर्ती सांसदों की 1,723 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च नहीं की जा सकी है।

मंत्रालय के मुताबिक, बची हुई राशि का उपयोग उसी सूरत में किया जा सकता है, जब पूर्ववर्ती सांसदों के सभी अनुमोदित कार्य पूरे हो जाएं तथा उनका बैंक खाता बंद कर दिया जाए और शेष राशि बाद के सांसद के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए। समिति ने सरकार से कहा, 'उसे उम्मीद है कि मंत्रालय इतनी बड़ी राशि के बेकार पड़े रहने से जुड़ी समस्याओं की पहचान करेगा और इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराएगा।' रिपोर्ट के अनुसार, 16वीं लोकसभा में एमपीलैड योजना के अधीन सांसदों की 470 किस्तों के तहत 1,175 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 में दो किस्तों के तहत 5 करोड़ रुपए, 2016-17 में 22 किस्तों के तहत 55 करोड़ रुपए, 2017-18 में 91 किस्तों के तहत 227 करोड़ रुपए और 2018-19 में 355 किस्तों के तहत 887 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 17वीं लोकसभा के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 में 102 किस्तें लंबित हैं। मालूम हो कि एमपीलैड योजना कोविड महामारी के दौरान दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए निलंबित कर दी गई थी। बहरहाल, प्रत्येक सांसद को दो करोड़ रुपए की एक किस्त जारी कर इसे 2021-22 की बाकी अवधि के लिए बहाल कर दिया गया है।

● **जय सिंह**

राशि से अधिक का प्रस्ताव

दो साल तक सांसद निधि सस्पेंड रहने के कारण विकास कार्यों की पेंडेंसी लंबी हो गई है। ऐसे में राशि से अधिक का प्रस्ताव बनाया गया है। बैतूल के सांसद दुगार्दास उइके के अनुसार राशि 2.5 करोड़ आई है और प्रस्ताव 5-6 करोड़ के आ चुके हैं। हमने गांवों में शवदाह गृह, हैंडपंप और यात्री प्रतीक्षालयों के निर्माण पर विशेष फोकस किया है। कोरोना के कारण विकास कार्य की पहली किस्त मिलते ही महिलाओं से संबंधित काम समय पर नहीं करा सके। वहीं बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन कहते हैं- पहली किस्त अभी नहीं मिली है। क्षेत्र में पेयजल का गंभीर संकट है। राशि मिलते ही गांव-गांव टैंकर भेजेंगे। सिंचाई, स्वास्थ्य, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, आंगनबाड़ी भवन और सड़कों के निर्माण पर फोकस है। जहां समर्थक ज्यादा हैं, वहां विकास कार्य कराएंगे। उधर, इंदौर के सासंद शंकर लालवानी कहते हैं- ढाई करोड़ की पहली किस्त मिल गई है। हमने तय किया है कि पानी के टैंकर, सामुदायिक भवन, गांवों में सड़कों का निर्माण और बोरिंग पर राशि खर्च करेंगे। 2 करोड़ के प्रपोजल दे भी दिए हैं। कोरोना के समय भी हमने क्षेत्र में विकास पर पूरा फोकस किया है।

राष्ट्रपति का रण

देश में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बनते ही सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी खेमे में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची शुरु हो चुकी है। विपक्ष इस बार भाजपा की मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जुटा है, तो भाजपा सिर्फ अपने नंबर दुरुस्त करने में लगी है। वैसे भी एक बार नंबर दुरुस्त हो जाएं, फिर कोई फिक्र वाली बात तो बचती भी नहीं है।

राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही संभावित उम्मीदवारों के रूप में दो नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे – आरिफ मोहम्मद खान और मायावती। आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल केरल के राज्यपाल हैं और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बसपा की नेता हैं। ये दोनों ही नेता सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल बात ये है कि सोशल मीडिया पर इनका नाम ट्रेंड करना ही इनके रास्ते की दीवार बन गई लगती है, क्योंकि अब इनके नाम में सरप्राइज एलिमेंट तो बचा नहीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीनियर भाजपा नेता अमित शाह तो ऐसे मामलों में सरप्राइज देने के लिए ही जाने जाते हैं। ये नेता अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की मोदी-शाह की संभावित सूची का हिस्सा भी रहे होंगे तो अब अपना पत्ता साफ ही समझें। हालांकि, ये धारणा भी भाजपा में 75 साल की रिटायरमेंट की उम्र जैसी ही है। 75 पार कर लेने के बाद भी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने काफी दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहकर भाजपा के बारे में बनी ये धारणा भी बदल दी है।

बहरहाल, मायावती के लिए राहत भरी संभावना ये जरूर हो सकती है कि विपक्ष अपने खाते से बसपा नेता को उम्मीदवार बनाने पर विचार करे। मीडिया में कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही हैं कि भाजपा में उप्र में भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए मायावती या मुलायम सिंह यादव के नाम पर भी विचार चल रहा है। मायावती की बात तो एक बार सोची भी जा सकती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव को भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति भवन भेजे जाने का कोई ज्योतिषीय संयोग भी नहीं लगता। सुनने में ये भी आ रहा है कि सोनिया गांधी ने इस बार ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ये पहला मौका होगा अगर वास्तव में कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है। बेशक कांग्रेस ने ऐसा कदम इसलिए बढ़ाया है ताकि विपक्षी खेमे में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर एक जैसी सोच वाले राजनीतिक दलों के बीच आम राय बन सके। एक सवाल ये भी है कि क्या सोनिया गांधी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस के पास राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में उतारने लायक कोई नेता ही नहीं बचा है?

शरद पवार- विपक्षी खेमे में एकमात्र शरद पवार ही ऐसे नेता हैं जो सीनियर होने के साथ-साथ सबसे अनुभवी भी हैं, और आज भी अपने दम पर चुनाव जिताने का माद्दा रखते हैं। 2019 में सतारा का वाकया शायद ही कभी कोई भूल पाए। विपक्ष में शरद पवार के अलावा राष्ट्रपति पद के लिए कोई दमदार उम्मीदवार तो नजर नहीं आ रहा है। सतारा में शरद पवार की चुनावी रैली थी और मौसम बहुत खराब हो गया था। लोग शरद पवार को रैली रद्द करने की सलाह भी दे रहे थे, लेकिन जो शख्स कैंसर जैसी बीमारी को हरा चुका हो वो कहां आसानी से अपने कदम पीछे खींच सकता है। शरद पवार रैली स्थल पर पहुंचे और सीधे मंच पर चढ़ गए। बारिश में भीगते हुए शरद पवार के भाषण का वीडियो वायरल हुआ और वहां जीत भी एनसीपी के ही खाते में जुड़ी। शरद पवार ने साबित कर दिया कि दमखम पूरा बरकरार है।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर पूछताछ के लिए पेश होने जाना पड़ रहा है, लेकिन वहीं प्रवर्तन निदेशालय शरद पवार को नोटिस भेजने के बावजूद मना कर चुका है कि उनको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। नोटिस मिलने पर शरद पवार ने घोषणा कर दी थी कि वो ईडी के दफ्तर जाकर पेश होंगे, लेकिन स्थिति कल्पना से घबराए पूरे मुंबई पुलिस प्रशासन को शरद पवार से अपना कार्यक्रम रद्द करने के लिए मान मनौव्वल करनी पड़ी थी। 80 साल से ऊपर के हो चुके शरद पवार विपक्षी खेमे के जनाधार वाले नेताओं में सबसे सक्षम नजर आते हैं और विपक्षी खेमे में ऐसी अहमियत है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं सोनिया गांधी भी उनको अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। अगर विपक्ष में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में शरद पवार के नाम पर आम राय बनती है तो एनडीए का जो भी उम्मीदवार हो, शरद पवार की चुनौती सबसे जबरदस्त हो सकती है।

मायावती- अगर मायावती एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती हैं तो भाजपा की तरफ

मीरा कुमार या मनमोहन सिंह

अब अगर सवाल है कि कांग्रेस के पास राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाने लायक कोई नेता नहीं है क्या? इस सवाल के जवाब में एकमात्र नाम आता है वो है गुलाम नबी आजाद का। लेकिन गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस में बागी बने हुए हैं और अगर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व उम्मीदवार बनाने का फैसला कर भी ले तो ये जरूर देखा जाएगा कि ऐसा करने कोई राजनीतिक फायदा भी हो सकता है क्या? गुलाम नबी आजाद का प्रभाव क्षेत्र जम्मू-कश्मीर है और वहां भाजपा के अलावा किसी के लिए भी राजनीति के लिए कम भी संभावना बन रही है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, भाजपा सरकार में पद्म पुरस्कार पाने वाले गुलाम नबी आजाद एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे क्या? कहीं ऐसा न हो कि इधर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की और उधर माया मोह में पड़कर वो सेवा में सविनय निवेदन के साथ ठुकरा दें? ऐसे में कांग्रेस के पास एक विकल्प ये भी बचता है कि वो मीरा कुमार को ही फिर से मैदान में उतार दे। कोई कुछ भी कहे अब ऐसा भी नहीं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास राष्ट्रपति चुनाव लड़ने लायक एक भी नेता न बचा हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भले ही अपने लिए ऐसे प्रस्तावों को अपने लिए मिसफिट पाते हों, लेकिन मनमोहन सिंह तो हैं ना!

मुसलमान भाजपा के साथ अब भी नहीं है

गुजरे जमाने में भाजपा को सियासी सजावट के लिए कुछ मुस्लिम नेताओं की सख्त जरूरत हुआ करती थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कट्टर हिंदुत्व के प्रभाव वाली आइडियोलॉजी को कंधे पर लेकर समान सोच वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता रहा, लेकिन अब रेस में भाजपा सरपट इतना आगे निकल चुकी है कि ऐसे सारे मिथक पीछे छूट चुके हैं। सत्ता की राजनीति के हिसाब से अब तक भाजपा के दो दौर देखे जा चुके हैं। और ये दोनों ही दौर ऐसे हैं जिनमें तुलना की जाए तो हर तरह से बड़े फासले नजर आते हैं, एक वाजपेयी का दौर और दूसरा मोदी का मौजूदा दौर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी की जरूरत अब भाजपा में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कभी आरिफ बेग, सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला और सैयद शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं की खासी अहमियत हुई करती थी। बाद में ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में एमजे अकबर और जफर इस्लाम का नाम भी शामिल हो गया, लेकिन वाजपेयी काल के नकवी और शाहनवाज की भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में जरूरत खत्म हो गई लगती है। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में लाने का थोड़ा सा क्रेडिट जफर इस्लाम को भी मिलता है, काफी है। मिशन पूरा हो गया तो आगे भी वैसे ही ढोते रहने से क्या फायदा।

से रिटर्न गिफ्ट ही समझा जाएगा। बीते चुनावों को छोड़ भी दें तो उप्र चुनाव 2022 में मायावती की भूमिका पर हमेशा सवाल उठे और उन पर भाजपा की मददगार बनने तक का आरोप लगा और बाद में तो राहुल गांधी ने भी ये बात खुलेआम बोल दी थी। मायावती को अगर विपक्षी खेमे का उम्मीदवार बनाया जाता है तो उप्र की राजनीति भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। विपक्ष उप्र के दलित वोटर को समझा सकता है कि भाजपा ने इस्तेमाल तो किया लेकिन मायावती पर विश्वास नहीं किया। अब सवाल ये है कि मायावती को विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? ऐसे फायदे का आधार सिर्फ ये हो सकता है कि उप्र के दलित वोटर को कौन क्या समझा पाता है? अगर कांग्रेस मायावती के वोट बैंक को ये समझा सके तो हो सकता है कि कुछ दलित वोटर पार्टी की तरफ लौट आए।

अगर कांग्रेस मायावती से मिलने वाले फायदे में अखिलेश यादव को भी शेयर होल्डर बना ले तो मामला काफी आसान हो सकता है। फिर कांग्रेस को अखिलेश यादव को यकीन दिलाना होगा कि आने वाले चुनाव में वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सपोर्ट करेगी और मायावती से मिलने वाले फायदे को दोनों आपस में शेयर करेंगे। मायावती के नाम पर उप्र से बाहर भी पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन ये भी मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा ही हो सकता है। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मायावती भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को राजी होंगी भी?

मुलायम सिंह यादव- एक मीडिया रिपोर्ट में मुलायम सिंह यादव को भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। दलील तो किसी भी तरफ से दी जा सकती है। सवाल ये है कि वो व्यावहारिक पैमाने पर भी तो खरी उतरनी चाहिए। भला भाजपा किसी ऐसे नेता को क्यों राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी जो कारसेवकों पर गोली चलवाने में बार-बार गर्व जता चुका हो और जिसके लिए उप्र के मुख्यमंत्री चुनावों में अब्बाजान कहकर बुलाते रहे हों? रही बात विपक्ष की तो मुलायम सिंह यादव को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने से होने वाले फायदे की तो उप्र के अलावा मुश्किल से हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों में ऐसी संभावना जताई जा सकती है। अंग्रेजी के विरोधी होने की वजह से दक्षिण भारत में तो विपक्ष को मुश्किल भी हो सकती है और ये भी संभव है कि एमके स्टालिन या पी विजयन जैसे नेता राजी न हों। खुद भी मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के लोगों से 2019 में ही बोल दिया था कि जिता देना, आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। सेहत का दुरूस्त न रहना भी एक बड़ी बाधा हो सकती है क्योंकि अभी करहल में भी देखा गया कि चुनाव प्रचार के लिए गए तो अखिलेश यादव के लिए वोट मांगना ही भूल गए थे। जब याद दिलाया गया तो लोगों से अखिलेश यादव को वोट देने की अपील की थी।

नीतीश कुमार- नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जिनको 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी का ऑफर सबसे पहले मिल चुका है। जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ही ऐसा प्रस्ताव दिया था। समझा जाता है कि प्रशांत किशोर वो प्रस्ताव तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की तरफ से दिए थे। अब ये नहीं मालूम कि उस प्रस्ताव की की कोई वैलिडिटी बची हुई है भी या नहीं? वैसे नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू नेता ने न तो ऐसा कोई दावा किया है, न ही ऐसी कोई उनकी इच्छा है। ऐसा लगता है कि मौका देखकर ही नीतीश कुमार ने अपने मंत्री से ये बयान दिलवाया है। दरअसल, मंत्री ने उनके 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का भी दावा किया है। वैसे भी जिस चुनाव में जीत की बहुत ही कम संभावना हो, नीतीश कुमार भला उम्र के इस पड़ाव पर कैरियर का कबाड़ा जानबूझकर क्यों करेंगे? अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भाजपा दे तो फायदा ही फायदा है, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ होने से तो फजीहत ही है।

आरिफ मोहम्मद खान- केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को भी भाजपा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था, सभी जानते हैं और उसी तर्ज पर आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर चर्चा होने लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मौजूदा भाजपा नेतृत्व को ऐसी कोई जरूरत महसूस होती होगी? राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होते ही ट्विटर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम ट्रेंड करने लगा था। ऐसे ट्वीट और रीट्वीट करने वालों का ये मानना रहा होगा कि भाजपा नेतृत्व आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान के उम्मीदवार होने की सूरत में विपक्षी दलों की तरफ से कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा।

● **कुमार विनोद**

तैयार होंगे नए औद्योगिक क्लस्टर

मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में 7 और 8 जनवरी 2023 को इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट को सक्सेस करने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने इनवेस्टर्स को रिझाने के लिए समिट के पहले प्रदेश के कई क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना की गिरफ्त से निकलकर प्रदेश निवेश की राह पर बढ़ने की तैयारी में है। जनवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट से पहले निवेश का नया रोडमैप तैयार हो जाएगा। 10 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ से प्रारंभिक सहमति बन गई है तो कुछ जगह को लेकर मशक्कत में लगी हैं। आने वाले दिनों में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन उद्योग से लेकर टैक्सटाइल-वेयरहाउसिंग जैसे परंपरागत उद्योगों तक में नए क्लस्टर आकार लेंगे।

बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण विदेशी निवेश लगभग बंद हो गया था। ऐसे में बंदिशों के कारण मप्र विदेशी निवेश को लेकर खास काम नहीं कर रहा था। अब स्थिति बदलने से वापस विदेशी निवेश पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगस्त में विदेश दौरा कर सकते हैं। इस बीच विभागीय स्तर पर विदेशी कंपनियों से निवेश को लेकर बातचीत जारी है। इन दिनों प्रदेश में औद्योगिक विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। ग्रीन एनर्जी, आर्गेनिक खाद से लेकर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आकार ले रही है। भोपाल-राजगढ़ में 250 करोड़ से ग्रीन एनर्जी पार्क बनना है। इसमें 15 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट, ऑर्गेनिक खाद, 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का कार्बन-डाई-ऑक्साइड कैप्चर प्लांट और 10 मेगावाट क्षमता का केप्टिव सोलर पॉवर प्लांट बनेंगे। हाइड्रोजन व अमोनिया गैस भी बनेगी। वहीं भोपाल-इंदौर-जबलपुर-ग्वालियर-कटनी सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों में एयरपोर्ट व सड़क कनेक्टिविटी वाले बड़े लॉजिस्टिक पार्क लाने की तैयारी भी है। भोपाल-इंदौर कॉरिडोर में आष्टा के समीप बड़े क्षेत्र पर एआई व आईटी हब के लिए प्लान है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ से बनना है। बैरसिया-भोपाल में 25.88 करोड़, आष्टा-सीहोर में 99.43 करोड़, धार में 79.43 करोड़, रतलाम में 462 करोड़ और नरसिंहपुर में 47.82 करोड़ की परियोजना है। इनमें 32 हजार करोड़ का निवेश संभावित है। 38 हजार रोजगार मिलेंगे।

इनवेस्टर्स समिट में आने वाले निवेश के प्रस्तावों को देखते हुए देवास में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। यहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, कमर्शियल, रेसीडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। देवास, सोनकच्छ, आष्टा व सीहोर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना है। वहीं पुणे के पिनेकेल उद्योग समूह ने 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दे रखे हैं। यह समूह पीथमपुर में 2000 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट लगाना चाहता है। इससे 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें बस और छोटी लाइट कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन होगा। जेएसडब्ल्यू पेंट समूह ने 1500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट व फोर्स मोटर्स समूह ने भी निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। जेके टायर समूह ने मुरैना में प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। 750 करोड़ से प्लांट लगेगा। हाइड्राइज समूह एथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी में है। यह प्लांट सिवनी में लगना है। यह कंपनी लंदन की एथेना कैपिटल्स के साथ प्रदेश में बड़ा निवेश करेगी। इसी तरह एथेनॉल प्लांट के लिए तीन और कंपनियों से प्रारंभिक बातचीत हुई है। जल्द ही प्रस्ताव आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चिरीपाल समूह ने रतलाम में 250 एकड़ में 4600 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। समूह सोलर सेल, सोलर ग्लास, पीवी मॉड्यूल की इकाई लगाएगा। टैक्सटाइल यूनिट भी लगेगी। इसमें 800 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। इंटरनेशनल कम्फर्ट टेक्नोलॉजीज 180 करोड़ से मंडला के मनेरी में मेट्रेस, फोम किल्ट रोल्स और पिलो निर्माण की इकाई के विस्तार का प्रस्ताव दे चुका है। यह कंपनी देश की पॉलीयूरेथेन फोम निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी स्लीपवेल ब्रांड में सामग्री का निर्माण करती है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 के बीच 51 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 3 हजार से एमएसएमई इकाइयां कोरोनाकाल के बीच नई शुरू हुईं हैं। सिवनी में हाइड्राइज ग्रुप ऑफ कंपनीज एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। इसके लिए लंदन स्थित एथेना कैपिटल्स हाइड्राइज ग्रुप ऑफ कंपनीज में 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे किसानों को लाभ होगा और तेल आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण के कार्यक्रम को तेजी से ट्रैक किया जाएगा। इसके वर्ष 2023 में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

● राजेश बोरकर

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रोजगार की बहार

मप्र को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। भोपाल और इंदौर के बीच बहुत जल्द ही देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम को जगह दिखा दी गई है। यह जमीन सोनकच्छ, चापड़ा, हाटपिपल्या के बीच है। यहां 30 हजार एकड़ क्षेत्र में मेगा इंडस्ट्रियल रिजन भी तैयार किया जाएगा। इस जगह एयरपोर्ट बनने की वजह से कई युवाओं को रोजगार उपलब्ध होंगे। अभी तक यहां पर कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जिन्हें इस जगह रोजगार मिल जाएंगे। भोपाल और इंदौर के बीच बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने का काम मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की वजह से यहां कई शहरों से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। इसके साथ ही हाईस्पीड कनेक्टिविटी होगी और जिलों से सीधा संपर्क भी जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र को रेलवे से भी जोड़ने की योजना है। यहां एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जा सकता है।

पोषण आहार पर संकट...

मप्र को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर मिशन मोड में काम कर रही है। लेकिन यहां का सिस्टम ही इस कदर कुपोषित है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई अव्यवस्था का शिकार हो जाती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि बजट के अभाव में कई जिलों में पोषण आहार व्यवस्था पर ही संकट मंडराने लगा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का बिजली बिल जमा नहीं हुआ है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछले कुछ माह से आधे मानदेय में काम कर रही हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, बजट के अभाव में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी लगातार विभाग के ध्यान में ला रहे हैं कि आवंटन नहीं मिलने से पोषण आहार वितरण को लेकर गंभीर समस्या बन सकती है। वहीं सतना के कलेक्टर ने पत्र लिखकर संभावना जताई है कि जल्द आवंटन नहीं मिला तो स्वसहायता समूहों पर गंभीर आर्थिक संकट आ सकता है और ऐसे में पूरक पोषण आहार प्रदान व्यवस्था गड़बड़ा सकती है।

प्रदेश के कई जिलों में पिछले तीन महीने से बजट का आवंटन नहीं हुआ है। सतना के जिला अधिकारी ने सूचना दी थी कि मार्च के बाद से यह लगातार तीसरा महीना है, हमें न तो आवंटन मिला है और न ही एसएचजी के लिए कोई निर्देश हैं जो सांझा चूल्हा और अन्य के तहत पूरक पोषण प्रदान कर रहे हैं। स्वसहायता समूह के सदस्य अपनी शिकायत निवारण के लिए जनसुनवाई में आ रहे हैं। हमें उन्हें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। उधर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च से मानदेय नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीएफएमएस के नए प्रावधानों के तहत कुछ निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। लाड़ली योजना की फीडिंग करने वाले ऑपरेटरों का दो साल से बकाया नहीं मिला।

प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को ही पूरा मानदेय नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में 1,94,270 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को फरवरी 2022 के बाद से आधा मानदेय दिया जा रहा है। विभाग का तर्क है कि इनके 10 हजार रुपए के मानदेय में केंद्र और राज्य का हिस्सा रहता है। राज्य ने अपने हिस्से का अतिरिक्त मानदेय यानि 5,500 रुपए दे दिए हैं। केंद्र के हिस्से का 4,500 रुपए मानदेय रुका है। वहीं वित्त विभाग ने करीब 80 करोड़ रुपए बिजली कनेक्शन और बकाया बिल के मंजूर किए हैं। बजट नहीं मिलने से आंगनबाड़ी केंद्रों की बिजली कटने लगी है। शहडोल जिले में ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं।

सतना कलेक्टर ने जो पत्र लिखा था उसमें चेतावनी दी गई थी कि एक जून को संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को लिखा-वित्तीय वर्ष 2022-23 के 2 माह समाप्त हो चुके हैं किंतु वेतन मद को छोड़कर शेष किसी भी मदों में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इससे विभाग की प्रमुख योजना पूरक पोषण आहार, आईसीडीएस, वाहन, कम्प्यूटर मरम्मत, फलैक्सी मद आदि में भुगतान की स्थिति लंबित है। बजट अप्राप्त रहने से आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाले स्व सहायता समूहों का माह मार्च 2022 से भुगतान लंबित है। समूहों के देयकों का तीन माह से भुगतान ना होने पर समूह की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका प्रबल है जिससे पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य प्रभावित हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की सागर संभाग की अध्यक्ष लीला शर्मा कहती हैं कि फरवरी का मानदेय नहीं मिला। मार्च का अतिरिक्त मानदेय आया है। इसमें भी भेदभाव हो रहा है।

उधर इंफेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में मप्र की स्थिति बिहार, उप्र और छत्तीसगढ़ से भी बदतर है। बीती 25 मई को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मप्र में जन्म लेने वाले एक हजार बच्चों में से 43 बच्चों की मौत, जन्म के 28 दिन से एक साल के भीतर हो जाती है। रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंफेंट (28 दिन से एक साल तक के बच्चे) मोर्टेलिटी रेट के मामले में मप्र की हालत, उप्र, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी खराब है। उप्र और छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 38, असम और ओडिशा में 36 और राजस्थान में 32 है। देश में सबसे बेहतर स्थिति मिजोरम की है। यहां एक हजार जन्म में से सिर्फ तीन नवजातों की मौत होती है। सिक्किम-गोवा में 5, नगालैंड में 4 और मिजोरम में शिशु मृत्यु दर 3 है। मप्र में एनएचएम की प्रमुख प्रियंका दास कहती हैं, हर लेवल पर शिशु मृत्यु के हर केस का ऑडिट कर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इनमें सिजेरियन डिलीवरी भी बड़ा कारण है। इसे लेकर जिला अस्पताल को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण कुछ चुनौतियां हैं। सभी जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रसव कराने के साथ ही मां और बच्चे की विशेष देखभाल की जाए, ताकि बच्चों और माताओं की मौतों को रोका जा सके।

● **अरविंद नारद**

भोपाल में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत

उधर प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मप्र में नवजातों की मौत चिंता का विषय बनी हुई है। आलम यह है कि प्रदेश में 1000 में से 43 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में सबसे अधिक भोपाल में बच्चों की मौत हो रही है। भोपाल में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 1004 बच्चों की मौत हुई है। ग्वालियर में 693, जबलपुर में 666 और इंदौर में 556 बच्चों की मौत हो रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में मप्र में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। हर 1000 में 43 नवजातों की मौत हो जाती है। किलकारी खामोशी होती जा रही हैं। कारण छुपाए जा रहे हैं, जबकि बीमारियों के अलावा ऐसी लापरवाही भी मौत की बड़ी वजह है। एनएचएम की एमडी प्रियंका दास द्वारा की गई चाइल्ड डेथ समीक्षा में सामने आया कि 2021-22 में 29,533 बच्चों की मौत के कारण दर्ज करने में बड़ी चूक की गई है। शिशु मृत्यु के 13,953 मामलों में मौत की वजह में 'अन्य' दर्ज किया गया है, जबकि 11,727 बच्चों की मौत का कारण 'घर पर देरी' लिखा है। इन सभी मामलों में मौत की सही वजह पता कर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

खेतों में छिड़का जा रहा जहर

कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग की प्रवृत्ति ने कृषि भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसे कई जहरीले कीटनाशकों को सरकारें समय-समय पर प्रतिबंधित भी करती आई हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक कर उन्हें जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पैदावार में घुलते जहर की प्रक्रिया पर लगाम लगाई जाए। आमतौर पर किसान कीटों से फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके दूरगामी दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें भान नहीं होता। कीटनाशक के छिड़काव के वक्त इनके अंश सांसों के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनकी मौत का कारण तक बन जाते हैं। उन्हीं उत्पादित खाद्य पदार्थों का सेवन हमारे शरीर को विषाक्त और अस्वस्थ बनाता है। कीटनाशकों के जहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से हर साल 30 लाख लोग बीमार होते हैं, जिनमें से ढाई लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

प्रदेश में एक तरफ सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान अच्छी फसल के लिए कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर मूंग की फसल पर इस कदर कीटनाशकों को इस्तेमान किया जा रहा है कि उससे मूंग दाल जहरीली होती जा रही है। प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग में सबसे अधिक मूंग की खेती होती है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक कीटनाशकों को **इस्तेमाल** हो रहा है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मूंग की जितनी भी खेती होती है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा नर्मदापुरम संभाग में उग रहा है, लेकिन यहां के किसान पूरी फसल को 2 महीने में पकाने के लिए चार बार और 12 घंटे में सुखाने के लिए एक बार कीटनाशक छिड़क रहे हैं। इससे फसल का दाना तो हरा बना रहता है, लेकिन वो हार्वेस्टर से आसानी से कट जाती है। अभी प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़ 35 लाख क्विंटल मूंग पैदा करने के लिए किसान यही तकनीक अपना रहे हैं। इससे जो मूंग दाल सबसे पौष्टिक मानी जाती है, वो अब जहरीली होती जा रही है।

किसान जिस तरह मूंग की खेती कर रहे हैं इससे न केवल सरकार परेशान है, बल्कि कृषि वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जहरीली फसल जमीन को 10 साल में बंजर बना देगी। बड़ी बात है कि कृषि मंत्री कमल पटेल भी किसानों से इस जहर की खेती को बंद करने की बात कर रहे हैं, लोगों को ऐसे जहर की खेती न करने का संकल्प दिला रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे। जबकि किसान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो मूंग उगा रहे हैं- वे भी इसे नहीं खाते। बीलाखेड़ी के किसान प्रफुल्लदास महंत कहते हैं कि 25 एकड़ में मूंग लगी है। एक एकड़ में 7 क्विंटल मूंग चाहिए तो दवाई तो डालना पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जुझारपुर के किसान विजयबाबू चौधरी का कहना है कि हम ये मूंग नहीं खाते। गुनौरा के यज्ञदत्त गौर, जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष नवल पटेल कहते हैं कि इस मूंग को कैसे खा सकते हैं। ये जहरीली है। किसान मूंग की बोवनी देरी से करते हैं और जल्दी फसल उगाने के लिए बार-बार कीटनाशक डालते हैं। जैविक खेती में मूंग की फसल 2 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन आधी फसल इल्लियां खा जाती हैं या फिर झड़ जाती हैं। कीटनाशक डालने से पैदावार 95 प्रतिशत तक हो जाती है। किसानों द्वारा क्लोरिन ट्रानिलिन प्रोल और थायो मैथाक्सम कीटनाशक हर 10 दिन में फसल पर छिड़का जाता है। इसमें पहली दवा इल्ली मार और दूसरी मच्छर-मक्खी मारती है। दोनों का घोल छिड़कते हैं। पैराक्यूट 2 बार डालते हैं। एक बार बोनी के 20 दिन बाद और दूसरी बार फसल सुखाने में।

किसान जिस तरह मूंग की जहरीली खेती कर रहे हैं उससे कृषि मंत्री के साथ ही कृषि विशेषज्ञ भी हैरान हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी तो किसानों ने ज्यादा कीटनाशक डाला। मैं तो किसानों को संकल्प दिला रहा हूं कि ये जहरीली खेती न करें। अभी नहीं रुके तो पंजाब जैसे हालात होंगे। कोरोनाकाल जैसी कैंसर रोगियों की भरमार होगी। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और होशंगाबाद विधायक सीतासरन शर्मा का कहना है कि ये फसल नहीं जहर है। मैं तो हर सभा में किसानों को समझा रहा हूं कि कीटनाशक की ऐसी खेती हमारी नस्लें खराब कर देगी, लेकिन किसान है कि मान ही नहीं रहे हैं। सरकार ही कोई ठोस कदम उठाए। नर्मदापुरम के कृषि सहायक संचालक सुनील कुमार धोटे के मुताबिक जमीन के जैविक तत्व जल रहे हैं। यहां के 100 प्रतिशत किसान जहरीली मूंग उगा रहे हैं। 10 साल में ये क्षेत्र पंजाब बन जाएगा। हर घर में कैंसर रोगी होगा। नर्मदापुरम में कृषि उपसंचालक जेआर हेडाऊ कहते हैं कि वैकल्पिक फसल का रास्ता कुछ कमाई और जमीन उपजाऊ रखने के लिए था, लेकिन किसानों ने जो तरीका अपनाया, वो घातक है।

● **बृजेश साहू**

18 जहरीले कीटनाशक प्रतिबंधित

गौरतलब है कि खेतों में प्रयोग किए जाने वाले बेनोमाइल, कार्बाइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, ट्राईफ्लूरलिन और अलाक्लोर समेत 18 जहरीले कीटनाशकों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। उससे पहले ये खेतों में बहुतायत में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जब परीक्षण किया गया तो इनमें विद्यमान जहर की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई। इसलिए उन पर नियंत्रण आवश्यक हो गया है। ऐसे कीटनाशकों के इस्तेमाल से कैंसर, किडनी एवं लिवर खराब होने, हार्टअटैक सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बेनोमाइल नामक कीटनाशक लिवर को विषाक्त बनाता है और मानव की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। इसी तरह कार्बाइल, डायजिनोन, फेनारिमोल जैसे कीटनाशक जलीय जीवों और मधुमक्खियों के लिए घातक होते हैं। अच्छी बात है कि भारत सरकार 27 अन्य जहरीले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। समस्या को देखते हुए यह आवश्यक भी हो गया है। जहरीले कीटनाशक का इस्तेमाल स्वयं किसानों और उपभोक्ताओं के साथ-साथ मृदा, जलस्नेतों और वायुमंडल के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इससे खेतों में आने वाले जानवरों तथा फसलों पर बैठने वाले कीट-पतंगों और पक्षियों के शरीर में भी जहर की मात्रा बढ़ती जाती है।

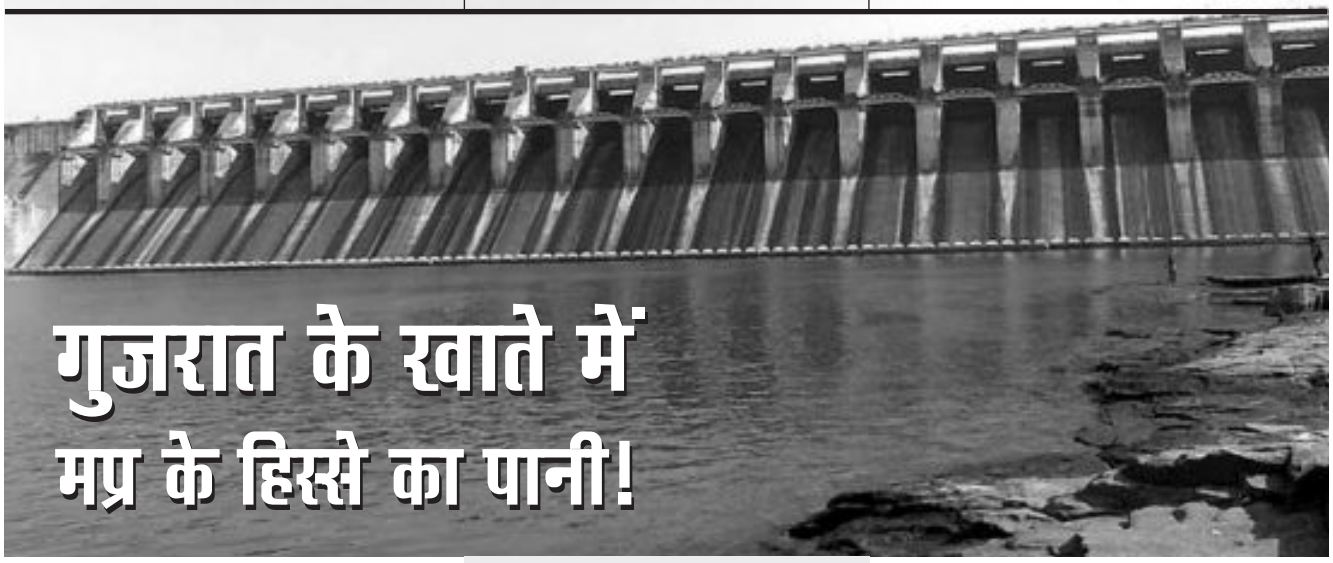

गुजरात के खाते में मप्र के हिस्से का पानी!

बरगी दांयी तट व्यपवर्तन योजना के तहत टनल निर्माण में हो रही लेटलतीफी के कारण विंध्य और नर्मदा के मिलन में संशय है। यहां के हिस्से का पानी 15 साल से कटनी के स्लीमनाबाद टनल में अटका हुआ है। स्थिति यह है कि यदि 2024 तक मप्र अपने हिस्से का 18.25 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) पानी संचित नहीं कर पाया तो यह गुजरात के हिस्से में चला जाएगा और महाकौशल व विंध्य के करीब 1450 गांव लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे।

दरअसल, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की धारा 6 के अंतर्गत नर्मदा नदी के जल निर्धारण के लिए नर्मदा ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार मप्र को 18.25 एमएएफ, गुजरात को 9 एमएएफ, राजस्थान को 0.50 और महाराष्ट्र को 0.25 एमएएफ पानी दिया गया है। आदेश में स्पष्ट है कि 12 दिसंबर 1979 से 45 वर्ष अर्थात् 31 दिसंबर 2024 तक यह पानी यदि मप्र उपयोग नहीं कर पाता है तो उसके हिस्से का जल दूसरे राज्य को दे दिया जाएगा। अब समय करीब आता देख सरकार ने टनल निर्माण के काम में दिलचस्पी जरूर दिखाई है, लेकिन बाधाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

बरगी नहर का अब तक 60 फीसदी से ज्यादा काम हो चुका है। अब इसकी राह में स्लीमनाबाद टनल बाधा है। यहां 12 किमी लंबी सुरंग बननी है, लेकिन 2011 से 2018 तक महज 4.6 किमी की खुदाई ही हो सकी थी। इसके बाद काम सुरंग में अटक कर रह गया था। प्रदेश का पानी गुजरात के हिस्से में जाता **देख सरकार** ने इसमें फिर दिलचस्पी दिखाई। विगत तीन-चार साल से जापान से आई महामशीन से सुरंग खुदाई का कार्य चल रहा है। हालांकि यहां लगी दो मशीनों में एक अक्सर बंद रहती है। ऐसे में अभी भी 2023 तक टनल का काम पूरा होना किसी चुनौती से कम नहीं है।

नर्मदा जल विंध्य तक पहुंचाने के लिए स्लीमनाबाद से सतना तक मुख्य नहर का निर्माण कार्य 10 साल पहले पूर्ण कर लिया गया था। ये नहरें अब जर्जर हो चुकी हैं। बिना मरम्मत के इनमें पानी छोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में मुख्य नहर का मेंटेनेंस भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उधर, सतना से रीवा पानी पहुंचाने के लिए बन रही मुख्य नहर का काम निर्माणाधीन है। सहायक नहर निर्माण के लिए सतना जिले के मैहर, उचेहरा एवं नागौद तहसील के 201 गांवों की भूमि अधिग्रहीत की गई। इसमें से करीब 141 गांवों के भूस्वामियों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं नागौद-सतना शाखा आरडी 00 से 83 किमी तक 1452.722 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जानी है। इसमें से महज 420.366 हैक्टेयर का ही अर्जन हो सका है। 1032.06 हैक्टेयर का अधिग्रहण करना शेष है। जानकारों की मानें तो जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में समय लगेगा। ऐसे में नहर समय सीमा में बन पाएगी, यह बड़ा सवाल है।

प्रदेश के हिस्से का पानी बचाने का एक ही रास्ता है। मंडला जिले में रोशरा एवं बसानिया तथा डिंडौरी जिले में राघवपुर डैम बरगी अपस्ट्रीम में बनने हैं। राघवपुर जल विद्युत परियोजना के लिए 225 मिली घन मीटर, रोशरा के लिए 432 और बसानिया के लिए 175 मिली घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। तीनों में करीब 832 मिघमी पानी उपलब्ध होगा। इन तीनों डैम के निर्माण का कार्य अभी तक नहीं हुआ। यदि शासन-प्रशासन गंभीरता से ले और निर्माण जल्द पूरा करा ले तो प्रदेश के हिस्से का पानी संचित हो सकता है। विंध्य में नर्मदा जल लाने के लिए बरगी नहर का निर्माण 2009 से चल रहा है। इस परियोजना से जबलपुर के 438 ग्राम, कटनी के 127, सतना के 855 और रीवा जिले के 30 गांव को पानी मिल सकेगा। यदि तय समय पर पानी पहुंच जाता है तो विंध्य क्षेत्र की 2.45 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी तथा खेती की पैदावार बढ़ेगी।

बरगी नहर में अंडर ग्राउंड टनल का निर्माण कार्य 25 जुलाई 2011 में पूरा होना था। लेकिन, लेटलतीफी के कारण काम नहीं हो पाया और लगातार एक्सटेंशन मिलता गया। चार एक्सटेंशन के बाद 31 मार्च 2021 तक काम पूरा करना था। अब एक और एक्सटेंशन देकर यह अवधि 2023 कर दी गई है। ईई नवदा कटनी सहज श्रीवास्तव का कहना है कि टनल खुदाई का काम चल रहा है। वर्तमान में एक मशीन बंद होने से हर माह लगभग 150 मीटर खुदाई हो पा रही है। 10-15 दिन में दोनों मशीनें काम करेंगी तो तय लक्ष्य अनुसार 300 मीटर हर माह खुदाई होगी। जून 2023 तक टनल का काम पूरा कर दिया जाएगा।

● श्याम सिंह सिकरवार

18 माह में खोदनी है 3500 मीटर सुरंग

बरगी के पानी का भविष्य तय करने वाली स्लीमनाबाद टनल का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अन्नदाता सरकारी उधेड़बुन में फंस कर रह गया है। प्रदेश सरकार ने टनल का काम पूरा करने के लिए जून 2023 की डेटलाइन तय की है। दो महामशीनों से प्रतिमाह 270 मीटर टनल खोदने का लक्ष्य रखा है। 10 मई तक 8.5 किमी सुरंग बन चुकी है। आगे 12 माह में 3510 मीटर टनल खोदने का कार्य किया जाना है। जबकि, हकीकत यह है कि दो में से एक मशीन बंद रहती है। इस कारण लक्ष्य की आधी ही खुदाई हो रही है। ऐसे में दावों के अनुसार जून 2023 तक सुरंग निर्माण का कार्य पूरा होने उम्मीद नहीं है। जानकारों की मानें तो इसी रफ्तार से काम चला तो यह काम 2025 तक चलेगा। ऐसे में यदि सरकार को 2024 से पहले नर्मदा का पानी सतना लाना है तो बचे हुए दिनों में प्रति दिन 10 मीटर टनल खोदनी होगी।

वीरान पहाड़ियों पर बसाया जंगल

कुल्हाड़ियों की आवाज खामोश हो गई हैं और वहां किसी भी जानवर को चरने की इजाजत नहीं है। इसलिए अब पन्ना जिले के पटना तमोली गांव की पहाड़ी ने मुरझाने, झुलसने, और उजड़ने के बावजूद सांस लेना शुरू कर दिया है। पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव 142 हेक्टेयर वीरान पहाड़ी को हरा-भरा करने की पहल के लिए चर्चा में है, जो 15 वर्षों में एक जंगल बन गया है। पटना तमोली के एक सेवानिवृत्त शिक्षक सेतुबंधु चौरसिया ने बताया, वर्तमान में यहां ऐसे पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 20 से 30 फीट के बीच है। यहां पर नीम के पेड़ और रात की चमेली सहित कुछ पेड़ प्राकृतिक रूप से उगे हैं, वहीं सागौन के पौधे लगाए गए हैं, उन्होंने उजड़ी हुई पहाड़ी ढलानों पर जंगलों को फिर से उगाने के लिए गांवों को एक साथ लाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव 142 हेक्टेयर वीरान पहाड़ी को हरा-भरा करने की पहल के लिए चर्चा में है, जो 15 वर्षों में एक जंगल बन गया है। चौरसिया सेतुबंधु ने बताया, पेड़ों के सिर्फ मरे हुए कुछ ठूंठ रह गए थे और जंगली झाड़ियों की जड़ों को भी नहीं बख्शा गया था। जलाओ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ उखाड़ दिया गया था। 70 वर्षीय ने बताया, चूंकि पहाड़ी पर कोई वनस्पति नहीं थी, हर बार बरसात के मौसम में पानी मिट्टी को धो देता था। इस वजह से लगभग 5 हजार की आबादी वाले इस गांव के भूजल स्तर में गिरावट भी आई। परिवर्तन की बयार सेतुबंधु चौरसिया की हमेशा से ही पर्यावरण में दिलचस्पी थी और उन्होंने स्थानीय लोगों की एक टीम बनाई, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण टीम के तौर पर काम किया।

सेतुबंधु ने याद करते हुए बताया, जहां भी हमें जगह मिली, हमने पौधे लगाना शुरू कर दिया और 2004 में हमारा ध्यान पटना तमोली गांव की तरफ आकर्षित हुआ। वीरान पहाड़ी, जहां घास का एक तिनका भी नहीं था, वहां हरियाली लाने के लिए मदद की सख्त जरूरत थी। सेवानिवृत स्कूल शिक्षक ने बताया, हमने वहां काम करने का फैसला किया और गांव के लोगों से संपर्क किया। हालांकि, उस समय उन्हें इस क्षेत्र को हरा-भरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन, पहाड़ियों को हरा-भरा करने का विचार गांव के कुछ युवाओं को भा गया। सेतुबंधु ने बताया, अजय चौरसिया उनमें से एक थे और इलाके के युवा एक साथ इकट्ठा हुए और विचार जोर पकड़ने लगा। सिर्फ पटना तमोली ही नहीं, आसपास के गांवों ने भी दिलचस्पी दिखाई और धीरे-धीरे लोगों ने पहाड़ी की हरियाली को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया और वहां अपने मवेशियों को भी ले जाना बंद कर दिया। कुछ वर्षों के अंतराल में, मानव गतिविधि से विचलित न होकर, ढलानों पर हरे रंग की परत उगने लगी और पेड़ फिर से दिखाई देने लगे।

हरियाली आंदोलन का हिस्सा बने युवाओं में से एक प्रमोद वर्मा याद करके बताते हैं, 2005 में पहाड़ी पर हरे नाम का कोई निशान नहीं था। वर्मा ने बताया, सेतुबंधु के अभियान और उनके प्रोत्साहन की वजह से स्वयं सहित गांव के युवकों, अजय चौरसिया, ओम सोनी, वृंदावन चौरसिया, कृष्ण कुमार पांडा और हरिनारायण ने एक टीम बनाई और काम पर लग गए। वर्मा ने को बताया, शुरूआत में हमने पहाड़ी की किसी भी तरह की वनस्पति को छेड़ा नहीं और जल्द ही गिरे हुए पेड़ों से अंकुर निकलने लगे। सिर्फ तीन से चार वर्षों में, हरे रंग की चादर ने ढलानों को ढक दिया, और अब हमारे सामने एक जंगल खड़ा है। नतीजतन, पिछले पंद्रह सालों में, पटना तमोली में 142 हेक्टेयर में फैली एक बार खराब हो चुकी पहाड़ी, अब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। पटना तमोली, एक ग्रीन तीर्थ स्थल आज न सिर्फ आसपास के गांवों और कस्बों के लोग, बल्कि वन अधिकारी भी पटना तमोली के लोगों के किए गए कार्यों की सराहना करते हैं।

20 साल पहले पटना तमोली एक घटना के कारण चर्चा में आया था। इस गांव में अगस्त 2002 में 65 वर्षीय महिला कट्टू बाई को उनके पति की चिता पर जिंदा जला दिया गया था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो साल के लिए सरकारी सहायता देने से इंकार कर दिया। सती होने की घटना गांव पर कलंक थी। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की पहल ने कुछ हद तक इस कलंक को धोया है। इसने न सिर्फ गांव वालों की सूरत बदली है, बल्कि अब पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए गांव की मिसाल दी जाने लगी है। हरित प्रयास में अहम **योगदान** देने वाले अजय चौरसिया ने दुख जताया कि कैसे विकास के नाम पर हर अवसर पर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। अफसोस जताते हुए उसने बताया, इतने सारे रूल और रेगुलेशन के बावजूद, गैरकानूनी खनन, पेड़ों की कटाई और भूजल का दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

खत्म हो रहा नदियों का अस्तित्व

जगह-जगह बोरवेल करने से नदियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है और न केवल पेड़, बल्कि पूरे जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया, जबकि लोग सूखे और बाढ़ के रूप में परिणामों का सामना कर रहे हैं, वे अभी भी इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रकृति की चेतावनी हैं। उन्होंने कहा, हम संकेतों की अनदेखी कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि पटना तमोली के लोग समय पर जागे, संकेतों को पढ़ा और सुधारात्मक उपाय करने का फैसला किया। सेतुबंधु ने काफी गर्व के साथ कहा, यह केवल हरी-भरी पहाड़ियां नहीं हैं जो हमारे लिए उत्सव का कारण हैं। नया जंगल पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है और कई प्रवासी प्रजातियां भी अब हमारे पास आती हैं।

केन बेतवा लिंक से वन्य जीवों को खतरा

परियोजना में विस्थापित होंगे 21 गांव

केन-बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा क्षेत्र डूब जाएगा। ऐसे में पार्क के वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इनमें पन्ना जिले के 7 और छतरपुर के 14 गांव हैं। छतरपुर एवं पन्ना कलेक्टर ने संबंधित गांवों में संपत्ति का सर्वे शुरू करा दिया है। अगले 6 से 8 महीने में सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है। उधर, दोनों नदियों पर बनने वाले ढोढन बांध को लेकर तमाम तरह के निर्णय लेने का अधिकार रखने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी का कार्यालय भी जून में ही भोपाल में खुल जाएगा। विश्वेश्वरैया भवन में अथॉरिटी को जगह दी गई है। इसके बाद छतरपुर जिले में भी कार्यालय खोला जाएगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से वन्य जीवों को होने वाले नुकसान पर भारतीय वन्य जीव संस्थान ने गहरी चिंता जताई है। इसे देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने उप्र के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य और मप्र के दुर्गावती व नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के मध्य एक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। इसकी मदद से तीनों अभ्यारण्य में जीवों के अनुकूलता के अनुरूप एक माहौल मिल सकेगा। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के साथ जीवों के संरक्षण के लिहाज से विस्तृत कार्य योजना तैयार है। इससे रानीपुर में बाघों के संरक्षण के साथ गिद्ध और घड़ियाल जैसे अन्य कई प्रजातियों के जीवों का भी संरक्षण आसानी से होगा। जीवों के संरक्षण के लिए दोनों नदियों और उनके आसपास के पूरे इलाके का व्यापक अध्ययन और विश्लेषण किया गया है।

मंत्रालय ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना फाइनल कर दी है। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) देहरादून के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इस परियोजना की वजह से तीनों अभ्यारण्य के जीव सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में वन्य जीवों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 50 फीसदी हिस्सा पानी में डूब जाएगा। ऐसे में टाइगर रिजर्व के दोनों नदियों केन और बेतवा पर बनने वाले ढोढन बांध में अब सबसे बड़ी अड़चन पन्ना टाइगर रिजर्व ही है। पहले यहां से वन्यजीवों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है।

बाघों को बचाने के लिए नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, उप्र के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य के बीच कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वहीं, बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी प्रमुख जातियों के संरक्षण और उन्हें आवास के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन देने के लिए भी इस एकीकृत प्लान में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 50 फीसदी हिस्सा पानी में डूब जाएगा। ऐसे में टाइगर रिजर्व के दोनों नदियों केन और बेतवा पर बनने वाले ढोढन बांध में अब सबसे बड़ी अड़चन पन्ना टाइगर रिजर्व ही है। पहले यहां से वन्यजीवों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र और उप्र-मप्र की सरकारें जहां बुंदेलखंड के लिए क्रांतिकारी और बेहद लाभदायक बता रही हैं तो दूसरी तरफ परियोजना से प्रभावित हो रहे गांवों के ग्रामीण, कई पर्यावरण पैरोकार और स्वयंसेवी संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी असहमति जताते हुए कहा कि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व तबाह हो जाएगा। विरोध करने वालों की दलीलें हैं कि सबसे बड़ा नुकसान बुंदेलखंड के एकलौते अभ्यारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क को होगा। इसका बड़ा इलाका पानी में डूब जाएगा। बड़े पैमाने में जंगलों का सफाया होगा। केन नदी का अस्तित्व खतरे में आ जाने की दलीलें भी दी जा रही हैं। केन-बेतवा लिंक में प्रस्तावित ढोढन बांध के नजदीक दो पावर हाउस (बिजली घर) बनेंगे। इनकी क्षमता क्रमश: 60 एवं 18 मेगावाट होगी। दूसरे चरण में बीना कांप्लेक्स में भी 20 मेगावाट और 5 मेगावाट के दो पावर प्रस्तावित हैं। ढोढन बांध में कोई सोलर प्लांट नहीं बनेगा। अलबत्ता दूसरे फेज में लोअरर परियोजना में 19 मेगावाट और कोथा बैराज में 8 मेगावाट के सोलर प्लांट बनेंगे।

उधर केन-बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण कार्य 8 साल में पूरा होगा। निर्माण कार्य की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। परियोजना के प्रीकंस्ट्रक्शन और इनवेस्ट सर्वे के लिए 243 दिन का समय तय किया गया है। वहीं 730 में जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पहुंच मार्ग के लिए 487 दिन, प्रोजेक्ट रोड के लिए 488 दिन, ऑफिस व कर्मचारी निवासी के लिए 518 दिन और निर्माण के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए 549 दिन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विस्तृत डिजाइन व ड्राइंग के लिए 730 और टेंडर प्रक्रिया के लिए 640 दिन का समय तय किया गया है। यानी 2 साल बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

टेंडर की प्रक्रिया के बाद डाइवर्सन नहर की खुदाई का काम शुरू होगा। जिसके लिए 182 दिन का समय तय किया गया है। वहीं कांक्रीट व कॉफर डैम निर्माण के लिए भी 182 दिन का समय लगेगा। इसके बाद परियोजना के मुख्य बांध ढोढन का अर्थवर्क शुरू होगा। बांध के फाउंडेशन कार्य में ही 1917 दिन यानि 5 साल का समय लगेगा। वहीं बांध का कांक्रीट वाला हिस्सा निर्माण करने के लिए 2098 दिन यानि इसमें भी 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा। सबसे अंत में पावर हाउस का कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जिसके निर्माण में 912 दिन का समय लगेगा। इस तरह से मुख्य बांध का संपूर्ण निर्माण कार्य 8 साल में पूरा होगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

घातक हो रही धार्मिक कट्टरता

गंगा-जमुनी तहजीब वाले भारत में धार्मिक कट्टरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस कारण देश में आए दिन धरना-प्रदर्शन, आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में ज्ञानवापी मामले में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से शुरू हुई बहस जो पैगंबर मोहम्मद साहेब तक पहुंच गई, उसे देखकर लग रहा कि धार्मिक कट्टरता विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए घातक होती जा रही है।

● राजेंद्र आगाल

धर्म और संप्रदाय की आड़ में देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक तनाव की बेलगाम घटनाओं के कारण भारत इन दिनों जितना बदनाम हो रहा है, शायद ही पहले कभी हुआ होगा। दुनिया के तकरीबन हर इस्लामी देश ने भारत में हो रहे सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जताई है। इसकी वजह है देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर भारत में इस कदर बवाल मचा कि पहले कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर, रांची, पश्चिम बंगाल, छिंदवाड़ा में ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आईं जो भारत की एकता-अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इन घटनाओं के पीछे आतंकी और विदेशी ताकतें हैं या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन अपनों के बीच जिस तरह खूनी खेल खेला जा रहा है, यह भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। हैरानी की बात यह है कि घोषणाओं के बावजूद शासन-प्रशासन सांप्रदायिक घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। इससे वातावरण दूषित हो रहा है।

पिछले 8 साल में भारत विश्व में एक बड़ा शक्ति केंद्र बनकर उभरा है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जो देश की गंगा-जमुनी संस्कृति के खिलाफ हैं। पिछले एक माह से तो सांप्रदायिक घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, जो चिंता का कारण हैं। ये घटनाएं एक ऐसे समय में सामने आ रही हैं, जब हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग इतिहास की गलतियों को सुधारने के लिए अदालतों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी पहल आगे बढ़ा रहा है। इसका आरंभ वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से लगी मस्जिद के मामले में फिर से सतह पर आने से हुआ। हिंदू समाज इस्लामिक शासकों द्वारा अतीत में किए गए कदाचार को दुरुस्त करने के प्रयास में लगा है। हिंदू संगठन उन तमाम उपासना स्थलों पर दावे कर रहे हैं, जिन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। इन दावों को लेकर मीडिया में भी हंगामा हुआ। खासतौर से टीवी चैनलों पर अनर्गल बयानों का सिलसिला चल निकला। चैनलों पर चल रही इस जुबानी जंग को देख यही अंदाजा लगेगा कि देश में कानून का शासन तार-तार हो गया है। टीवी चैनलों पर चलने वाली इन बहसों में न केवल मर्यादा की बलि चढ़ गई, बल्कि सड़कों पर हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी तक हुई। इस सबके बीच **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ** के प्रमुख मोहन भागवत ने सही समय पर समाज को चेताने का काम किया।

सत्ता और विपक्ष पंगु

देश में जिस तरह सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, ऐसे समय में न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है। आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे तमाम चंगू-मंगू नेता और मौलाना कुछ हफ्तों से अनजान आसमानी ताकत के वश में नजर आ रहे हैं। सत्तालोलुप विपक्ष की पीठ भी लगभग 45 डिग्री झुकी देखी जा सकती है। लेकिन जनता की चुनी सरकार को भी लकवा मार जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। हर जगह सरकार के बारे में उनके अपने लोग यही कह रहे हैं। उस सरकार को जिसे इस देश की करोड़ों जनता ने भारी भरकम बहुमत देकर लगातार जितवाया है। क्या हर शुक्रवार और उसके बाद शनिवार-रविवार का दिन दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे सूरमा चुने गए थे? अगर आप भी मुंह छिपा रहे तो भला शरद पवार और अखिलेश यादव से न्याय की उम्मीद क्या ही की जाए? एक कश्मीर पर्याप्त था, राजनीति ने दर्जनों बना दिए। हर शुक्रवार एक नया कश्मीर और वही पैटर्न। नमाज और फिर पत्थरबाजी या धार्मिक नारों वाले जुलूस। किसी जुलूस में तिरंगा लहरा देने भर से वह संविधान और कानूनी दायरे में नहीं आ जाता।

देश की जनता कह रही है कि गली मोहल्ले के छुट्टा लखैरे, पत्थरबाज देश की सड़कों पर अराजकता का **नंगा नाच** करते घूम रहे हैं। हर तरफ आम शहरियों को डराया और धमकाया जा रहा है। हर पल देश के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक-दो दिन तो झेला जा सकता है, मगर 24 घंटे और 30 दिन की नंगई, जिद और फर्जी गुरूर का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होता। एक कश्मीर में यह सब देखने को मिलता था, अब तो समूचे देश में ही घाटी के अंतहीन सिलसिले नजर आ रहे हैं। बिना नागा। हर शुक्रवार। सत्तालोलुप विपक्ष और सरकारों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? विपक्ष को अगर कुर्सी चाहिए तो वह सीधे कहे कि हमें कुर्सी दे दो भाई। शांति मिल जाएगी। शांति की कीमत सिर्फ कुर्सी है तो ले लो ना यार। सरकार को लग रहा हो कि उसके हाथ किसी चीज से बंधे हैं- तो वह भी मुंह खोले। आजाद भारत की महिलाओं ने अपने गहने बेंचकर सेनाओं को युद्ध लड़वाया है। आजादी की इतनी कीमत देश हंसी-हंसी चुकाने को तैयार हो जाएगा। कुछ कहिए तो? देश जानता है दुनियाभर में इस वक्त किस तरह का दबाव है।

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सद्भाव के लिए समरसता जरूरी

भाजपा के प्रवक्ताओं की बेलगाम बयानबाजी के चलते इस्लामिक देशों से जो तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है वह स्वाभाविक है। निश्चय ही यह देश की प्रतिष्ठा को आंच आने वाली स्थिति है जो भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़ा करती है। निश्चित रूप से जिस उग्र दक्षिणपंथी राजनीति का सुख अब तक भाजपा ले रही थी, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा प्रवक्ता द्वारा अल्पसंख्यकों के आराध्य को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी अकेला मामला हो। तमाम दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा सांप्रदायिक रुझान की टिप्पणियां गाहे-बगाहे सामने आती रही हैं। दूसरे हालिया बयानबाजी के बाद डैमेज कंट्रोल की कवायद भाजपा की तरफ से देर से की गई, जिसकी कीमत देश की प्रतिष्ठा पर आई आंच के रूप में चुकानी पड़ रही है। अरब देशों समेत पाक-ईरान आदि देशों की तल्ख प्रतिक्रिया को इस रूप में देखा जा सकता है। भाजपा ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई तब की जब भारत से कारोबारी रिश्ते रखने वाले अरब राष्ट्रों ने तल्ख रवैया दिखाया। जाहिरा तौर पर दुनिया में यह संकेत गया कि देश के राजनीतिक विमर्श में बड़ी गिरावट उत्पन्न हुई है। कई देशों का राजनयिक विरोध इसकी बानगी भर है। कई खाड़ी देशों में भारतीय सामान के बहिष्कार की चेतावनी के अलावा उन भारतीयों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो वहां काम करते हैं। हाल के दिनों में टीवी पर होने वाली सांप्रदायिक बहसों को प्राइम टाइम कार्यक्रमों की सफलता का जरिया बना लिया गया। गैरजिम्मेदार एंकर इसमें उकसाने का कार्य करते हैं। हालांकि, विवादित बयान आम भारतीय की राय नहीं है और न ही वे सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे सतारूढ़ पार्टी के पदों पर तो रहे हैं। भाजपा को अब सोचना होगा कि विकास के मुद्दों से इतर विभाजनकारी राजनीति उसके व देश के लिए घातक हो सकती है।

फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब दूसरों का सम्मान करना भी है

क्या सरकारें सब्र के बांध टूटने का इंतजार कर रही हैं? जो लगभग टूटने की कगार पर पहुंच ही चुका है। वह सिर्फ इतना देख रहा है कि अराजकता के खिलाफ संविधान और कानून के दायरे में कोई तो वीर बहादुर पार्टी या व्यवस्था होगी जो आगे बढ़कर आएगी और चीजों को दुरुस्त करेगी। लेकिन कुछ हफ्तों में मजहब के नाम पर जिस तरह लगातार भय का माहौल बनाया जा रहा है, लग ही नहीं रहा कि देश किसी संविधान और कानून के जोर से चलता है। यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन फिर बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान को देश में एक मजहब भर की बपौती बना दिया गया है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उसी के दायरे में है। वह जो कहे जैसा कहे, सबको मानना पड़ेगा। कानून उससे डरकर बिल में दुबका पड़ा रहे। क्या यह वही देश है जहां जड़ **इस्लामिक ताकतें** मनमाने तरीके से पाकिस्तान लेकर भी संतुष्ट नहीं हुई। क्या उन्हें अब दूसरे पाकिस्तान की दरकार है? लग तो ऐसा ही रहा है। हर चीज में एकसूत्री एजेंडा कि किसी भी तरह भारत को अराजकता की आग में झोंक देना है। यह देश पिछले दो साल से कोरोना महामारी और चीन से आमने-सामने का मोर्चा लेते हुए बचा कैसे है, यह समझ में नहीं आता। शायद ईश्वरीय चमत्कार ही है।

आशंका से ग्रस्त है मुसलमान?

नागरिकता कानून से फिलहाल नुपुर शर्मा के विवाद तक एक जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या यह संभव है कि 20 करोड़ लोगों का रातोंरात नरसंहार कर दिया जाएगा या उन्हें भारत की जमीन से ही बेदखल कर दिया जाएगा? ऐसा कहीं होता है क्या? यह तो कई अरब देश भी नहीं कर पाए जो कभी बर्बरता के लिए मशहूर थे। भारत जिसने ना जाने कितने अल्पसंख्यक समुदायों को मानवीय शरण दी। यहां तक कि खलीफा का विद्रोह करने वाले को भी मानवीय शरण दी जिसकी कीमत राजा दाहिर सेन ने समूचा वंश और राज्य गंवाकर चुकाई। आज का जो पाकिस्तान है उसने इतिहास की सबसे बड़ी बर्बादी इसी एक मानवीय गलती की वजह से झेली थी। अरबों ने हमला सिर्फ इसी एक वजह से किया था। इसमें पैगंबर साहब का तो दोष नहीं था। दोष लालची खलीफा और कासिम का था। किसी ने कभी भारत पर विदेशी हमलों के लिए पैगंबर साहेब को दोषी नहीं ठहराया है। जहां तक कासिम की बात है धरती पर जब तक आखिरी भारतीय जिंदा रहेगा, चिल्ला-चिल्लाकर उसके कुकर्मों को बताता रहेगा।

समझ में नहीं आता कि आखिर किस विचारधारा ने भारतीय मुसलमानों के अंतर्मन में दुनियाभर की आशंकाओं और विरोधाभास को भर दिया है? यह देश आजम खान और **ओवैसी** की पुश्तैनी जायदाद नहीं है। धार्मिक नेता मौलाना मदनी की भी जायदाद नहीं है जो **वलीउल्लाह** जैसे आतंकी को फांसी की सजा से बचाने का कानूनी तिकड़म रच रहे हैं। यह देश नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भी जायदाद नहीं है। देश इनसे पहले से था और हजारों हजार साल तक रहेगा भी। यह देश बहुसंख्यक हिंदुओं और गैर इस्लामी अल्पसंख्यकों का हिस्सा है। उनका अपना हिस्सा है। उन्होंने इसी अपने हिस्से में मुसलमानों को मनुष्य की तरह संविधान और कानून के दायरे में रहने की अनुमति दी थी, सिर पर चढ़कर कूदने की नहीं। जैसे रोज-रोज कूद रहे हैं। उन्हें भारतीय बनकर ही रहना पड़ेगा। वर्ना सरकार और विपक्ष का तो नहीं पता, लेकिन भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ तो बहुत मुसीबत पहाड़ की तरह सिर पर गिरेगी।

मामला कहां से कहां पहुंचा दिया?

ज्ञानवापी में मामला कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंचा दिया गया? ज्ञानवापी मामले में किसने याचिका डाली थी। ज्ञानवापी में मस्जिद के लिए लड़ने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि याचिका किस कमजोरी की वजह से स्वीकार हुई? सर्वे शिवलिंग का मिलना तो बाद की चीज है। बुद्धि नाम की भी कोई चीज होती है। जब ज्ञानवापी के बहाने मुगलिया सल्तनत के सबसे बर्बर और आततायी शासक औरंगजेब के कारनामों पर बात हो रही थी तो उसमें पैगंबर घुसे ही कैसे? दंगा करने पर आमादा भीड़ ने एक बार भी इन सवालों पर विचार किया क्या? भारत की छाती को हमेशा चाकू से चाक करने की कोशिश में बैठा ओवैसी संभाजी

निरंकुश तत्वों पर नियंत्रण जरूरी

आज हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों को यह समझना होगा कि उन्हें एक-दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान करना होगा। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि दोनों ही वर्गों में ऐसे लोग बहुसंख्या में हैं, परंतु दुर्भाग्य से दोनों ओर कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, जो माहौल खराब कर सांप्रदायिक परिवेश में विष घोलने में लगे हैं। हिंदुओं में कुछ धर्मगुरु ऐसी बातें करते हैं जैसे वे दिमागी दिवालियापन से ग्रस्त हों। कोई नरसंहार की बात करता है, कोई लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, कोई दस बच्चे पैदा करने की बात कहता है। मुसलमानों को देखा जाए तो उनके धर्मगुरु इंटरनेट मीडिया पर ऐसी बकवास करते हैं जो केवल कोई असंतुलित मस्तिष्क का मतांध आदमी ही कर सकता है। एक लेखक के अनुसार गोरी, गजनी, खिलजी, तुगलक, बाबर और औरंगजेब के समय से चली आ रही इस्लामिक कट्टरता आज भी एक समूह में उसी प्रकार मौजूद है। ये लोग जब तक अपने समुदाय के गौरव की तलाश में विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करते रहेंगे तब तक सांप्रदायिक वैमनस्य बना रहेगा। मुसलमानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व वे अंग्रेजों के मोहरे बने रहे और बाद में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण उनके सोच में संतुलन नहीं रहा। दूसरी ओर हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उनके कुछ धर्मगुरु अनर्गल बातें करते रहते हैं और कुछ निरंकुश तत्व भगवा वस्त्र पहनकर कानून को हाथ में लेने लगे हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत है। मीडिया पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, कुछ टीवी चैनल लोगों को जहर उगलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस विषय पर चिंता प्रकट की है। विधिवेत्ता ताहिर महमूद के अनुसार मोहम्मद साहब ने एक जगह कहा है कि उन्हें भारत से अरीज-उल-रूहानिया यानी अध्यात्म की खुशबू आती है। इस देश के मुसलमान भी जिस दिन यहां की आध्यात्मिक सुगंधि का अनुभव करने लगेंगे तब शायद देश के सांप्रदायिक माहौल में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे भारत को 'दारुल अमन' यानी शांति की धरती बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि यह देश कभी 'दारुल हरब' यानी अशांति का अखाड़ा न बने।

महाराज के हत्यारे आलमगीर औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने किस मकसद से पहुंचा था? संभाजी के ही महाराष्ट्र में ऐसा करने की उसकी हिम्मत आखिर कैसे हुई? लगता है कि भारत के बड़प्पन को उसकी कमजोरी समझ लिया गया। सड़कों पर निकलने वाली उन्मादी भीड़ को पता नहीं कि दूसरों की नसों में भी पानी नहीं बल्कि गर्म और गाढ़ा खून ही बहता है।

ज्ञानवापी में सर्वे के बाद शिवलिंग मिला था। कोर्ट में लड़ाई गई तो गई कैसे? और जब कोर्ट में नहीं लड़ पाते हो, चुनाव में नहीं लड़ पाते हो- उसे सड़क पर खींच रहे हो। भला औरंगजेब के कुकर्मों को अपना कुकर्म क्यों मान बैठे हो? कोई पत्थर प्राचीन शिवलिंग है या फव्वारा- पुरातत्व के अध्येता दो सेकेंड में साफ कर देंगे। अगर अपने धर्म पर कोई बात सुनने की क्षमता नहीं है फिर किस अधिकार से दूसरों के धर्म पर सवाल उठाते हो। नुपुर शर्मा ने जो कहा वह मजहबी दायरे में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने माफी मांग ली। सरकार भी बैकफुट पर है। क्या अब इसी बहाने देश को अराजकता में झोंकने की कोशिश हो रही है। वह भी उस वक्त जब दुनियाभर में वैश्विक हालात रोज तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। हैरानी होती है कि भारतवंशी मुसलमान औरंगजेब और पैगंबर साहेब को एक ही तराजू पर रखकर कैसे तौल सकता है?

अरब देशों की हिमाकत

नुपुर शर्मा के बयान तक तो पैगंबर साहेब का जिक्र तक नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर आमखास हर तरह के मुसलमान औरंगजेब को बचाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। हर कोई मजहब के लिए सिर कटाने और काटने की बात करता फिर रहा है। क्या दूसरे लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। भारतीय मुसलमान अरब देशों की ऐसे तारीफ कर रहा है, जैसे उनकी खैरात पर भारत पलता है। अरब का कोई देश भारत पर एहसान नहीं कर रहा। वह पाकिस्तान और अमेरिका का करता होगा। भारत को फ्री में तेल नहीं मिलता। मस्जिदों-मदरसों को जरूर अरब से चंदा मिलता होगा। एक देश के तौर पर भारत किसी भी मुल्क से जो पाता है उसकी कीमत देता है। बदले में उनका पेट भी भरता है और तन ढकने के लिए कपड़े भी देता है। भारत भी मुफ्त में नहीं देता। दुनिया का यही कारोबार है।

ताज्जुब इस बात पर है कि खुद को पढ़ा-लिखा बताने वाला नौजवान भी औरंगजेब को अपना आका कह रहे हैं। एक लिखता है- पैगंबर साहेब और औरंगजेब हमारे आका हैं। कौन सी एक वजह है कि भारत के लोग औरंगजेब को पूजे? कोई एक वजह है तो बताइए। धार्मिक विद्वेष में भारत के निरीह लोगों की हत्या करने वाला एक हत्यारा किस

आस्था बनाम हिंसा

लोकतंत्र में किसी मसले पर विरोध प्रदर्शन करना लोगों का नागरिक अधिकार है, पर हिंसक बर्ताव करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। किसी को भी किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पैगंबर पर दिए बयान को लेकर दुनियाभर में नाराजगी जाहिर की गई। उस पर सरकार ने संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसलिए अपेक्षा की जा रही थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जिससे देश और समाज में अस्थिरता पैदा हो। पर कुछ शरारती तत्वों को शायद यह मुद्दा एक अवसर की तरह हाथ लगा है और वे इसे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए मस्जिदों को चुना। सब जानते हैं कि जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं और उन्हें उत्तेजित कर अपना मकसद आसानी से साधा जा सकता है। वरना उनका मकसद सचमुच केवल विरोध प्रदर्शन करना होता, तो वे कोई और जगह चुनते। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले हर धर्म में मौजूद हैं। इस्लाम इससे अछूता नहीं है। यह बात इस समुदाय के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी वे कैसे अपना विवेक खोकर हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए। शायद लंबे समय से उनके भीतर दबा आक्रोश और असुरक्षाबोध अचानक प्रकट हुआ होगा। मगर इन घटनाओं के लिए पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन लोगों की पहचान होनी चाहिए, जिन्होंने साजिशन भीड़ को हमलावर बना दिया। फिर यह सवाल अपनी जगह है कि कैसे खुफिया एजंसियों और प्रशासन को ऐसी घटना की आशंका नहीं हुई। गत दिनों ही कानपुर में, जुमे के रोज हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस घटना से कोई सबक लेना क्यों जरूरी नहीं समझा गया कि इस जुमे को भी उप्र सहित कई राज्यों में वैसी ही घटना हो गई।

शर्त पर भारत का पूजनीय हो सकता है? झगड़ा किस बात का है भाई? पैगंबर को देश का हर नागरिक सम्मान देने को तैयार है। उसे शिकायत नहीं। मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों के आगे इक्का-दुक्का को छोड़ किसी मुसलमान ने सिर नहीं झुकाया। लोग इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते। बुरा मानते तो करोड़ों लोग मजारों-दरगाहों को श्रद्धा के साथ पूजते नहीं। कंधे पर ताजिया नहीं ढोते और मस्जिदों की हिफाजत भी नहीं करते। इस्लाम के पैदा होने के हजारों साल पहले भारत और उसकी सांस्कृतिक सभ्यता का वजूद रहा है। बावजूद अपनी श्रेष्ठता को किनारे रखते हुए हर दौर में हर संस्कृति के साथ घुलने-मिलने की कोशिश भारत के लोगों ने की है।

संघ प्रमुख का संदेश

संघ प्रमुख ने यह उचित ही कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? उनके कथन में निहित यह संदेश स्पष्ट है कि अब संघ मंदिर-मस्जिद मामले में किसी नए आंदोलन का पक्षधर नहीं है। ज्ञानवापी प्रकरण पर देश के विभिन्न इलाकों में बढ़ रहे सामाजिक तनाव के संदर्भ में उनके शब्दों पर गौर करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है, जिसे हम अब नहीं बदल सकते। न तो आज के मुस्लिम और न हिंदू इस ऐतिहासिक तथ्य के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में आक्रांताओं के साथ ही इस्लाम ने दस्तक दी और हिंदुओं का मनोबल तोड़ने के लिए मंदिरों का विध्वंस किया गया। सच है कि यह सब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इस मुद्दे को तूल देकर क्यों हर मस्जिद में शिवलिंग खोजा जाए? मोहन भागवत ने यह भी कहा कि लोगों को हर दिन एक नए मुद्दे को नहीं उछालना चाहिए। उनका यह कहना भी उल्लेखनीय है कि जो लोग अदालत का रुख करते हैं, उन्हें अवश्य ही उसके निर्णय को भी स्वीकार करना चाहिए। संविधान और न्यायिक तंत्र पवित्र हैं, जिनका सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए।

निरंकुश तत्वों पर नियंत्रण जरूरी

इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में जिस प्रकार की भद्दी, अश्लील एवं ओछी भाषा एवं भाव-भंगिमाओं का प्रदर्शन हो रहा है, उससे यही लगता है कि ऐसा करने वाले शायद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 295 के प्रविधानों या ऐसे ही उन अन्य कानूनों से परिचित नहीं हैं, जो आपत्तिजनक बयानों के मामले में कड़ी कार्रवाई निर्धारित करते हैं। ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा और हर्जाना या दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। टेलीविजन पर होने वाली बहसें बेलगाम होकर सांप्रदायिक स्थिति को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। यदि इन बहसों में मर्यादा रेखा लांघने वालों पर आईपीसी की इस धारा का उपयोग नहीं किया गया तो स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाए।

मोहन भागवत के विवेकसम्मत सुझाव पर अमल करते हुए भाजपा ने कदम भी उठाए हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने अपनी एक प्रवक्ता पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। उन्होंने माफी मांगने के साथ अपनी सफाई में यह भी कहा कि टीवी चैनल पर हो रही बहस में **भगवान शिव को** लगातार अपमानित करने से उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आवेश में वह बात कह दी, जिस पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। उनकी मानें तो उन्होंने जो कहा वह हदीस का हिस्सा है और मुस्लिम समाज उससे अवगत भी है। प्रतीत होता है कि उबाल उस टिप्पणी की विषयवस्तु को लेकर नहीं, बल्कि उस लहजे को लेकर है, जिसमें वह बात कही गई। जो भी हो, इसका निर्धारण तो अदालत ही करेगी। इसीलिए कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पूरी फुटेज देखकर यह पड़ताल करें कि किसने आईपीसी के प्रविधानों का उल्लंघन कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी की। भाजपा ने अपने एक अन्य प्रवक्ता को भी उनके विवादित ट्वीट के लिए निष्कासित किया है। इस प्रवक्ता के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को सजगता दिखाना इसलिए और जरूरी है, क्योंकि टीवी चैनलों पर आने वाले मेहमान हिंदुत्व को लेकर धुआंधार अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। टीवी चैनलों की बहसों में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर जिस प्रकार की ओछी एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर अगर हिंदू भी मुस्लिमों की भांति भड़कने लगें तब देश के हर शहर में रोज हिंसा होगी। ट्विटर, फेसबुक और वॉट्सएप के इस दौर में भारत में जिस तरह के नए लोकतंत्र का उभार हो रहा है, उसमें मुसलमानों को धीरज रखने और सहिष्णु होने का अभ्यस्त होने की आवश्यकता है। जब उनके मुल्ला और कथित प्रवक्ता हिंदुओं को लेकर सार्वजनिक रूप से गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के साथ, मौत की धमकी देते, जगह-जगह हिंसा भड़काते या जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर लामबंद होने की कवायद करते दिखते हों तो उन्हें अति-संवेदनशील होने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यदि हम देश के पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों से कड़ाई से निपटना होगा। इस मामले में उप्र सरकार ने एक मिसाल कायम की है। योगी सरकार कानपुर में हिंसा भड़काने वालों के बैंक खाते खंगालने से लेकर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कड़ा संदेश दे रही है। जब भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई कर अपनी ओर से पहल कर दी है, तब पूरा दारोमदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे ही अन्य मुस्लिम संगठनों पर है कि वे इस कार्रवाई और संघ प्रमुख मोहन भागवत के कथन के मर्म को समझें। यदि वे स्वतंत्रता के बाद से देश में कायम पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हैं और सामाजिक सौहार्द की दिशा में योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने पाले में खड़े कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम कसनी होगी।

नमाज के बाद पत्थरबाजी या हिंसा किस किताब का हिस्सा?

जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी या हिंसा का ये पहला मामला नहीं है। जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी का इतिहास जुमे की नमाज के साथ ही जुड़ा हुआ है। हालांकि, अब कश्मीर में पत्थरबाजी पुरानी याद हो गई है। और, अब राज्य में हिंदुओं की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जाने लगा है। हां, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसके लिए जुमे का इंतजार नहीं किया जाता है। वैसे, गत दिनों कानपुर में हुई हिंसा भी शुक्रवार की नमाज के बाद ही भड़की थी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों से लेकर तीन तलाक के खिलाफ तकरीरें जुमे के दिन ही दी जाती हैं। क्योंकि, इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा होते हैं। लेकिन, इन तमाम बातों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए। तो, सबसे अहम सवाल यही है कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी या हिंसा किस किताब का हिस्सा है? देश कानून और संविधान से चलता है। तो, प्रदर्शन कीजिए। लेकिन, पत्थरबाजी और हिंसा की जाहिलता का प्रदर्शन मत कीजिए।

सभ्यताओं की लड़ाई से जंग की ओर

दरअसल, गंगा-जमुनी तहजीब की बात करने वाले ये तमाम जिम्मेदार लोग इस हिंसा, पत्थरबाजी और अराजकता का ठीकरा इस्लाम के सिर नहीं आने देना चाहते हैं। क्योंकि, अगर ऐसा हो गया, तो देश के मुस्लिमों का एक वर्ग सीधे तौर पर मजहबी धर्मांधता से घिरा हुआ घोषित हो जाएगा। इन प्रदर्शनकारी मुस्लिमों को बाहरी तत्व बताकर तमाम जिम्मेदार लोग केवल अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, इन मुस्लिम प्रदर्शनकारियों में से एक भी पाकिस्तान या अन्य इस्लामिक देश से नहीं आया था। ये सभी इसी भारत देश के बाशिंदे हैं। धर्मनिरपेक्षता का नारा देने वाला मुस्लिमों का एक वर्ग खुलेआम लोगों के बीच भड़काऊ तकरीरें करता है। और, उनके अंदर की मजहबी कट्टरता को और बढ़ाता है।

कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट की सर्वसुलभता ने रजा अकादमी, पीएफआई जैसे दर्जनों मुस्लिम संगठन, जो किसी समय खुलकर अपने प्रदर्शनों को अंजाम देते थे। अब उन्हें बेनकाब होने में समय नहीं लगता है। बात जम्मू-कश्मीर के किसी मौलाना के भड़काऊ भाषण देने की हो या कर्नाटक में नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी देने की। पलक झपकते ही ये चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। खैर, इसे किनारे रखिए। बीते साल तमिलनाडु के किसी हिस्से में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने पर हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने का फैसला कर लिया जाता है। और, इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट को फैसला देना पड़ता है। ऐसी खबरें भी अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छिपी नहीं रहती हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, तो यह एक तरीके से सभ्यताओं की लड़ाई ही नजर आती है।

आतंकियों की ताकत को कुचलना होगा

पिछले कुछ महीनों में घाटी में कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर उनकी हत्या के मामलों में जो तेजी आई, उसने पूरे देश की चिंता बढ़ाई है। 'टारगेटेड किलिंग' की ये घटनाएं असल में आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा हैं। पिछले कुछ समय से सुरक्षा प्रतिष्ठान की सक्रियता उन पर आफत बनकर टूटी है। इस बीच एनआईए की एक अदालत द्वारा आतंकी यासीन मलिक को सुनाई गई सजा से भी स्पष्ट संदेश निकला है कि भारतीय राज्य अब आतंकियों से सख्ती से निपटने वाला है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एनआईए अदालत ने शांति-सुलह का ढोंग करने वाले पाकिस्तानी पिट्ठू हुर्रियत कांफ्रेंस जैसे संगठन को भी 'आतंकी' बताया। वास्तव में आतंकी, हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठन और पाकिस्तान का त्रिकोण भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करता रहा है और आज भी कर रहा है। इसमें मुख्यधारा के नेताओं का चौथा कोण भी है, जिन्हें अभी अनावृत्त करना शेष है। ये चारों मिलकर अपनी-अपनी तरह से भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं।

एनआईए की जांच में यह सामने आया कि यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मुहम्मद अशरफ खान, मसर्रत आलम, जफर अकबर, सैयद अली शाह गिलानी, उसका बेटा नसीम गिलानी और आसिया अंद्राबी आदि इस जंग के प्रमुख किरदार हैं। यासीन मलिक इस आतंकी काकटेल के सबसे दुर्दांत चेहरों में से एक है और उसे सजा मिलने के बाद उम्मीद बंधी है कि कानून के हाथ अन्य आतंकियों तक भी पहुंचेंगे। स्पष्ट है कि इससे भी आतंकी और उनके समर्थक बौखलाए हुए हैं। जिस तरह यासीन को सजा मिली, उसी तरह अन्य आतंकियों और उनके आकाओं को भी सजा मिलनी चाहिए।

यासीन की सजा पर उठे इन सवालों का भी जवाब मिलना चाहिए कि आखिर उसके उन मददगारों को सजा कब मिलेगी, जिन्होंने उसे गांधीवादी साबित करने के लिए हरसंभव जतन किए। आतंक के खिलाफ युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में यह भी सामने आना चाहिए कि चार सैन्य अफसरों की हत्या और रूबिया सईद के रहस्यमय अपहरण में लिप्त होने के बावजूद 1994 में यासीन को क्यों और किसके इशारे पर रिहा किया गया? कश्मीर में आतंकियों के पनाहगार बने सफेदपोश 'जयचंदों' का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए और यह भी जांचा जाना चाहिए कि क्या आतंकियों-अलगाववादियों के तार मुख्यधारा के नेताओं और स्वयंभू सेक्युलर-लिबरल तत्वों से भी जुड़े रहे हैं?

कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद तो इसके साफ संकेत मिल रहे हैं कि कश्मीर के प्रशासन में भी आतंकियों के समर्थक घुसे हुए हैं। आतंक की कमर तोड़ने के लिए इन्हें भी बेनकाब करना होगा। सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के साथ न्यायपालिका को भी तत्परता दिखानी होगी। कम से कम आतंकवाद के संगीन मामलों का निपटान तो त्वरित गति से होना ही चाहिए। बेहतर हो कि इन मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में हो, ताकि आतंकियों और उनके समर्थकों को सबक सिखाने के साथ कश्मीरी अवाम को भी सही संदेश दिया जा सके। यह एक तथ्य है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद को अनदेखा किया। यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकियों को स्वीकार्यता प्रदान करना इसका प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने वाले कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल और अप्रैल 2005 में शुरू हुई 'कारवां-ए-अमन' बस सेवा से पाकिस्तान जाने वालों में यासीन भी शामिल था। उसे 'कश्मीर समस्या' पर बात करने के लिए अमेरिका भी भेजा गया।

कश्मीर मुद्दे के जबरिया स्टेकहोल्डर बने ये आतंकी-अलगाववादी और यहां तक कि मुख्यधारा के कई नेता भी दिल्ली में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करते थे, जम्मू में सेक्युलरिज्म और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते थे और श्रीनगर पहुंचते-पहुंचते पाकिस्तानपरस्ती पर उतर आते थे। विदेशी पैसे पर पलने वाले इन लोगों ने हमेशा दहशतगर्दी और खून-खराबे की फसल बोई और काटी है। ये न सिर्फ भारत के, बल्कि अमन-चैन और तरक्की के भी दुश्मन हैं। उन्हें उनकी करतूतों की सजा देकर ही आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है और जम्मू-कश्मीर में खुशहाली लाई जा सकती है। अब इस दिशा में काम हो रहा है। यासीन मलिक की सजा पर 'गुपकार गैंग' के नेताओं की प्रतिक्रिया इसकी बानगी है। यह प्रतिक्रिया उनके असल चेहरे और मंसूबों को उजागर करती है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि इन नेताओं की प्रतिक्रिया काफी कुछ पाकिस्तान जैसी रही?

● **अक्स ब्यूरो**

आतंकियों की आंखों में चुभ रही शांति

जम्मू-कश्मीर में तेजी से सामान्य हो रहा जनजीवन भी आतंकियों की आंखों में चुभ रहा है। कामकाज के लिए देशभर से लोग राज्य में आ रहे हैं। दशकों बाद इस बार इतनी बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर घूमने निकले हैं। 5 अगस्त, 2019 के बाद हुए तमाम सुधारों और सकारात्मक परिवर्तन ने आतंकियों और उनके समर्थकों को बेचैन एवं बदहवास किया है। ऐसे में सरकार और सुरक्षा बलों को अपने आतंक विरोधी अभियान को और धारदार बनाना होगा, ताकि राज्य में पटरी पर आती जिंदगी को आतंकी अपनी करतूतों से बेपटरी न कर सकें। इसी के साथ घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को बसाने की योजना को दृढ़ता से आगे बढ़ाना होगा, भले ही इसके लिए विशेष कॉलोनियां क्यों न बनानी पड़ें? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए लोगों के भरोसे और मनोबल को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मनोबल की लड़ाई भी है। यह समझने की जरूरत है कि आतंकियों और उनके समर्थकों को समय पर सख्त सजा न देने से अतिवाद और आतंकवाद बढ़ता ही है। अच्छी बात है कि देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त कदम उठाए जा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर से तमिलनाडु तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार सियासी दलों के नेताओं पर कार्रवाईयां कर रही है। जिससे इस बात की संभावना जगने लगी है कि मोदी-विरोधी गठबंधन शायद न बने लेकिन ईडी पीड़ितों का एक गठबंधन बन सकता है।

महागठबंधन का मुद्दा भी मकसद भी!

नेशनल हेराल्ड मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार से पूछताछ करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। इसी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को जमानत तक करवानी पड़ी थी। खैर, इस मामले की पूछताछ का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले सभी सियासी दलों के बीच अभी भी किसी तरह का ताल-मेल नजर नहीं आता है। मोदी-विरोधी गठबंधन को लेकर की जा रही तमाम कोशिशें अभी तक हवा-हवाई ही साबित हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार दो लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अभी से जोर-आजमाइश में लगा हुआ है। कांग्रेस ने हाल ही में चिंतन शिविर के जरिए मोदी-विरोधी गठबंधन तैयार करने के लिए कमर कसी है। तो, पंजाब जीतने के बाद सातवें आसमान पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल अपने अखिल भारतीय चुनावी अभियान पर अकेले ही निकल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही किनारे लगाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी एक अलग तीसरे मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ फिलहाल कई दल अलग-अलग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।

इन तमाम कोशिशों को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि मोदी-विरोधी गठबंधन कभी मूर्त रूप ले सकेगा। लेकिन, हाल ही में हुई ईडी कार्रवाईयों को देखकर एक उम्मीद जगती है कि मोदी या भाजपा के विरोध में न सही, तमाम सियासी दल ईडी की कार्रवाई को देखते हुए शायद महागठबंधन बना लें। जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के सियासी दलों और उनके नेताओं पर हो रही ईडी की कार्रवाई इस संभावना को और बल देती है कि मोदी-विरोधी न सही, ईडी-विरोधी महागठबंधन ही बन जाए। विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी की कार्रवाईयों से नेताओं के बीच खलबली तो मची ही हुई है। आइए जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक प्रवर्तन निदेशालय ने किन राज्यों के किन सियासी दलों के नेताओं पर कार्रवाई की है।

जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला से भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में फारूख अब्दुल्ला ईडी के रडार पर हैं। इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से भी ईडी ने पूछताछ की थी। दरअसल, उमर अब्दुल्ला से उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान जम्मू-कश्मीर बैंक से एक इमारत खरीदने के मामले में यह पूछताछ की गई थी। पीडीपी नेता महमूबा मुफ्ती से भी बीते साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की थी।

पंजाब: कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के खिलाफ पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई काफी चर्चा में रही थी। अवैध रेत खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चन्नी के भांजे को गिरफ्तार भी किया गया था।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के भी कई मंत्रियों पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर बनी हुई है। एनसीपी की बात की जाए, तो एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के खिलाफ भी प्रवर्तन निदेशालय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज कर चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की

छापेमारी का चुनावी कनेक्शन?

अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय ही जांच एजेंसियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जिससे ऐसा लगता है कि छापेमारी का चुनावी कनेक्शन है। इस साल उप्र में अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। सपा नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम की रेड ऐसे समय पड़ी जब उप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म था और सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक चुनावी अभियान में जुटी थी। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उप्र ही नहीं बल्कि देश के राज्यों में भी चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही एक्टिव थी और विपक्षी नेताओं को अपने रडार पर लिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु में चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता देखने को मिल चुकी है। इसी साल फरवरी-मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर टीएमसी नेता थे। कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई टीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को जांच में शामिल होने के लिए समन दिया। इससे जांच एजेंसियों की कार्रवाई संदेह में घिर जाती है।

महाराष्ट्र की राजनीति में ईडी का खौफ

महाराष्ट्र वो राज्य है जहां हाल के सालों में ईडी ने सबसे ज्यादा मामले राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से ईडी राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों के केंद्र में है। महाराष्ट्र में ईडी के निशाने पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम आया वो था एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे छगन भुजबल का। भुजबल पर आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के पुनर्निर्माण के ठेकों में घोटाला किया और उससे अर्जित की गई कमाई को विदेश में ठिकाने लगाया। इस मामले में उनके भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद चाचा भतीजा को जमानत मिली। साल 2021 में एक और एनसीपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। देशमुख पर ट्रांसफर पोस्टिंग से अर्जित कमाई से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। साल 2022 में ईडी की गिरफ्त में आने वाले सबसे ताजा राजनेता बने एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक। उन पर दाऊद गिरोह से संपत्ति की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब तक एनसीपी के तीन मंत्री ईडी के मार्फत जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन ईडी के निशाने पर सिर्फ एनसीपी ही नहीं हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार का प्रमुख घटक दल शिवसेना भी है। हालांकि अब तक शिवसेना का कोई नेता गिरफ्तार तो नहीं हुआ है लेकिन ईडी की कार्रवाई ने शिवसेना नेताओं की नींद उड़ा रखी है।

थी। जिसके चलते अनिल देशमुख को अपना मंत्री पद भी खोना पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नवाब मलिक अभी भी जेल में हैं। और, ईडी अब नवाब मलिक की पत्नी और दोनों बेटों पर भी शिकंजा कस रही है। एनसीपी के नेता अनिल भोंसले, एकनाथ खड़से का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

शिवसेना: इसी साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रा चाल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की 1,034 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। बीते साल ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से लंबी पूछताछ की थी। इसी साल प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर माधव पाटनकर की संपत्तियां भी जब्त की थीं। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत ये कार्रवाई हुई थी। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। अनिल परब पर अनिल देशमुख से जुड़े मामले में ही जमीन सौदे में हेराफेरी और करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक, सांसद आनंदराव अदसुल और सांसद भावना गवाली भी ईडी की रडार पर हैं।

कांग्रेस: पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रीति श्रॉफ और उनके पति पर बैंक फ्रॉड के जरिए 35 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

राजस्थान: बीते साल प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को 130 करोड़ के एक फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन की 5 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को जांच में सहयोग न करने की वजह से गिरफ्तार किया है।

उप्र: बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से शिकंजा कस रहा है। मायावती और उनके रिश्तेदारों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कई करीबियों पर उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। इसके अलावा माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के सहयोगियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है।

बिहार: चारा घोटाले में अपराधी घोषित हो चुके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें प्रवर्तन निदेशालय लगातार बढ़ा रहा है। ईडी ने चारा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

झारखंड: हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। पूजा सिंघल के सीए के घर से 18 करोड़ कैश बरामद हुआ था। खनन विभाग की अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भेजा जा चुका है। और, फिलहाल ईडी इस मामले के सियासी धागों को खोलने की कोशिश कर रही है। जेएमएम चीफ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पहले से ही खनन पट्टा आवंटित किए जाने के मामले की सुनवाई चल रही है।

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में हुए खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

तमिलनाडु: प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के मंत्री ए राधाकृष्णन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। और, इसी साल फरवरी में डीएमके नेता की 6.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर चुकी है। शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी ने उनकी 50 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। जिसमें इंग्लैंड के समरसेट का एक बंगला, स्पेन के बार्सिलोना में एक टेनिस क्लब जैसी संपत्तियां शामिल थीं।

● **विपिन कंधारी**

...एक नया आत्म-विश्वास

मोदी के 8 साल में भारत ऐसे देश के रूप में उभरा है, जिसमें अपने लिए ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, और जिसे उम्मीदों को साकार करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। सुधार के साथ एक राजनीतिक चुनौती है- नया भारत और भारतवासी ज्यादा देर तक 'फ्री-बी' और लुभावने नारों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। उन्हें बेहतर, सस्टेनेबल भविष्य की आकांक्षा है। नरेंद्र मोदी ने सही मायने में उन महर्षि अरविंद के दर्शन को जमीन पर उतारा है, जिनका यह मानना था कि कांग्रेस को भारत की अपनी पारंपरिक राज्य व्यवस्था साकार करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी तौर-तरीकों से देश का कभी भला नहीं होने वाला।

देशों में ऐतिहासिक परिवर्तन और उत्थान पेचीदा होता है। इसको समझने के लिए बड़ी घटनाओं को वैश्विक संदर्भ, नेतृत्व, परिवर्तन के स्थायित्व वगैरह को साथ जोड़ना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल भारत के उत्थान का महत्वपूर्ण दौर है- एक 'नया' भारत उभर रहा है जो महत्वाकांक्षी उम्मीदों से लबरेज है और जहां आत्मविश्वास खिताब की तरह धारण किया जाता है।

आजादी के बाद, लुई माउंटबेटन की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति से लेकर अधिकतर प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता रही है। नेतृत्व निर्विवादित रूप से कांग्रेस के हाथ में रहा। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद सरकारी प्रणाली के शिकंजे देश और जनता पर कस गए और 1947 का वह जोशो-खरोश कम होता रहा। यह शिकंजा इमरजेंसी ले आया और हमें राहत जयप्रकाश नारायण और 1977 में जनता पार्टी की जीत की वजह से मिली। राजीव गांधी ने लाइसेंस राज को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की पर समय कम था। असली क्रांतिकारी बदलाव पीवी नरसिंह राव के तहत आया। निजी उद्यमियों के जज्बे को उड़ान का मौका मिला और भारत सरकारी शिकंजे से निकलना शुरू हुआ। राव की विरासत मुख्यत: बाजार संचालित अर्थव्यवस्था है, जिसके अपने नफा-नुकसान हैं। 1947 में राजनीतिक आजादी मिली तो राव के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को खोला।

मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। कोविड-19 जैसी महामारी की भयावह चुनौती के बावजूद उनके 8 साल में जन धन खाते, आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) जैसी गेम चेंजिंग योजनाएं दिखीं। सुर्खियों से अलग शायद सबसे अहम यह है कि मोदी के 8 साल भारत के उत्थान में निर्णायक दौर साबित हो रहा है। भारत और भारतीयों ने आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच के हर क्षेत्र में कदम रखने शुरू किए।

मोदी-पूर्व भारत यथास्थिति को कबूल कर बैठा था, अपने को परिस्थितियों का बंदी समझकर जैसे हिंदू प्रगति दर से संतुष्टि, गांवों में गरीबी को स्वीकारना, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं में भारी जनहानि का होना। हम घटनाओं से नियंत्रित होते रहे और 'माई-बाप सरकार' पर अति-आश्रित थे। मोदी के तहत यह बदल गया और सक्रियता और पूर्वाकलन से काम का दौर शुरू हुआ। कोविड से निपटना मिसाल बना। जिस समय कई देश दुविधा में फंसे थे, पहले लॉकडाउन का आदेश दिया गया। हालांकि बहुत से लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों को तकलीफें उठानी पड़ीं, लाखों जानें बचाई जा सकीं। फिर टीकाकरण मुहिम शुरू हुई।

विकसित देश टीकाकरण नीति के छोटे

आत्मनिर्भरता की बात पर लोगों का भरोसा

कोरोना महामारी से जब देश-दुनिया त्रस्त थी, तब मोदी देशवासियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। प्रतिक्रियावादी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मोदी ने उनकी परवाह नहीं की। इस दौरान वह पारंपरिक चिकित्सा को एक नई पहचान दिलाने में सफल रहे, जिसका व्यापार करीब 6 गुना बढ़ गया है। उद्योग के क्षेत्र में नैनो यूरिया खाद एक अभूतपूर्व पहल है। कुछ दिन पहले उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। यह खाद तरल होगी और एक बोतल से एक बोरी यूरिया की ताकत मिलेगी। उप्र समेत देश के कई राज्यों में इस तरल खाद के प्लांट लगाए जाएंगे, जो कृषि क्षेत्र में सचमुच एक ऐतिहासिक क्रांति होगी। अभी तक यूरिया खाद आयात करनी पड़ती थी। सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च करने पड़ते थे। अब यह खर्चा बचेगा। अगले कुछ वर्षों में देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर भी इस कड़ी में एक अहम कड़ी है।

घटकों पर बहस करते रहे, इसी दौरान भारत में 194 करोड़ से ज्यादा टीका लगाए गए। इसका एक नजरिया पेश करें तो यह भारत के बाद 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की जनसंख्या के योग के बराबर है।

रक्षा क्षेत्र में भी सक्रियता से बदलाव आया है। हमारी दुखती रग थी खरीद प्रक्रिया का अति लंबा और पेचीदा होना, एवं सुरक्षा दलों के बीच तालमेल। मोदी ने बिपिन रावत को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया। जनरल रावत की मौत के पहले खरीद प्रक्रिया को दुरुस्त करने और सेना के तीनों अंगों में तालमेल में काफी सुधार हुआ। कश्मीर के लोगों को कृत्रिम तरीके से देश की प्रगति से बाहर रहना तकलीफदेह मुद्दा था। जैसे अलेक्जेंडर ने गॉर्डन नॉट काट डाली, मोदी ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया। निहित स्वार्थ द्वारा हिंसा सहित सभी तरकीबों के इस्तेमाल के बावजूद, जम्मू-कश्मीर का भारत से जुड़ाव अब अपरिवर्तनीय है।

मोदी ने यह आस्था भरी कि हम पक्के तौर पर अपनी तकदीर के स्वामी हो सकते हैं। आज हमें राजनीतिक नेतृत्व से भी ऊंची उम्मीदें हैं। महेंद्र सिंह धोनी के उभार ने बड़े शहरों से बाहर क्रिकेट का प्रसार संभव बनाया, इसका संकेत आईपीएल में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं की आमद से मिलता है। मोदी राजनीतिक नेतृत्व को शहरी-एलीट वर्ग से बाहर ले आए। हालांकि चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा और चरण सिंह जैसे गैर-शहरी पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री हुए हैं, मगर वे दिल्ली दरबार के दबदबे में आ गए या उसमें घुलमिल गए। मोदी अपने उभार के लिए 'लुटियन दिल्ली' के कर्जदार नहीं रहे। इसलिए उनके निर्णय प्रणाली में ताजगी है, और राज्यों एवं क्षेत्रों से नीतियों में आदान हुआ है और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। मनोहर पर्रिकर जैसे राज्यों के नेताओं को आगे लाया गया। दूसरा पहलू निजी निष्ठा की उम्मीद है। मोदी ने अपने कामकाज की नेकनीयती से रिकॉर्ड स्थापित किया। उनके परिवार के लोगों का मध्यवर्गीय जीवन इसका सबूत है।

उम्मीदों को असलियत में बदलने के लिए मोदी का नीतियों पर रवैया भी अलग है। सबसे ज्यादा दिखता है शार्ट-कट के बदले प्रक्रिया और नीतियों के अमल पर ध्यान। चाहे वह जन धन हो, स्वच्छता या बिजली कनेक्शन, हर योजना पर विचार कर पहल की गई और परियोजना की तरह अमल किया गया। टाइमलाइन तय करके अमल की गई और फायदे पहचाने गए और उसे साकार किया गया। नीतियों में 'स्केल' था- 45 करोड़ जन धन खाते एक मिसाल हैं।

मोदी ने नीति-निर्माण में दकियानूसी या अहं-केंद्रीत बातों को दरकिनार किया। 'आधार' को बढ़ावा दिया और जीएसटी पर अमल हुआ।

8 साल में भरपूर विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत माला परियोजना और पर्वत माला परियोजना के माध्यम से सारा भारत सड़कों से जुड़ गया है। इन 8 वर्षों में पहली बार पूर्वोत्तर के कई राज्य रेलवे से जुड़े हैं। देश के जनमानस को स्वावलंबी बनाने के लिए मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और ग्राम उदय से लेकर भारत उदय जैसे अभियानों की शुरुआत हुई। हुनर हाट जैसी गतिविधियों के जरिए देश की स्थानीय कारीगरी, कला और कौशल को उचित सम्मान मिला। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक से मुक्ति और हर क्षेत्र में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने की भी सकारात्मक पहल की है। डिजिटलीकरण और एक राष्ट्र-एक टैक्स यानी जीएसटी देश के इतिहास में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। इसी प्रकार सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान और 48,000 करोड़ रुपए से 83 स्वदेशी तेजस विमान खरीदे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू आलोचनाओं के बावजूद, मोदी ने विरासत के बोझ से प्रभावित हुए बगैर पड़ोसियों की ओर हाथ बढ़ाया। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धमक में नहीं आए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को हार्ले-डेविडसन की लॉबीइंग करते वक्त एहसास हुआ। मोदी बदलाव में सहजता महसूस करते हैं। अक्षय ऊर्जा पर जोर, योजना आयोग की जगह नीति आयोग या स्टार्टअप, हर मामला यही बताता है कि विकास की तेज छलांग के लिए के लिए कुछ नया खड़ा करना जरूरी है। दूसरों से सीखने के लिए भी खुलापन है। रक्षात्मक मुद्रा अपनाने या महज तारीफ करने की जगह भारत में दुनिया की बेहतरीन प्रथाओं को अपनाने की भूख है। नीतियों के जरिए ही मोदी के नेतृत्व में भारत उत्थान के नए चरण पर पहुंचा है।

अपनी कल्याणकारी नीतियों में मोदी, महात्मा गांधी के सर्वोदय से प्रभावित है। साथ-साथ योजनाओं का महत्वपूर्ण पहलू है उनको लोगों तक पहुंचाना (टेक्नोलॉजी के जरिए हो; जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति 'अंधा' हो) सबको लाभ मिले, और लाभार्थी दलालों से मुक्त हो। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी), राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो, सभी टेक्नोलॉजी के जरिए होते हैं और बिचौलियों की भूमिका कम करते हैं। यहां तक कि वापस लिए गए कृषि विधेयक भी किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए विकल्प मुहैया और बिचौलियों से छुटकारा दिलाने के लिए था। 'सबका प्रयास' पर जोर दिया गया। हजारों परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी।

सतत् विकास के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ नीतियों में विश्वास की आवश्यकता है। मोदी आम नागरिक और उद्योग के लिए अवसर पैदा करने का माहौल बना रहे हैं, ताकि वे कामयाब हों और दुनिया में चैंपियन बनें। स्किल इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसे पहल से देश के युवाओं का दृष्टिकोण एवं मानसिकता में बदलाव आया है। सरकारी नौकरियों की तरफ देखने के बदले, देश में उद्यमी संस्कृति फल-फूल रही है, और इससे रोजगार पैदा होता है। महामारी के दौरान शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान भारतीय कारोबार को पटरी पर लौटाने और भविष्य में प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं। उत्पादन केंद्रित प्रोत्साहन योजना से देश में उत्पादन क्षमता की संभावनाएं खुलेंगी। आश्चर्य नहीं कि 2021 में 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न तैयार हुए।

● **इन्द्र कुमार**

हसदेव को बचाने का रण

छत्तीसगढ़ में पिछले मार्च से यहां हरिहरपुर, फतेहपुर, मदनपुर, घाटबर्रा, साल्ही, तारा जैसे कई गांवों के आदिवासी 'हसदेव बचाओ' के नारे के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और अडाणी समूह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल, इस वन क्षेत्र के परसा ईस्ट केते बासन के दूसरे चरण और परसा ब्लॉक में खनन करने की इजाजत दे दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एमडीओ अनुबंध पर अडाणी समूह को सौंप दिया है। उसके विरोध में उतरे आदिवासियों का कहना है कि इस खदान की स्वीकृति फर्जी ग्रामसभा के आधार पर ली गई है और इन खदानों के लिए लगभग साढ़े चार लाख पेड़ों की कटाई होगी। विशेषज्ञ भी इसके विनाशकारी परिणाम को रेखांकित कर रहे हैं। इन तमाम आपत्तियों के बावजूद परसा कोयला खदान को मंजूरी दी गई और पेड़ों की कटाई भी शुरू कर दी गई। हालांकि विरोध तेज होने पर फिलहाल पेड़ों की कटाई रोक दी गई है।

हसदेव अरण्य को बचाने की कवायद कोई नई नहीं है। आदिवासी पिछले एक दशक से इस जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल केंद्र सरकार की मुहर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य के परसा कोयला खदान को अप्रैल में मंजूरी दे दी। सरगुजा और सूरजपुर जिले के 1252.447 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोयला खदान का 841.538 हेक्टेयर जंगल का इलाका है, जबकि 410.909 हेक्टेयर क्षेत्र जंगल क्षेत्र से बाहर का इलाका है। हसदेव अरण्य के घने जंगल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पहले ही 2711.034 हेक्टेयर में फैले परसा इस्ट केते बासन का क्षेत्र खनन के लिए आवंटित है। इसके बाद इस वर्ष मार्च में इसी कोल ब्लॉक के समीप 1762.839 हेक्टेयर में फैले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित केते एक्सटेंशन को राज्य सरकार ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी और करीब 10 दिन के अंतराल में सरकार ने परसा कोयला खदान को भी स्वीकृति दे दी।

हालांकि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आंनद शुक्ला कहते हैं, सरकार का पूरा प्रयास है कि आदिवासियों का विस्थापन न हो। राजस्थान सरकार ने कहा कि यहां कोयला खनन रुकने से उनके राज्य में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। उनके इस तर्क के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आधार पर खनन के लिए सहमति दी है कि आदिवासियों का कम से कम नुकसान हो। हम चाहते हैं वहां खनन हो मगर आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर। दूसरी ओर बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुके युवक संबल सिंह खनन की मंजूरी को आदिवासी संस्कृति के लिए विनाशकारी बताते हैं। वे कहते हैं कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में विस्थापन होगा, विस्थापन के बाद पहचान का संकट पैदा हो जाता है। रिश्तेदारी वगैरह भी छूट जाती है। रीति, रिवाज, परंपराएं, संस्कृति सब नष्ट हो जाती हैं। वे कहते हैं, हमारे पूर्वज यदि बगैर बिजली के ही रह लिए तो हम भी उनके ही वंशज हैं। हम भी बिना विकास के रह सकते हैं।

कोल ब्लॉक को मंजूरी मिलने के बाद एक तरफ जहां विस्थापन और उससे जुड़े खतरों की आशंकाओं से आदिवासी चिंतित हैं तो दूसरी ओर सरकार पर 'फर्जी ग्राम सभा' के जरिए वन स्वीकृति देने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी ग्रामीण इस बात को बार-बार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कभी यहां कोल ब्लॉक के लिए अनुमति नहीं दी है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि भूमि अधिग्रहण के लिए कोल बेयरिंग एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला कहते हैं कि परसा कोल ब्लॉक खुलने से हरिहरपुर गांव और फतेहपुर गांव पूरी तरह विस्थापित हो जाएंगे। विवाद का मसला यह है कि लगभग 170 हजार हेक्टेयर का यह जंगल संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां बिना ग्राम सभा की सहमति के न तो वनभूमि का डायवर्जन हो सकता है न ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है। पांचवीं अनुसूची ग्राम सभाओं और वहां हजारों साल से रह रहे आदिवासी समुदायों को उनकी परंपरा, रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं को 'वैधानिक बल' प्रदान करती है। शुक्ला दावा करते हैं कि हरिहरपुर, फतेहपुर और साल्ही ने कभी भी ग्राम सभा में सहमति नहीं दी। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वन स्वीकृति दी गई है, इसलिए आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। हरिहरपुर के ही ठाकुर राम भी कहते हैं कि फर्जी ग्राम सभा के जरिए कंपनी परसा कोल ब्लॉक को चालू करने जा रही है। वे सख्त लहजे में कहते हैं, हम 2 मार्च से यहां बैठे हैं। लेकिन सरकार ने एक बार भी हमसे पूछने की कोशिश नहीं की कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हम क्यों धरने पर बैठे हैं।

● रायपुर से टीपी सिंह

अदालत से आस

सरकार से बार-बार अपील कर रहे आदिवासियों की आस अब अदालत से है। इस संबंध में 11 मई को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग-अलग परिणाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने 'हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति' की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि-अधिग्रहण में 'पेसा कानून' को दरकिनार कर रही है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की याचिका पर केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान राज्य विद्युत निगम और अडाणी के स्वामित्व की कंपनी 'परसा केते कोलरीज लिमिटेड' को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले में पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया, हसदेव अरण्य जंगल नो गो एरिया घोषित था। इसमें परसा ईस्ट केते बासन खदान को दी गई अनुमति को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही रद्द कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च से इस क्षेत्र में खनन के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करने को भी कहा था। केंद्र ने ऐसा अध्ययन कराए बिना ही अन्य खदानों को इजाजत देना जारी रखा। अब सात साल बाद वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट की अध्ययन रिपोर्ट आई है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि हसदेव के जितने हिस्से में खनन हो गया उसके अलावा अन्य इलाकों में खनन न किया जाए। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा ईस्ट केते बासन खदान के दूसरे चरण और परसा खदान को अनुमति दे दी है। इसके लिए चार लाख 50 हजार पेड़ काटे जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ेगा।

आदित्य की यात्रा

राज ठाकरे की अयोध्या जाने की मंशा भले ही पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन शिवसेना सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में जाकर भगवान राम की पूजा-अर्चना कर यह संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी का अभी भी आधार हिंदुत्व ही है।

सरयू नदी के तट पर एक आरती, पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिकों के आने के लिए ट्रेनों और बसों की बुकिंग और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन – ये नजारा था शिवसेना के वंशज आदित्य ठाकरे की अयोध्या की पहली एकल यात्रा का। 32 साल के आदित्य ने अपने पिता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बिना उप्र के शहर का दौरा किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि एक दिन की यात्रा युवा ठाकरे और शिवसेना, दोनों के लिए खास मायने रखती है। इसका उद्देश्य उन्हें न केवल एक 'ठाकरे वंशज' के रूप में बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना है जो अपने पिता के साये से बाहर निकल रहा है और जो अपने दम पर शिवसेना की विरासत को आगे बढ़ाएगा।

शिवसेना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, 'यह आदित्य साहब की खुद की पहली यात्रा थी। इससे पहले भी वह अयोध्या गए थे, लेकिन उस समय उद्धव साहब उनके साथ थे। जब भी शिवसेना के नेता राज्य से बाहर जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनका अनुसरण करते हैं। इस बार कार्यकर्ताओं में उत्साह कुछ ज्यादा देखने को मिला है।' उन्होंने कहा, 'आदित्य साहब जब अयोध्या पहुंचे, तो वहां मौजूद शिवसैनिकों की संख्या उद्धव साहब के इस तरह के किए गए दौरे की तुलना में बहुत अधिक थी।'

आदित्य की अयोध्या यात्रा ऐसे समय में भी हुई जब शिवसेना सहयोगी से प्रतिद्वंद्वी बनी भाजपा के साथ इस मसले पर रस्साकशी का खेल चल रहा है कि हिंदुत्व के प्रति किसकी प्रतिबद्धता ज्यादा मजबूत है। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि जून में उनके अयोध्या जाने की योजना के बाद शिवसेना ने आदित्य की अयोध्या यात्रा की घोषणा की थी। हालांकि उप्र के एक भाजपा सांसद ने मनसे के उत्तर भारत विरोधी रुख के कारण उनकी यात्रा पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जिसके बाद मनसे अध्यक्ष ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना दौरा रद्द कर दिया। शिवसेना के पदाधिकारी ने कहा, हम किसी के लिए अपने हिंदुत्व को सही ठहराने के लिए अयोध्या नहीं गए थे। आदित्य की इस यात्रा के लिए पिछले छह महीनों से विचार किया जा रहा था। लेकिन किसी न किसी कारण से अंतिम तारीख तय नहीं हो सकी थी।

शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंडे के अनुसार, इस यात्रा का हिंदुत्व को लेकर शिवसेना पर भाजपा के हमलों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'शिवसेना ने कभी भी राजनीतिक कारणों से भगवान राम का इस्तेमाल नहीं किया। यह सिर्फ एक तीर्थ है। हमारा हिंदुत्व दिखावा करने के बारे में नहीं है। राजनीतिक टिप्पणीकार अभय देशपांडे ने कहा, 'आदित्य की अयोध्या यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना अपनी नई अधिक उदार विचारधारा और हिंदुत्व के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।'

ठाकरे के दौरे की तैयारी के लिए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'नासिक से भी एक टीम तैयारियों के लिए आई थी। जैसा कि हमने (मुंबई से) किया था। हजारों शिवसैनिक नासिक, ठाणे, मुंबई और अन्य जगहों से आए थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शिवसेना ने मुंबई से पूरी दो ट्रेनें बुक की थीं। एक ट्रेन में पार्टी के लगभग 1700 से 1800 सदस्य थे, जबकि काफी सारे तो पहले ही बसों में निकल चुके थे। अकेले मुंबई और ठाणे से करीब 8,000 पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या गए हुए थे।

शिवसेना के 55 विधायकों में से कोई भी अयोध्या नहीं गया। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव 20 जून को होने हैं। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। राउत ने जोर देकर कहा, 'लेकिन यह ताकत का प्रदर्शन नहीं है। मतलब साफ है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है।' भले ही शिवसेना यह कह रही है कि यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक रही, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल, शिवसेना आदित्य ठाकरे को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी के रणनीतिकारों की मंशा है कि अगले चुनाव तक आदित्य ठाकरे को राजनीतिक क्षेत्र में इस कदर सक्रिय किया जाए कि वे शिवसेना का चेहरा बन सकें।

● **बिन्दु माथुर**

अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं आदित्य

आदित्य ठाकरे ने औपचारिक रूप से 2010 में राजनीति में प्रवेश किया था। तब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली में एक प्रतीकात्मक तलवार सौंपी और अपने पोते को युवा सेना के अध्यक्ष के रूप में लॉन्च किया। पार्टी में उनका दबदबा बाद के दशक में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया, जिसमें शिवसेना की उदार राजनीति का एक बड़ा हिस्सा आदित्य के युवा वोटों को आकर्षित करने के प्रयास से जुड़ा है। उन्होंने शिवसेना से अपने आक्रामक वैलेंटाइन्स डे विरोध को छोड़ने, नाइटलाइफ, खुले स्थान और शहर में खेल सुविधाओं आदि के बारे में बात करने के लिए कहा। अभय देशपांडे को लगता है कि आदित्य ठाकरे धीरे-धीरे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। और पार्टी के मामलों को सामने से आकर संभालते दिख रहे हैं। देशपांडे कहते हैं, आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मुंबई नागरिक निकाय के मामलों की देखरेख कर रहे हैं। इस जिम्मेदारी को पहले पिता संभालते थे। वह इस साल के अंत में नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार अभियान की कमान भी संभाल सकते हैं।

पशु चारे का अकाल

पशुधन की अर्थव्यवस्था घाटे की तरफ

चारा संकट ने पशुधन की पूरी अर्थव्यवस्था को ही घाटे की तरफ धकेल दिया। गर्मियों के समय अक्सर दूध देने वाले पशुओं की कीमतों में दो से पांच हजार रुपए तक की वृद्धि होती थी, लेकिन चारे के भावों ने इसे पूरी तरह से उलट दिया। अब पशु सस्ते हो गए हैं। बीकानेर के किसान हीरालाल करड ने बताया कि दूध देने वाली गाय 30 से 35 हजार रुपए में खरीदी-बेची जा रही थी, वही अब 25 हजार रुपए में आसानी से मिल जाती है। इसी तरह से भैंस की कीमत को देखा जाए तो 70 हजार रुपए वाली भैंस 55 हजार रुपए तक मिल जा रही है। चारे के संकट के समय हमेशा से प्रदेश में सरकारी चारा डिपो खोले जाते रहे हैं जिसमें पशुपालक को सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध कराया जाता रहा है। किसान नेता गुरचरण सिंह मोड़ ने कहा कि चारा डिपो नहीं खोले गए और अन्य राज्यों से आने वाले चारे पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो चारे के लिए किसान सड़कों पर उतरेंगे।

राजस्थान में तीन तरह के अकाल माने जाते रहे हैं, पहला अकाल अनाज का, दूसरा चारे का और तीसरा पानी का। तीनों जब एक साथ होते हैं तो उसे 'त्रिकाल' कहा गया। यहां के लोग चारे के अकाल को भी बहुत भयावह मानते हैं, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी का बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन पर निर्भर होता है। इस बरस भी राजस्थान में 'चारे के अकाल' से पश्चिमी राजस्थान के करीब 10 जिले प्रभावित हैं। इन जिलों में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चुरू, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और जालोर शामिल हैं। यह इलाका राजस्थान के सर्वाधिक पशुधन वाला इलाका है, जहां गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और भेड़ें पाली जाती रही हैं।

20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन 53.57 करोड़ है, जिसमें गायों की संख्या 13.9 करोड़, भैंसों की संख्या 13.7 करोड़, भेड़ों की संख्या 7.9 करोड़, बकरियों की संख्या 20.84 करोड़ और ऊंटों की संख्या 2.13 लाख है। चारे के संकट से जूझ रहे जिलों में राजस्थान के सर्वाधिक पशुधन वाले दो जिले भी शामिल हैं, जिनमें बाड़मेर के 53.66 लाख और जोधपुर के 35.90 लाख पशु इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।

सूखा भूसा जो पिछले तीन महीने पहले 500 रुपए क्विंटल था। पशुपालक ने सोचा कि गेहूं निकलते ही चारा सस्ता हो जाएगा। सीकर के राकेश बिरड़ा बताते हैं कि इस आस में उन्होंने अपने पशु बेचे नहीं, जबकि उस समय पशुओं की कीमत भी ठीकठाक मिल रही थी। लेकिन गेहूं कटते ही चारे के भाव 700 रुपए क्विंटल से शुरू हुए और आज चारा 1200 रुपए क्विंटल से लेकर 1500 रुपए क्विंटल तक हो गया है। ज्वार और मूंगफली का चारा 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया तो चने का चारा 800 रुपए प्रति क्विंटल मिल भी नहीं रहा है।

चारे के मूल्य में यह बढ़ोतरी हर साल के मूल्य के हिसाब से चार गुना हो गई। गेहूं और चावल के चारे के बढ़े हुए मूल्य से गाय और भैसों के दूध का व्यापार करने वाले पशुपालकों की दूध उत्पादन की लागत को भी उसी अनुपात में चार गुना तक बढ़ा दी है। इसी तरह से बकरी और भेड़ के लिए इस इलाके में काम में आना वाला चारा खेजड़ी के पत्ते जिन्हें 'लूंग' कहा जाता है, उसके भाव बढ़कर 1600 रुपए क्विंटल हो गए हैं। इस इलाके में बकरी और भेड़ को 'एटीएम' कहा जाता है। यानी, ऐसा पशुधन जिसे पशुपालक किसी भी जरूरत के समय बेच सकता है। बीकानेर के लाखुसर गांव के किसान जेठाराम का कहना है कि अब तो हमारे लिए बकरी पालना भी मुश्किल हो गया है। गाय को रोजाना लगभग 7 किलो चारे की जरूरत पड़ती है, जिसका पहले भाव 5 रुपए किलो था, लेकिन अब का भाव 15 रुपए किलो है और पशुपालक को रोजाना 70 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसी तरह भैंस लगभग 10 किलो चारा रोजाना खाती है, इसलिए पशुपालक को 100 रुपए रोजाना अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। बकरी रोजाना लगभग 1.5 लूंग खाती है, जिसके पहले भाव 6 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 16 रुपए किलो हो गया है। भेड़ को लूंग के साथ सूखा चारा भी खिलाया जाता है। भेड़ दो किलो चारा खाती है, जिस पर पहले 8 रुपए खर्च आता था, जो बढ़कर 16 रुपए हो गया है।

चारे के महंगे होने के कारणों को देखा जाए तो इस बार खरीफ की फसल के समय बरसात के अभाव से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ज्वार और बाजरे से होने वाले चारे का उत्पादन कम हुआ। साथ ही, फसल जब पककर तैयार हुई उस समय होने वाली अतिवृष्टि ने इस संकट को अधिक गहरा कर दिया। दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि यह श्रीगंगानगर, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों से आने वाले चारे को ईंट-भट्टों में काम में लेने के कारण भावों में इतना उछाल आया है। भूसे को ईंट पकाने के काम में लिया जाने लगा है। सूखी लकड़ियों के अभाव के कारण ईंट भट्टों संचालकों ने भूसे का उपयोग बढ़ा दिया है। बीकानेर जिले के नौरंगदेसर गांव के किसान छोगाराम ने बताया कि हरियाणा में भूसे को दूसरे राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इससे चारे का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही, चुरू के किसान नेता छगन चौधरी का यह भी कहना है कि व्यापारियों ने सूखे चारे का स्टॉक करके भाव बढ़ने की स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि चारे के स्टॉक पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। इसलिए यह स्थिति भविष्य में भी पशुपालकों को संकट में डालेगी।

इन कारणों के अलावा बदलती पारिस्थितिकी ने किसानों के फसल चक्र में भी बदलाव किया है। इस बार गेहूं और चने की बजाय सरसों और प्याज की फसल अधिक लगाई गई। इसके अलावा घटते चारागाहों के कारण चारे के अभाव के स्थिति लगातार बनती जा रही है। लाखुसर के किसान भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि एक तरफ बढ़ते अतिक्रमण ने चरागाहों को कम किया वहीं दूसरी तरफ टूटे मकानों के मलबे और कांक्रीट डालने से घास उगने की जगह कम होती जा रही है। गांवों से बाहर गोचर भूमि में फैल रहे प्लास्टिक ने स्थिति को अधिक चिंताजनक बनाया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है कि ऊंटों की घटती संख्या का कारण चरागाहों के कमी होना है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कांग्रेस मुक्त उप्र विधान परिषद!

देश के सबसे बड़े राज्य उप्र की विधान परिषद के इतिहास में 6 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा होगा, जब प्रदेश के उच्च सदन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस की मौजूदगी समाप्त हो जाएगी। प्रदेश में सियासी फलक पर लगातार सिमट रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में फिलहाल मात्र एक विधायक है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल आगामी 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि उप्र विधान मंडल के पिछले 72 साल के इतिहास में इस समय कांग्रेस की दोनों सदनों में सदस्य संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ दो उम्मीदवार विधायक बन सके। विधानसभा में दो सदस्यों के बलबूते कांग्रेस के लिए विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहे चुनाव में अपना उम्मीदवार जिता पाना मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि उप्र में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 403 को देखते हुए विधान परिषद की एक सीट पाने के लिए 32 विधायकों के समर्थन की दरकार है। कांग्रेस, चुनाव दर चुनाव दोनों सदनों में हाशिये पर सिमट रही है। विधानसभा के 2012 में हुए चुनाव में कांग्रेस के 28 विधायक थे, जो 2017 में घटकर 7 रह गए और 2022 में यह संख्या 2 पर सिमट गई। ऐसे में उप्र विधान मंडल का उच्च सदन अगले महीने कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। इसे कांग्रेस के लिए त्रासदपूर्ण स्थिति करार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने इस स्थिति के लिए पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। त्रिपाठी ने कहा, एमएलसी बनने के लिए कम से कम 32 विधायकों का समर्थन जरूरी है। स्पष्ट है कि उच्च सदन में अब हमारा कोई सदस्य नहीं होगा। इससे पहले 72 साल ऐसा कभी नहीं हुआ। विधान मंडल ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की इस जर्जर हालत के लिए पार्टी हाईकमान ही जिम्मेदार है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व नौकरशाह पीएल पूनिया ने हालांकि भरोसा जताया है कि जल्द ही इस स्थिति में बदलाव होगा और कांग्रेस की एक बार फिर वापसी होगी। पूनिया ने कहा कि पिछले तीन चुनाव में 28 से 2 पर पहुंचने के सच को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब कानपुर हिंसा सहित अन्य **तमाम मामलों** के बाद लोगों को भाजपा के तिलिस्म की हकीकत का पता चल रहा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य पूनिया ने कहा कि लोगों के मन में भाजपा के प्रति व्याप्त भ्रम टूटा है और इसके साथ ही जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पूनिया ने कहा कि भाजपा भी दो सीट से आज शिखर तक पहुंची है, इसी प्रकार दो सीट पर पहुंच चुकी कांग्रेस भी जल्द वापसी करेगी। उन्होंने बसपा का उदाहरण देते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्षणिक होता है। ऐसे में राष्ट्रीय दल के रूप में अब लोग कांग्रेस को ही विकल्प मान रहे हैं।

उप्र की राजनीति का दशकों से विश्लेषण कर रहे राजीव श्रीवास्तव ने पूनिया की दलीलों को नकारते हुए कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए राजनीति में उसकी प्रयोगधर्मिता को जिम्मेदार ठहराया। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस उप्र में 1989 से ही प्रयोगधर्मी बनी हुई है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की 'कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स' का हर प्रयोग नाकाम रहा। इसमें मायानगरी के चेहरे राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से लेकर निर्मल खत्री और जमीन से जुड़े नेता की पहचान वाले अजय कुमार लल्लू तक, सभी प्रयोग विफल रहे। उन्होंने दलील दी कि कांग्रेस के तीन दशक से अधिक समय के प्रयोगधर्मी कालखंड में पूरी पार्टी खेमों में बंट गई। इसके इतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी इस खेमेबाजी के जंजाल से कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाए, नतीजतन प्रदेश का विधान मंडल ही 'कांग्रेस मुक्त' होने लगा है।

कांग्रेस के लिए भविष्य की किसी उम्मीद के सवाल पर श्रीवास्तव ने कहा कि देश और प्रदेश में आज भी कांग्रेस के चाहने वालों की कमी नहीं है, कमी उस नेतृत्व की है जो इन्हें पार्टी कैडर के रूप में खड़ा करने की क्षमता से युक्त हो। उन्होंने आगाह किया कि **मौजूदा नेतृत्व** जब तक 'कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स' कर जनेऊ पहनने से लेकर नवरात्रि के व्रत करने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके लोगों को रिझाने की कोशिश करेगा तब तक, कांग्रेस फर्श पर ही रहेगी।

गौरतलब है कि आगामी 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों के लिये द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है। विधान मंडल में कांग्रेस जैसी ही हालत बसपा की भी है। पिछले 15 साल में अर्श से फर्श तक का सफर तय करने वाली बसपा का विधान परिषद में आगामी 6 जुलाई के बाद मात्र एक सदस्य बचेगा। बसपा के तीन एमएलसी दिनेश चंद्रा, अतर सिंह राव और सुरेश कुमार कश्यप का कार्यकाल 6 जुलाई को पूरा हो जायेगा। इसके बाद बसपा के एक मात्र सदस्य भीमराव अंबेडकर रह जाएंगे। साल 2007 में विधानसभा के 206 सदस्यों वाली बसपा के 2012 में 80 और 2017 में 19 विधायक ही जीत पाने के बाद अब पार्टी का मात्र एक नुमांइदा ही निचले सदन में बचा है। ऐसे में बसपा के पास भी अगले 5 साल तक विधान परिषद में अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करने का कोई विकल्प नहीं है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

विधान परिषद में कांग्रेस का हाल

बता दें कि उच्च सदन में सत्ताधारियों का ही बोलबाला रहता है। आमतौर पर यह चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उप्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पार्टी के महज दो ही विधायक इस बार जीत पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधान परिषद में किसी भी प्रत्याशी को जिता पाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि उसे कहीं से भी अपने प्रत्याशी को जीत मिलती नजर आए। इससे साफ है कि विधान परिषद में इस बार कांग्रेस का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होगा। ज्ञात हो कि उप्र के उच्च सदन की 100 में से 66 सीटें इस समय भाजपा के पास हैं, जो कि 20 जून को विधान परिषद चुनाव के बाद बढ़कर 73 पर पहुंचना तय है। इसी प्रकार सपा के अभी 11 एमएलसी हैं, इनमें से 5 सदस्य 6 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे और 20 जून के चुनाव में 4 सदस्य निर्वाचित होने पर पार्टी की कुल सदस्य संख्या 10 होने की संभावना है।

जातीय जनगणना की चाल चली

बिहार की सियासी बिसात पर शह और मात का नया खेल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर जो गोलबंदी शुरू की थी, इफ्तार की दावतों ने उसमें तूफानी तेजी ला दी और तभी तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के नाम पर ललकारने लगे। तेजस्वी यादव का वो स्टैंड काफी हद तक प्रायोजित ही लगा था। जैसे परदे के पीछे नीतीश कुमार ही रिंग मास्टर की भूमिका में हों। तेजस्वी यादव वैसे तो नीतीश कुमार को ललकार रहे थे, लेकिन निशाने पर साफ-साफ भाजपा नजर आ रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की घोषणा कर डाली थी। अगर भाजपा की जगह निशाने पर नीतीश कुमार होते तो तेजस्वी यादव पटना से बिहार भर का दौरा करने की घोषणा करते और नीतीश कुमार ने फटाफट तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुलाकर कंफर्म भी कर दिया कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? आगे का कंफर्मेशन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आकर दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के आश्वासन को बेहद भरोसेमंद बताया और अपना दिल्ली **मार्च स्थगित** करने का भी लगे हाथ ऐलान कर दिया।

पहले से ही नीतीश कुमार को चुनावी राजनीति के जरिये घेर चुके भाजपा नेतृत्व को भी सब बखूबी समझ में आ रहा था, लेकिन तमाम तिकड़मों के बाद भी मजबूरियां खत्म तो हो नहीं पाई थीं, लिहाजा जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में नीतीश कुमार के एजेंडे के साथ भाजपा भी खड़ी हो गई। जैसे भाजपा नेतृत्व को जेडीयू नेता की चालों का पहले से अंदाजा रहा, नीतीश कुमार भी तो निगाह टिकाए ही हुए थे, बस सही मौके का इंतजार था। अब भाजपा ने जेडीयू के ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार भी तो घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं, आरसीपी सिंह के मामले में भी वो वैसा ही दबाव बनाने में कामयाब लगते हैं जैसा चिराग पासवान के केस में बिहार चुनाव के बाद देखने को मिला था। अब तो हाल फिलहाल जो हाल हो चला है, मानकर चलना चाहिए 2024 के आम चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं?

आरसीपी सिंह को जेडीयू से बेटिकट होने का अंदाजा उसी वक्त लग गया होगा, जब वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर मोदी कैबिनेट में शामिल होने का फैसला किए थे। अव्वल तो आरसीपी सिंह को तब जेडीयू के हिसाब से फैसला लेना चाहिए था, लेकिन भाजपा की तरफ से मिले मंत्री पद के लालच में वो आ गए और नीतीश कुमार बस मुंह देखते रह गए। नीतीश कुमार धैर्य के साथ आरसीपी सिंह के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करते रहे और मौका मिलते ही वो कर डाले जो पहले से ही सोच रखे थे। आरसीपी सिंह जेडीयू की तरफ से राज्यसभा नहीं जा सके। नीतीश कुमार ने ये भी ठीक ही कहा है कि अभी आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नियमों के तहत कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा कायम रखते हैं तो अगले 6 महीने तक तो कैबिनेट में रह ही सकते हैं।

जिस बात को लेकर नीतीश कुमार ने 2019 में ही मोदी मंत्रिमंडल में लेकर शामिल होने से मना कर दिया था, दो साल बाद आरसीपी सिंह ने बगैर किसी मोलभाव के अपने मनमाफिक सौदा पक्का कर लिया। तब आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद। ऐसे भरोसेमंद कि जब अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया तो एक अन्य करीबी ललन सिंह की जगह आरसीपी सिंह को तरजीह दी। तब नीतीश कुमार को शायद ही लगा हो कि वो अपने खिलाफ दूसरे जीतनराम मांझी को खड़ा कर रहे हैं।

आरसीपी सिंह और जीतनराम मांझी के केस में कॉमन बात ये भी है कि दोनों ही को नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ अपना प्रतिनिधित्व दिया था और शुरुआत भी दोनों की सही रही, लेकिन आगे चलकर दोनों ही भाजपा के खेल में फंस गए। जीतनराम मांझी तो माफी मांगकर नीतीश कुमार के दरबार में वापसी भी कर चुके हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के लिए ये सब काफी मुश्किल है। ये भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा कि भाजपा अभी से ही आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह को लेकर खबर आई थी कि वो अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक मैसेज भी भेज चुके थे कि जेडीयू छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक मंजूरी मिली हो ऐसा तो नहीं लगता। चिराग पासवान का केस बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भाजपा पहले इस्तेमाल करती है और काम निकल जाने के बाद विश्वास भी नहीं करती, ऐसा लगता है आरसीपी सिंह का भी चिराग पासवान जैसा ही हाल होने वाला है।

● **विनोद बक्सरी**

जातीय जनगणना पर भाजपा झुकी क्या?

एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के नाम पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पहले ही हाथ मिला लिया था। साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली भी पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव ही नहीं, भाजपा के जनक राम को भी दबाव बनाकर लेते गए। सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर भाजपा को भी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने की मजबूरी थी, मान भी गई और अब तो बिहार में राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराने पर आम सहमति भी बन चुकी है। अब तो कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। काम भी शुरू हो ही जाएगा। नीतीश कुमार ने बताया कि जातीय जनगणना किस तरीके से कराई जाएगी, जाति आधारित जनगणना की जगह गणना की जाएगी... बिहार सरकार सभी जातियों, समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। नीतीश कुमार को भले ही अंदाजा न रहा हो, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद से तेजस्वी यादव नए फॉर्म में नजर आने लगे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का पूरा क्रेडिट वो लालू यादव को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लालू यादव की जीत है।

अंधेरे में डूब रहा पाकिस्तान

कंगाल पाकिस्तान के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध महासंकट बन गया है। यूरोपीय देशों के रूस से एलएनजी खरीद लेने के कारण पाकिस्तान अंधेरे में डूबता जा रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान को दोगुनी दर पर गैस खरीदना पड़ रहा है। इससे शहबाज सरकार के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए यूरोप ने रूस को दंडित करने के लिए उसके ईंधन से किनारा करने का अभियान तेज कर दिया है। इससे जहां रूस को आर्थिक झटका लग रहा है, वहीं उसके असर हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान तक देखे जा रहे हैं। यूरोप के इस दांव से पाकिस्तान के अंधेरे में डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इससे इमरान खान को हटाकर सत्ता में आई शहबाज शरीफ की नई सरकार की स्थिरता को लेकर खतरा पैदा हो गया है।

दरअसल, एक दशक पहले पाकिस्तान ने तेल की अचानक बढ़ती-घटती कीमतों से खुद को बचाने के लिए एलएनजी में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। उसने इसके लिए इटली और कतर के साथ लंबी अवधि का गैस सप्लाई का समझौता किया था। अब इनमें से कुछ सप्लायर डिफाल्ट कर गए हैं और पाकिस्तान को गैस देने की बजाय यूरोपीय देशों को दे रहे हैं जिससे उन्हें तगड़ा मुनाफा हो रहा है। इससे पाकिस्तान का अब वही हाल हो गया है जिससे बचने के लिए वह गैस की ओर बढ़ा था।

पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने ईद पर खुद को अंधेरे से बचाने के लिए 10 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था ताकि बाजार से एलएनजी से भरे एक जहाज को मंगवाया जा सके। वह भी तब जब पाकिस्तान कंगाली की हालत से गुजर रहा है। इस साल जुलाई में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक देश के एलएनजी का कुल खर्च 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है जो एक साल पहले की कीमत से दोगुना है। इसके बाद अब आईएमएफ ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह ऊर्जा और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करे।

अब पाकिस्तान में हालत यह हो गई है कि कई इलाकों में 12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इससे भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रही है। वहीं इमरान खान अब बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती को लेकर शहबाज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और विशाल रैलियां कर रहे हैं। इससे शहबाज शरीफ की सरकार की स्थिरता पर भी संकट मंडरा रहा है। उन्होंने माना है कि जनता संकटों के दौर से गुजर रही है। अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार से मंहगी गैस खरीदने का आदेश दिया है। एलएनजी की कीमतें जहां बढ़ रही हैं, वहीं यूरोप के धनी देश लगातार इसकी खरीद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री अहसान इकबाल की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक के दौरान चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) ने यह बात कही है। सीपीईसी परियोजना के तहत ऊर्जा, संचार, रेलवे जैसे क्षेत्रों में काम कर रही चीन की 30 कंपनियां भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने 300 अरब पाकिस्तान रुपए (15,95,920,800 डॉलर) का भुगतान नहीं मिलने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चीन की स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लगभग 25 प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो वे कुछ दिन के भीतर काम करना बंद कर देंगे।

इस समय पाकिस्तान बिजली की समस्या से जूझ रहा है। वैसे तो ऊर्जा आपूर्ति की कमी का सामना पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इस समय पड़ोसी देश पाकिस्तान ईंधन की कमी और तकनीकी बाधाओं के कारण गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है। जहां पहले 21,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, वहीं अब 15,500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, जिसकी वजह से देश में 6000 मेगावाट कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि कुल 33,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता में से पनबिजली प्लांट 1000 मेगावाट, निजी क्षेत्र के बिजली प्लांट 12,000 मेगावाट जबकि ताप विद्युत प्लांट 2,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई बिजली प्लांट बंद हो चुके हैं, जिससे वहां बिजली का संकट गहराया है। यही वजह है कि वहां रोजाना 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है। सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 33,000 मेगावाट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में से, जल विद्युत संयंत्रों ने 1,000 मेगावाट, निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्रों ने 12,000 मेगावाट का उत्पादन किया, जबकि थर्मल पावर प्लांटों ने केवल 2,500 मेगावाट का उत्पादन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस क्षेत्र में लगभग 10 अरब रुपए का दैनिक नुकसान झेलना पड़ा है। बिजली संयंत्रों के प्रमुखों ने केंद्रीय बिजली खरीद एजेंसी-गारंटी (सीपीपीए-जी) के खिलाफ बिजली संयंत्रों की मरम्मत और तेल खरीदने के लिए पर्याप्त धन की आपूर्ति नहीं करने के लिए शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी हैं, जिसे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने काफी गंभीरता से लिया और सीपीपीए-जी को बिजली संयंत्रों को तत्काल प्रभाव से धन का वितरण करने के लिए आदेश दिया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, उस पर बढ़ती महंगाई की वजह से इमरान को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, लेकिन लोगों को महंगाई से किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिखाई दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (नेप्रा) ने बिजली दरों में प्रति यूनिट 4.80 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोत्तरी की है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिजली वितरण कंपनियों को अनुमति दी है कि वो उपभोक्ताओं से शुल्क को बढ़ाकर वसूलें। इसके बाद से बिजली वितरण कंपनियां सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से अप्रैल के बिल में फरवरी के लिए ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) बढ़ाकर वसूलेंगी। यही नहीं, पाकिस्तान में गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल से चलने वाले कई बिजली संयंत्रों को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में बिजली की कमी का ये कारण भी अहम कारणों में से एक है। बिजली की भारी किल्लत झेल रहे पाकिस्तान में बंद किए गए कुछ बिजली संयंत्रों में 525 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला नंदी पावर प्लांट, 840 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला मुजफ्फरगढ़ पावर प्लांट और अन्य कई पावर प्लांट शामिल हैं।

क्वाड के समक्ष लक्ष्य साधने की चुनौती

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख लोकतंत्रों का रणनीतिक गठबंधन क्वाड अब संकल्पना से अधिक यथार्थ का रूप ले रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक वक्त इसका उपहास उड़ाते हुए इसे सुर्खियां बटोरने की कवायद बताया था, जो प्रशांत या हिंदू महासागर में किसी बुलबुले के मानिंद कहीं गुम हो जाएगी। हालांकि, चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते ही आस्ट्रेलिया-भारत-जापान और अमेरिका का क्वाड गठबंधन जोर पकड़ रहा है। चूंकि अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर पड़ रहा है तो अमेरिका को अपने साथियों संग मिलकर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक खुले एवं स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड अमेरिकी रणनीति के केंद्र में है। आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ 'आकस' जैसी पहल के बावजूद अमेरिका के लिए क्वाड की अहमियत जरा भी कम नहीं।

स्पष्ट है कि भारत, जापान और आस्ट्रेलिया को साथ लिए बिना अमेरिका एशिया में स्थायित्वपूर्ण शक्ति संतुलन नहीं बना सकता। अमेरिका भी इसे भलीभांति समझता है। यही कारण है जहां लंबे समय तक क्वाड की कोई बैठक नहीं हुई, वहीं जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद 14 महीनों के भीतर क्वाड नेताओं की चार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, फिर भी इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि क्वाड की राह में अभी भी तमाम चुनौतियां कायम हैं। सदस्य देशों को उनका समाधान तलाश इस संगठन को तार्किक बनाने के लिए सक्रिय रहना होगा।

आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका और भारत इस समय चीन के भीमकाय व्यापार अधिशेष में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। इसी आर्थिक ताकत के दम पर चीन का सामरिक खतरा बढ़ रहा है। क्वाड का एक उद्देश्य चीन की सामरिक शक्ति से उपजे खतरे की काट करना है। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया एवं जापान, दोनों ने बीजिंग प्रवर्तित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी 'आरसेप' को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें 'आरसेप' से भारी आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, भले ही इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के गणित को तय करने में चीन की ताकत ही क्यों न बढ़ जाए। चीन लंबे समय से विदेशी व्यापार को राजनीतिक संबंधों से अलग रखने की मुहिम चला रहा है और यह रणनीति क्वाड सदस्य देशों के साथ बढ़िया साबित होती दिख रही है। गत वर्ष चीन का व्यापार अधिशेष 676.4 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर रहा। महामारी के बावजूद विदेशी व्यापार में इतनी ऊंची बढ़त ही चीनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती रही, अन्यथा वह पटरी से उतर जाती।

चीनी व्यापार अधिशेष में अमेरिका ही सबसे अहम किरदार है। 2021 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 25.1 प्रतिशत बढ़कर 396.6 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के व्यापार अधिशेष में 60 प्रतिशत का योगदान अकेले अमेरिका का है। वहीं भारत की बात करें तो इस साल चीन के साथ उसका व्यापार घाटा 88 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह पहले ही भारत के रक्षा बजट को पार कर चुका है। वह भी ऐसे समय में जब चीन के साथ पिछले दो वर्षों से सीमा पर तनातनी चल रही है। इसके बावजूद सरकार चीन से जुड़े इस जोखिम को कम करके आंकती दिख रही है। आस्ट्रेलिया और जापान की भी चीन से कारोबारी निकटता है। ऐसे में इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही दिखता है कि क्वाड देश चीन पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय परस्पर व्यापार को वरीयता दें।

बीते दिनों टोक्यो में हुई क्वाड सदस्य देशों की बैठक से पहले अमेरिका ने इस दिशा में एक पहल की है। इसे हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी आईपीईएफ नाम दिया गया है। यह कोई व्यापारिक व्यवस्था न होकर एक आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य भारत सहित 13 सदस्य देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल नियमों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यह पहल व्यापार बाधाओं या टैरिफ घटाए बिना ही की गई है। दूसरी ओर बाइडन प्रशासन चीन पर लगे व्यापार टैरिफ घटाने की दिशा में विचार कर रहा है, जबकि पहले उसने यही ऐलान किया था कि जब तक चीन अपना व्यवहार नहीं सुधारेगा, तब तक ये टैरिफ जारी रहेंगे। इस तरह देखा जाए तो बाइडन के नेतृत्व में क्वाड का ध्यान वैश्विक चुनौतियों के मामले में भी बदलता जा रहा है। ये चुनौतियां जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य और लचीली आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हैं। अपने छोटे दायरे को देखते हुए क्वाड व्यापक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं दिखता। फिर भी मार्च 2021 के अपने पहले सम्मेलन में क्वाड देशों ने जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन और अहम एवं उभरती तकनीकों को लेकर कार्यकारी समूह गठित किए। उसी साल सितंबर में जब क्वाड नेता व्हाइट हाउस में मिले तो साइबर सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अंतरिक्ष जैसे विषयों पर तीन और समूह बना दिए। बहरहाल वादे, इरादे और उन्हें पूरा करने के बीच अंतर तो वैक्सीन के मामले में ही दिख गया, जब अमेरिका ने भारत के वैक्सीन निर्माण से लेकर अन्य देशों को उसकी उपलब्धता की राह में अवरोध पैदा कर दिए।

● **कुमार विनोद**

क्वाड के समक्ष नई अनिश्चितताएं उत्पन्न

क्वाड का टोक्यो सम्मेलन यही दोहराता है कि अत्यंत महत्वाकांक्षी एजेंडा न केवल क्वाड के हिंद-प्रशांत फोकस को कमजोर करेगा, बल्कि इससे समूह को परिणामोन्मुखी बनाना भी मुश्किल होगा। वैसे भी एक ऐसे दौर में जब अमेरिका यूक्रेन को हथियार आपूर्ति से लेकर तमाम अन्य किस्म की मदद के माध्यम से रूस के साथ छद्म युद्ध में उलझा हुआ है, तब क्वाड के समक्ष नई अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में बाइडन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन में रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की क्षमता है। निसंदेह सदस्य देशों की निरंतर बैठक और व्यापक सक्रियता से क्वाड मजबूत हो रहा है, लेकिन खतरा यह है कि इससे वह अपनी रणनीतिक दृष्टि और उद्देश्य से भटक सकता है। क्वाड इस समय चौराहे पर खड़ा है। अगर वह कोई ऐसा शोपीस नहीं बनना चाहता है, जो केवल चीनी विस्तारवाद को बढ़ावा देता हो तो उसके सदस्य देशों को एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा एवं मायने तलाशने होंगे। इसका पहला चरण तो यही होगा कि क्वाड वैश्विक चुनौतियों के बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करे।

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

संघर्ष का सामने करने की प्रेरणा देती है गीता

श्रीमद्भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है बल्कि संपूर्ण विश्व और मनाव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आंइसटीन तक अनेकों महापुरूष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि...

हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्,
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृतनिश्चयः॥

यानी यदि तुम (अर्जुन) युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे... इसलिए उठो, हे कौन्तेय (अर्जुन), और निश्चय करके युद्ध करो।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं गलत निर्णय सफलता की ऊंचाइयों से हमें जमीन पर भी ला सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने भागवत गीता में निर्णय लेने कुछ नियम बताए हैं। जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। श्रीमद्भगवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हर इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे सकती है।

सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना, परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है...

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं... इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य-कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो।

भगवत गीता ज्ञान और दर्शन का ऐसा भंडार है जिसे अपनाकर हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो चीज हमें अच्छी अनुभूति देती हैं हम उसे ही पसंद करते हैं। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध खोने का डर था। परंतु श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती हैं। श्रीमद्भगवत गीता के छठे अध्याय में श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा।

श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है अपनी इन्द्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है...

श्रद्धावान्ल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

यानी श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इन्द्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम-शांति को प्राप्त होते हैं।

जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए, कहीं ये निर्णय गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं ले रहे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। भगवत में एक शब्द बार-बार दुहराया गया है, जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए। वहीं क्रोध से मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है...

क्रोधाद्भवति संमोहः
संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

यानी क्रोध से मनुष्य की मति-बुद्धि मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति-भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है।

भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो इस काम को न करें। अपने निर्णय के बारे में दुबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी न हो वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद न हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कोई निर्णय न लें। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। साथ ही उसकी हार कभी नहीं होती है।

● **ओम**

सवेरा

बापू, मुझे निकालो यहां से। यह पिंजरा मेरे लिए जेल बन गया है। पिजरे में कैदी बने संतू ने पिता से कहा।

मैंने तुझे बंद किया है क्या, जो मैं तुझे आजाद करूं? तेरी शराब ने ही तुझे खराब किया है, अब तो तुझे पिंजरे में शराब के साथ ही रात काटनी पड़ेगी। बापू चल दिए।

रातभर पिंजरे में बंद रहूंगा, 2500 रुपए जुर्माना भी दूंगा, सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी मिल गई है, अपनी नटनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा! संतू सोच में पड़ा था।

मैं तो डमरू-खंजीरा बजाता हूं, पर नटनिया तो जान हथेली पर लेकर रस्सी पर डोलती है, जिससे रात को रोटी नसीब हो, पर उसे रोटी कैसे मिले! मैं तो सारे पैसे शराब में घोलकर पी जाता हूं! पतली गली से नसीब निकल लिया।

अरे तू पैसे क्या शर्म भी शराब में घोलकर पी गया है! शर्म को भी शर्म आ रही थी।

घर में तो गद्दा भी नहीं नसीब होता, पर नींद खूब आती है, यहां जेल में गद्दा है, पर नींद कैसे आए! संतू साख बचाने की जुगत सोच रहा था!

साख तो तेरी तभी चली गई थी, जब तेरी नटनिया ने तेरे हाथ से बोतल छीन ली थी और तूने अपनी मर्दानगी दिखाकर उसके तन-मन को घायल कर दिया! साख ने कहा, वह भी निकल ली!

तेरे लिए यही पिंजरा ठीक रहेगा, केवल रातभर के लिए नहीं उम्र भर के लिए। शराब ने कहना जारी रखा, तुम लोग शराब न पियो तो शराब वाले शराब बनाएं ही क्यों? शराब भी उसे छोड़कर चला गया।

अच्छा है, तू खुद ही मुझे छोड़ गया, वर्ना सुबह बस्ती वाले आएंगे, 2500 रुपए का जुर्माना मांगेगे और शराब छोड़ने की कसम खिलवाएंगे, तब मैं तुझसे कैसे नजरें मिलाता! संतू की सोच सिमट गई।

संतू जैसे अनेक कैदियों के शराब से तौबा करने से गांव का सवेरा हो गया था।

- लीला तिवानी

तुमसे ही हर सांस है मेरी

तुमसे ही हर सांस है मेरी
तुमसे ही मेरा हर पल
तुमसे ही मेरा जीवन है
तुम ही मेरा आज व कल
तुमने ही महकाया मेरे
उजड़े इस सूनेपन को
तुमने ही आकर छुआ है
मेरे इस अन्तर्मन को
कोई नहीं है सिवा तुम्हारे
तुम्हीं मेरा हो आत्मबल
तुमसे ही मेरा जीवन है
तुम ही मेरा आज व कल
दुर्गम इस कठिन से पथ पर
मुश्किल होता यूं चलना
तुम्हारे बिना इस जहान में
असंभव था मंजिल मिलना
वीराने से इस जंगल में
भटक रही थी मैं अविरल
तुमसे ही मेरा जीवन है
तुम ही मेरा आज व कल
रोम-रोम पुलकित है मेरा
तुमसे हुआ यूं अनुबंध
गीतों में तुम ही समाय हो
तुम हो प्यारा-सा इक छंद
तुम ही मेरे हर सवाल का
बने हुए हो अद्भुत हल
तुमसे ही मेरा जीवन है
तुम ही मेरा आज व कल

- डॉ. सारिका ठाकुर 'जागृति'

एक मां का इंतजार

जीवी मां ने बड़े दुख सहकर मोहन को पढ़ाया था। 20 साल की उम्र में मोहन के बापू की मृत्यु हो गई थी तब मोहन सिर्फ 2 साल का था। घर में 10 लोगों का खाना बनाना घर का सारा काम करना, गायों की सेवा चकरी करना, दूध दोहना आदि कामों में व्यस्त रहती थी। खुद तो अनपढ़ थी लेकिन मोहन की पढ़ाई तरीके से हो उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसका देवर पढ़ा लिखा था तो वह मोहन को पाठशाला से मिला घर काम करवाएं उसका ध्यान रखती थी। मोहन ने मैट्रिक पास कर ली तो उसे शहर के कॉलेज में भी पढ़ाया और उसकी वहीं नौकरी लग गई। जब बेटा शहर गया तो उसकी एक आंख बेटे की प्रगति देख हंस रही थी तो उसके विरह में दूजी आंख रो रही थी। बरसों बीत गए और उसने शादी उधर ही कर ली, उसके दो बच्चे भी हो गाएं। पहले साल में अकाद बार मां से मिल जाता था लेकिन धीरे-धीरे वह भी बंद हो गया। अब जीवी की तबियत भी ठीक नहीं रहती थी और फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि पता नहीं कितने दिन हैं उसके पास।

एक सुबह सब उठे ही थे तो देखते क्या, उसकी दरवाजे की और देख रही आंखों में जान नहीं थी, बेटे या इंतजार करते-करते वह चल बसी थी।

- जयश्री बिरमी

रन मशीन मिताली राज

मिताली राज के कैरियर ने दो दशकों का लंबा सफर तय किया और भारतीय महिला क्रिकेट का उदय होते देखा, जिसने मैदान और मैदान के बाहर दोनों जगह संघर्षों का सामना किया। दाएं हाथ की बल्लेबाज जिसने लंबे समय तक कप्तानी की है। कम जानकारी रखने वालों के लिए मिताली के खेल को आकड़ों के परिप्रेक्ष्य में रखकर बताया जा सकता है - सचिन तेंदुलकर 24 साल तक खेले, जबकि मिताली ने 23 साल तक बड़े मंच पर कब्जा जमाए रखा। वह अपनी टीम को दो बार विश्व कप फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहीं और विशाल 10,868 रन बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन ये आंकड़े हमें यह नहीं बताते हैं कि मिताली मुख्य रूप से पुरुषों के लिए माने जाने वाले इस खेल में महिला क्रिकेटरों की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उनके जाने से 1990 के दशक के भारतीय क्रिकेट के उस आखिरी जुड़ाव का भी अंत हो गया जो अभी तक खेल में सक्रिय बना हुआ था। हरमनप्रीत कौर अब अपने नेतृत्व में क्रिकेट के हर प्रारूप में एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार हैं। उनको सौंपा गया पहला असाइनमेंट इस महीने के अंत में भारत का श्रीलंका दौरा होगा। जब मिताली राज ने क्रिकेट में कदम रखा था तो उस समय भारत में महिला क्रिकेट की किसी को परवाह नहीं थी। 23 साल बाद उनकी शांत विदाई महिला क्रिकेट के प्रति उस संस्कृति और रवैये की खासियत है जिसे बदलना अभी बाकी है।

मिताली राज ने 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ जब अपने खेल की शुरूआत की तो उस समय वह एक टीनएजर थीं। 2004 में कप्तान बनीं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में लगभग 11,000 रन बनाने के लिए अथक रूप से बल्लेबाजी की। उन्होंने इस साल मार्च में महिला विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी राउंड-रॉबिन मैच हारने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने में विफल रही। इन 23 सालों में मिताली ने अपनी तकनीक और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और समझदारी से खेलते हुए हमेशा अपने विकेट को अहमियत दी। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 20 कैलेंडर वर्षों में उनका औसत 40 से अधिक का रहा, जिसमें 2004 और 2017 में दो बड़े सीजन शामिल थे, तब भारत महिला विश्व कप फाइनल तक पहुंची थी। उस समय 34 साल की मिताली के लिए 2017 का विश्व कप विशेष रूप से शानदार था। उसमें उन्होंने 9 पारियों में 409 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट से सिर्फ एक रन पीछे थे।

ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जारोड किम्बर कहते हैं, 'वह अपने समय की बेहतरीन खिलाड़ी रहीं थी, और उनके पास 70 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन महिलाओं के सफेद गेंद वाले क्रिकेट के विकास के साथ-साथ स्ट्रोक प्ले और पावर गेम की कमी ने उनके खिलाफ काम किया, खासकर टी 20 में।' और इसलिए अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 66 के स्ट्राइक रेट के बाद भी मिताली को उन खिलाड़ियों से रैंकिंग में काफी पीछे रखा गया जिन्होंने 2000 और 2010 में डेब्यू किया था। इन खिलाड़ियों में लिजेल ली, नट साइवर, मेग लैनिंग, स्टैफनी टेलर और यहां तक कि उनकी टीम की साथी स्मृति मंधाना का नाम लिया जा सकता है। और ये अंतर 2022 के विश्व कप में और भी साफ हो गया। मिताली 7 पारियों में 26 के औसत और 63 से कम के स्ट्राइक रेट पर केवल 182 रन ही बना सकीं। एक खिलाड़ी के लिए यह एक साफ संकेत था कि अब वह अपना श्रेष्ठ पीछे छोड़ चुके हैं। फिर भी अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव में मिताली ने भारतीय मध्यक्रम को एक साथ जोड़कर रखा, जिसे शीर्ष स्तर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जमने के लिए सीनियर्स से समय और लगातार विश्वास की जरूरत थी।

अपने ऑन-फील्ड कारनामों और शानदार पारी की बदौलत मिताली टीम की साथी झूलन गोस्वामी के साथ एक भारतीय और वैश्विक क्रिकेट आइकन बन गईं। उनकी पीढ़ी के कुछ पुरुष खिलाड़ी दशकों तक खेलते हुए उनके लंबे कैरियर की तुलना में उनके करीब तक आए, मसलन- जेम्स एंडरसन, शोएब मलिक, रंगना हेराथ, क्रिस गेल, मोहम्मद हफीज और रॉस टेलर। हालांकि इन नामों और मिताली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन सभी खिलाड़ियों के पास या तो पहले से ही अंतिम विदाई मैच या श्रृंखला के साथ बाहर जाने का अवसर था, या निकट भविष्य में एक मैच होने की उम्मीद थी (यहां तक कि हफीज को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी पड़ी) लेकिन मिताली की विदाई की खबर उनके आखिरी मैच के लगभग तीन महीने बाद एक सोशल मीडिया ग्राफिक के जरिए आई और कहीं गुम भी हो गई। क्योंकि खबरों ने तेजी से अपना रूख दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय पुरुषों की चल रही टी-20 श्रृंखला की तरफ मोड़ लिया था।

टेस्ट मैच को क्रिकेट का सबसे शुद्ध और सबसे चुनौतीपूर्ण रूप माना जाता रहा है। इस वित्तीय और लिंग-आधारित अंतर को जल्द ही कभी भी गंभीरता से संबोधित किया जाना बाकी है। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की पिछले हफ्ते की टिप्पणी के आलोक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट के भविष्य में क्रिकेट परिदृश्य का हिस्सा नहीं बनने की बात कही थी। अपने लंबे क्रिकेट कैरियर में मिली उपलब्धियों के बीच मिताली इस बात का भी प्रतिनिधित्व करती हैं कि महिला क्रिकेटरों को उच्च स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए किन-किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। अगर क्रिकेट गवर्निंग बॉडी चाहे वह बीसीसीआई हो या आईसीसी, महिलाओं के खेल में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ियां को इनका सामना नहीं करना पड़ेगा।

● आशीष नेमा

बॉलीवुड में राधिका को नाक से लेकर ब्रेस्ट सर्जरी तक कराने की सलाह दी गई थी

एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में राधिका ने फिल्म इंडस्ट्री के कई तरह के प्रेशर के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब वह फिल्मों में काम करने आई तो इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें कई तरह की सर्जरी करवाने की बात कहीं, कुछ ने तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए कह दिया था।

राधिका ने इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों की बात करते हुए कहा, जब मैंने बॉलीवुड में काम करने के लिए कदम रखा तो मुझ पर कई सारे प्रेशर थे। मुझे मेरी बॉडी और चेहरे पर काम करने लिए कहा गया। जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो मुझसे नाक की सर्जरी करवाने के लिए कहा गया। दूसरी मीटिंग में ब्रेस्ट की सर्जरी करवाने को बोला गया। लेकिन सलाहों का यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, कुछ ने मुझे कहा कि आपको अपने पैरों में कुछ करना चाहिए तो कुछ ने कहा कि आप बोटॉक्स क्यों नहीं करवा लेती हैं। राधिका ने आगे बताया, मुझे अपने बालों को कलर करवाने में 30 साल लगे हैं। लोग मुझे इंजेक्शन लगवाने और प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सलाह दे रहे थे। इंडस्ट्री के लोग जब मुझे यह सारी सलाह दे रहे थे तब मुझे उनपर गुस्सा भी आया। लेकिन हां इन सभी की सलाह से मुझे अपनी बॉडी अपने चेहरे से और भी ज्यादा प्यार हो गया। राधिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी 24 जून को फिल्म फॉरेंसिक रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मेसी और प्राची देसाई लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा वह ऋतिक रोशन स्टारर विक्रम वेधा मे भी नजर आएंगी। यह फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मेहदी हसन ने पाकिस्तान जाकर 10 हजार रुपए से शुरू की थी साइकिल वर्कशॉप

शहंशाह-ए-गजल मेहदी हसन गजल गायन के इतिहास में सबसे महान और प्रतिभावान शख्सियतों में से एक थे। हसन साहब ने अपनी जिंदगी में करीब 50 हजार से ज्यादा गजल को आवाज दी है और करीब 300 फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो हसन साहब और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया। जब वो पाकिस्तान जाकर बसे तो उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता के पास महज 10 हजार रुपए थे। परिवार के पालन-पोषण के लिए उनके पिता ने सोचा कि क्यों ना वो एक लकड़ी का टाल खोल दें। पिता की ये बात 20 साल के हसन साहब को रास नहीं आई। हसन साहब ने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें कुछ रुपए दे दें जिससे वो परिवार के पालन-पोषण के लिए एक साइकिल वर्कशॉप खोलेंगे। पिता को बेटे की ये बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने हसन को रुपए दे दिए। उन्होंने शहर जाकर एक साइकिल वर्कशॉप खोली। इससे वो रोज 20 रुपए तक कमाते और कमाई का एक चौथाई हिस्सा अब्बा को देते थे।

जीवन रिफ्लेक्टर में सिल्वर पेपर चिपकाने का काम करते हुए बन गए थे हीरो

50-80 के दशक के सबसे खतरनाक विलेन समझे जाने वाले ओंकार नाथ धर उर्फ जीवन को गुजरे 35 साल बीत चुके हैं। बता दें कि जीवन ने अपने एक्टिंग कैरियर में करीब 60 फिल्मों में नारद मुनि का रोल निभाया था। जीवन कश्मीरी पंडितों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये कश्मीर में फोटो स्टूडियो खोलना चाहते थे, जिसकी ट्रेनिंग के लिए वो बॉम्बे पहुंचे थे। एक्स्ट्रा कमाई के लिए जीवन के दोस्त ने उन्हें फिल्म सेट पर काम करने की सलाह दी। जीवन शूटिंग के दौरान रिफ्लेक्टर की सिल्वर रील बदला करते थे। एक दिन शूटिंग के समय उन्होंने देखा कि एक ग्रुप अपने सीन की प्रैक्टिस कर रहा है। उन्हें बचपन से ही अभिनय में रुचि थी तो वो खड़े होकर देखने लगे। टाइमपास करने के लिए जीवन आगा हशर के प्ले की लाइनें दोहरा रहे थे। उस ग्रुप को एक एक्टर की तलाश थी और जैसे ही उनकी जीवन पर नजर पड़ी तो ये तलाश पूरी हो गई। डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने उन्हें तुरंत अपनी अगली फिल्म रोमांटिक इंडिया में साइन कर लिया और यहां से जीवन का फिल्मी कैरियर शुरू हो गया।

होना चीयर बालाओं का

आज नहीं तो कल मैच के लिए चीयरबालाएं अपरिहार्य हो जाएंगी।

उनका रूप कैसा होगा हमें पता नहीं लेकिन हमें कल्पना के घोड़े दौड़ाने से कौन रोक सकता है।

किसी क्रिकेट मैच के पहले टीम की घोषणा होगी तो लोग कहेंगे, हमें खिलाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है। चाहे पोवार को लो या हरभजन को। हमें ये बताओ कि चीयर कौन करेगा? कायदे का चीयर न हुआ तो समझ लो गया मैच हाथ से।

क्रिकेट की कमेंट्री के साथ-साथ चीयरबालाओं की भी कमेंट्री होने लगे शायद। कमेंट्रेटर चीयरिंग अप का आंखों देखा हाल सुनाते हुए बोले- अब मैच शुरू होने वाला है। गेंदबाज रन अप पर। बल्लेबाज क्रीज पर। चीयरबालाएं तैयार। चीयरबालाओं के वर्णन के लिए रीतिकाल विशेषज्ञ आने ही वाले हैं। तब तक हम शुरू होते हैं।

चीयर बाला ने तीन ठुमके बायीं तरफ की पब्लिक के लिए लगाए। जनता चौथे ठुमके की आशा में थी लेकिन उसने चौथी बार रिवर्स ठुमका लगा दिया है और ये दायीं तरफ की जनता के कलेजे के पार। ये बहुत सीनियर चीयरबाला हैं। सालों तक क्रिकेट की सेवा की है। कई बार इनके उत्साही ठुमकों कारण क्रिकेट की टीम बची है। कभी-कभी लोग कहने लगते हैं कि इनको जो करना था कर चुकीं लेकिन अभी भी इनके अंदर दो-तीन साल के ठुमके बचे हुए हैं। जब जरूरत नहीं होती तब वे अपना शानदार चीयर निकाल के सामने दिखा देती हैं।

युवराज सिंह बल्लेबाजी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने चीयरबालाओं के कप्तान को इशारा किया है। चीयरबालाओं का स्थान परिवर्तन हो रहा है। वही कम्बीनेशन जमा दिया गया है जिसको देखते हुए पिछले मैच में उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। और ये छक्का।

पहला पावर प्ले शुरू होने वाला है। युवा चीयरबालाओं को स्टैंड के सामने से हटाकार ठीक बैट्समैन के सामने लगा दिया गया है। बल्लेबाज को बहुत सावधान होकर खेलना होगा। जरा-सी चूक होते ही वे विकेट के नजदीक से हटकर चीयरबाला के नजदीक से होते हुए पवेलियन तक जा सकते हैं।

चीयरबालाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास। पिछला मैच उन्होंने, जो भारत की टीम लगभग हार चुकी थी, केवल अपनी चीयरिंग से जितवा दिया था। उनको देखकर खिलाड़ियों की सांसें सेन्सेक्स की तरह ऊपर-नीचे हो रही हैं।

ये एकदम साफ मामला था। अम्पायर एकदम पास में खड़े थे। लेकिन चूंकि उनका ध्यान चीयरग्रुप की तरफ था इसलिए वे खेल को देख नहीं पाए। उन्होंने तीसरे अम्पायर की सेवा लेने का फैसला लिया है। लेकिन अफसोस कि

वहां से भी कुछ पता नहीं चला पाया क्योंकि सभी कैमरे भी चीयरग्रुप के ऊपर लगे हुए थे। आखिर में दोनों कप्तानों की सहमति से खिलाड़ी के आउट/नाटआउट होने का निर्णय टास उछाल कर किया जा रहा है। आउट होने पर खिलाड़ी उछलता हुआ बाहर चला जाएगा। आने वाले खिलाड़ी का मुंह लटका होगा। उसकी चीयर-चेन जो टूट गई है।

चीयरबालाओं की तर्ज पर महिला खिलाड़ियों के मैच में चीयरबालकों की मांग होगी। कुछ दिनों में मिक्स चीयरग्रुप का प्रचलन भी शुरू हो जाएगा।

तब मजे रहेंगे। बारिश के कारण मैच रद्द हो जाएगा लेकिन चीयरग्रुप का कार्यक्रम चालू रहेगा। लोग मैच के पहले हवन वगैरह करेंगे- हे भगवान आज पानी बरसा दो। टिकट का पूरा मजा लेने दो। खेल तो देखते ही रहते हैं। आज जी भर के चीयरिंग हो लेन दो।

खिलाड़ी भी कामना करेंगे- काश पानी बरस जाए तो पवेलियन में टांग पसार के चीयरफुल हो जाएं।

खिलाड़ियों के काम्बिनेशन से ज्यादा चीयरग्रुप का काम्बिनेशन मायने रखेगा। उनके चयन में सिर फुटौव्वल होगी। बचे हुए कपड़े तक फाड़े जाएंगे।

खिलाड़ी जैसे आजकल अपना बल्ला बदलते हैं, ग्लव्स बदलते हैं वैसे ही कल को कहेंगे- फलानी वाली चीयरबाला को इधर लगाओ, इनको उधर करो। साइड स्क्रीन की तरह वे उनको इधर से उधर खिसकवाते रहेंगे। होने को हो तो यह भी सकता है कि कल को चीयरबालाएं और चीयरबालकों का ही जलवा हो सकता है। यह जलवा इतना तक हो सकता है कि वे कहें- इन खिलाड़ियों को रखो, इनको बाहर करो तभी हम चीयर करेंगे। अगर ये कम्बीनेशन रखेंगे तभी हमारा चीयरइफेक्ट काम करेगा।

पता लगा कि अच्छा खासा रन बनाता खिलाड़ी अपना मुंह बनाता हुआ मैच से बाहर। कोई हल्ला नहीं कोई टेंशन नहीं। मैच चीयर हो रहा है आराम से। कोई पूछेगा भी नहीं कि पिछले मैच का हीरो कहां चला गया।

आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा कि खिलाड़ी से ज्यादा उनका हौसला बढ़ाने वाले की औकात कैसे हो जाएगी। क्रिकेट है तो चीयरबालाएं/चीयरबालक हैं। क्रिकेट ही नहीं होगा तो बालाएं क्या करेंगी? मजाक तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन लगता है कि यह हो भी सकता है। जब क्रिकेट में जीत-हार को देश की जीत-हार मान लिया जाए। क्रिकेट में जीत गए तो मानो दुनिया जीत गए। सारा देश क्रिकेट के पीछे पगलाया घूमता है। इसके ग्लैमर के नशे में टुन्न। तो यह भी काहे नहीं हो सकता है। आखिर यह भी तो ग्लैमर है। ये चीज बड़ी है मस्त-मस्त।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

अल्ट्राटेक
इंजीनियर की पसंद
देश का नं.1 सीमेंट
घर एक, मौक़ा एक,
इसीलिए सीमेंट भी
देश का नं. 1
UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice
INDIA'S NO.1 CEMENT
'अल्ट्राटेक, देश का नं.1 सीमेंट' – क्लेम के विवरण के लिए ultratechcement.com पर विज़िट करें.